13.05 hrs

***hDemands for Supplementary Grants, 2024-25? Second Batch; Demands For Excess Grants, 2021-22 Manipur Budget, (2025-26)- General Discussion Demands for Grants On Account- (Manipur), 2025-26 And Demands For Supplementary Grants- (Manipur), 2024-25**

***m01 HON. CHAIRPERSON:** Hon. Members, Item nos. 15 to 19 will be taken together.

Motions moved:

?That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2025, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 6, 8, 10, 11 to 13, 15, 17 to 22, 25, 26, 29 to 32, 35, 41, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 58 to 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70 to 72, 74, 76, 78, 79, 85, 86, 89, 91 and 97.?

Demands for Supplementary Grants- Second Batch for 2024-2025

submitted to the Vote of Lok Sabha

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई संख्या और मांग का शीर्षक No. and Title of the Demand submitted to the Vote of the House	अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grants

?That the respective excess sums not exceeding the amounts on Revenue Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2022, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 6 and 39.?

Demands for Excess Grants for 2021-22 submitted to the Vote of Lok Sabha

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई

मांग की संख्या और शीर्षक		अनुदानों की मांगों की राशि		
No. and Title of the Demand		Amount of Demand for Grants submitted to the Vote of the House		
1	2	3		
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹	जोड Total ₹
6. उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers	493,37,93,293	...	493,37,93,293
39. पेशन	39 Pensions	742,56,55,188	...	742,56,55,188
कुल	TOTAL	1235,94,48,481	....	1235,94,48,481

?That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Manipur, on account, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2026, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 50.?

and

?That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Manipur, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2025, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 5 to 7, 14, 20, 23 to 25, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 46, 48 and 49.?

Hon. Member, Shri Gaurav Gogoi ji.

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants, Demands for Excess Grants, and on the Manipur Budget. ? (*Interruptions*)

सर, हाऊस को ऑर्डर में लाइए । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please be seated.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज़ आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you are a senior Member of the House.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not disturb.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please be seated.

? (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई(जोरहाट): सभापति महोदय, मैं दोबारा अभी से प्रारंभ करता हूं कि आज मैं सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का जो दूसरा बैच आया है, उसमें लगभग 52 ग्रांट्स और तीन एप्रोप्रिएशंस हैं । कुल मिलाकर ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडीचर लगभग 26 लाख 78 हज़ार 508 करोड़ रुपये का है । जो नेट एडिशनल स्पेंडिंग सरकार की होगी, वह लगभग 51,462 करोड़ रुपये का होगा । जिसमें से लार्जेस्ट एलोकेशन डिफेंस पेंशन, कम्युनिकेशंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर स्कीम्स ऑफ फर्टीलाइज़र सब्सिडीज़ पर है ।

सर, बहुत से महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को मद्देनज़र रखते हुए, मणिपुर के बजट को मद्देनज़र रखते हुए । The Finance Minister has tabled the Manipur Budget envisaging an expenditure of Rs. 35,103 crore, जिसमें से सोशल सैक्टर आउटले लगभग 9,520 करोड़ रुपये का है I The Demands for Excess Grants are related to the year 2021-22, which have occurred in two Grants and two Appropriations amounting to ? (*Interruptions*) I hope the Parliamentary Affairs Minister will help us to conduct this discussion in a normal manner. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Gaurav ji, please go ahead.

श्री गौरव गोगोई : सर, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ कि ये सप्लिमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए हैं, उनको ले कर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय देश के सामने है, वह बहुत गंभीर है । बहुत अफसोस की बात यह है कि यह पूरी सरकार, सिर्फ हैडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे, आज उस पर ज्यादा ज़ोर दे रही है । पूरी सरकार भाषणों पर ज्यादा निर्भर है । पूरी सरकार चाहती है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनकी हैडलाइंस पर ध्यान दे और वास्विक जो स्थिति है, उस पर उनका ध्यान न जाए ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Deputy Leader of the Opposition is speaking.

? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, noise is coming from the Treasury Bench. ? (*Interruptions*) Noises are coming from the Treasury Bench. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting the hon. Members from both sides of the House.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज़ आप लोग भी बैठ जाइए और आप लोग भी बैठिए ।

? (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI: I am asking you to please restrain the Treasury Bench. I can hear that they are making more noises than my colleagues. We are all hearing the Treasury Bench. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Deputy Leader of the Opposition from the Congress Party is speaking.

? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: We are only hearing the Treasury Bench. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay. Please go ahead.

SHRI GAURAV GOGOI: Please resolve your issue.

I want to give an example of Manipur. सभापति महोदय, आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस वक्त आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मणिपुर में शांति निकट है, बहुत जल्दी ही शांति आने वाली है । यह आज से 21 महीने पहले की बात है । लेकिन आज हम 13 फरवरी, 2025 को क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल-356, मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हुआ है । सर, यह हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है ।

13.10 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2023 के अविश्वास प्रस्ताव के समय स्वयं कहा कि शांति निकट है । मणिपुर में शांति आने ही वाली है । प्रधानमंत्री जी हमें पहले यह बताए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ? प्रधानमंत्री हमें बताए कि वह आजतक मणिपुर क्यों नहीं गए?? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपसे कहा कि आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वह व्यापक चर्चा करें । जब राष्ट्रपति शासन का विषय आएगा तो उस समय भी इस विषय पर चर्चा होगी । अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, मैं मणिपुर के बजट पर ही बोल रहा हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर के बजट पर वहां के विधान सभा में क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आज भी विधान सभा की स्थिति क्या है? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आज हमें वहां के बारे में पता है कि स्टेट असेम्बली डिजॉल्व हुई है या स्टेट असेम्बली सस्पेंडेड एनिमेशन है । हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आज चर्चा में भाग लें और हमें बताएं कि विधान सभा की स्थिति क्या है? मणिपुर में आज जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, गृह मंत्री जी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी । मैं आदरणीय गृह मंत्री से जी निवेदन करता हूं कि मणिपुर में आज उनकी जो विफलता हुई है, उस संदर्भ में वह अपना राजधर्म पालन करें ।? (व्यवधान)

महोदय, मैं आपकी तरफ ही देख कर बोल रहा हूं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी माननीय वित्त मंत्री जी को बताओ । जब वह विषय आए, तब उनको बताना ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, आज से दो साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हुआ था, तब गृह मंत्री जी वहां जाकर बोले थे कि मैं जल्द वापस आऊंगा । अब आप उनसे पूछ लीजिए, दो साल हो गया, लेकिन गृह मंत्री जी वहां पर नहीं गए । इसीलिए, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अपनी नैतिक जिम्मेवारी लें । प्रधानमंत्री जी वहां पर जाएं । बंदूक के दम पर उत्तर-पूर्व में शांति नहीं आएगी । पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी । अगर वास्तव में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दीजिए । अगर वास्तव में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का आपके पास धैर्य होना चाहिए । उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है? उसको सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए ।? (व्यवधान)

सर, क्या इसी तरह से सदन चलेगा? ? (व्यवधान) आप उनको अलाऊ कर रहे हैं । यह बहुत गलत है । मुझे अपनी बात रखने दीजिए । मणिपुर एक संवेदनशील मामला है ।? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, रूल 216 यह कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही होगा । यह हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा ।? (व्यवधान) कांग्रेस वाले चिल्ला कर मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते हैं । यह रूल कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा कीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : इस तरह से आप मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते हैं ।? (व्यवधान) यह रूल है । यह संविधान है । यह देश संविधान से चलेगा । यह हाउस संविधान से चलेगा । आप केवल बजट पर बात कीजिए । आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बात कीजिए ।? (व्यवधान) आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं ।

स्पीकर सर, ये लोग चिल्ला नहीं सकते हैं ।? (व्यवधान) यही रूल कहता है । स्कोप यही है, इससे आगे नहीं है ।? (व्यवधान) ये लोग चिल्ला कर मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते हैं ।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, मुझे टाइम दीजिएगा ।

माननीय अध्यक्षः मैं आपको टाइम दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है ।

नियम 216, अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक सीमित होगा, जिसमें बने हों और चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने, उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर उससे संबंधित नीति पर चर्चा होगी । यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं । आपने जिस कानून का उल्लेख किया, वह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया जाए । इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में, यह क्यों यहां पर आया है, उस संदर्भ में मैं यहां पर बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं । मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप हैं या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे हैं । यह आपको तय करना चाहिए । ?(व्यवधान) आप हैं सर ।? (व्यवधान) आप पूरा सुन रहे हैं । ? (व्यवधान) यह आज तय होना चाहिए कि कौन है? यह तय होना चाहिए ।? (व्यवधान) आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है, उसका वहां उल्लंघन हुआ है । ? (व्यवधान) मैं आपका सम्मान कर रहा हूं । उनको इसमें क्यों दिक्कत है? मैं आपका सम्मान करता हूं । Sir, I recognise you only ? (*Interruptions*) I do not recognise anyone from the Treasury Benches.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज एक मिनट । आप बैठे-बैठे मत बोलिए । मैंने उनको पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने की परमीशन दी थी, तब वे बोले । मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं, बाकी तो सदन में बोल सकते हैं लेकिन यह अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोलें ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, we are discussing on the Budget of Manipur.? (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I want to raise a Point of Order.? (*Interruptions*)

***m12 माननीय अध्यक्ष :** क्या मैं आपको इजाजत दूं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, मैंने अभी आपको इजाजत नहीं दी है ।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पर है । आपने पिछले ढाई सालों से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है । आप विफल रहे हैं । आप बंदूक के दम पर शांति लाने की व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए । प्रधान मंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं । लोगों के मन में क्या भय है, उसको सुनें । राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकती है । हम सकारात्मक रूप से यहां पर सुझाव दे रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि जब भी देश का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, तो ? *

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत करिए ।

श्री गौरव गोगोई: प्रधान मंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं । वे शांत हो जाते हैं ।? (व्यवधान)

***m14 माननीय अध्यक्ष :** पहले भी सदन के अंदर, चलते सदन में पूर्व के प्रधान मंत्री जी भी गए हैं और जब भी माननीय प्रधान मंत्री जी जाते हैं, तो सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं । प्रधान मंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं । आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है ।

***m15 श्री गौरव गोगोई:** हम प्रधान मंत्री जी का सम्मान करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए ।

श्री गौरव गोगोई: हम प्रधान मंत्री का सम्मान करते हैं । जब हम वर्तमान प्रधान मंत्री का सम्मान करते हैं तो बार-बार पूर्व प्रधान मंत्री पर ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों प्रयोग करते हैं और उनकी बातें रिकॉर्ड पर क्यों आती हैं? इस पर भी आप बाद में सोचिए । हम सभी प्रधान मंत्री, वर्तमान और पूर्व प्रधान मंत्रियों का सम्मान करते हैं । लेकिन, जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है, बार-बार रिकॉर्ड पर आता है । हमारा तो यह रिकॉर्ड में रहेगा या नहीं, पता नहीं, कल पता चलेगा ।

***m16 माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट, वित्त मंत्री जी कुछ कह रही हैं ।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): You said something very profound. You have said something very profound. I would like to add one thing to it.

Sir, with due respect, it was music to my ears to hear from a leading Member of Opposition party saying that प्रधान मंत्री जी का सम्मान करते हैं ।

Quickly to add, when the Treasury Benches talk about the previous Prime Ministers, they speak not in *sammanjanak* language. How many times has the Prime Minister been abused in this House by them, and how many times was he not allowed to speak in this House? ? (*Interruptions*) They stood in the Well and shouted? ? (*Interruptions*) Will the hon. Member, Gaurav Gogoi apologise for the number of times they have used the abusive names against the PM? Today, he is ironing out all that.? (*Interruptions*) He is whitewashing all that. That is not enough. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong, and they should not do it again. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Through you, hon. Speaker, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last Session. His entire speech was abusing the former Prime Ministers.? (*Interruptions*) I have written a letter to you putting on record the number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. ? (*Interruptions*) So, please, before pointing fingers, अपने घर में कुछ झांके ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: This is not done, Sir. If it is this, very clearly, I have to read the speech. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Hon. Finance Minister, I do not expect this from you. What is this going on? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I name the Members who stood up here and named the Prime Minister with abusive language. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, have the patience to listen. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Look at the way in which all of them are shouting. Why are they shouting? What Gogoi said is wrong? Is that what they are saying?? (*Interruptions*) Is that what they are saying? If Gogoi had the large heartedness to say that we should not abuse anybody, then, what is going on? That shows the attitude of the Congress party.

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर बोलिए न, गौरव जी, आप बजट पर भी तो कुछ बोलें । आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं । यही आपकी स्ट्रेटजी है, आपको सुनने की ताकत नही है । दोबारा फिर से ? (व्यवधान) यही स्ट्रेटजी है, ? (व्यवधान)

***m24 SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** He started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister.? (*Interruptions*) None of them will agree. They do not want to agree. I will get up every number of times. ? (*Interruptions*) When an hon. Member says that he respects the Prime Minister, and that should be the attitude there, that Member is honourable enough but not the rest.? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए यह बात उठाई है क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं । अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर चर्चा हो चुकी है, उसमें भारत ने कबूल कर लिया है कि टैरिफ घटेगा?

माननीय अध्यक्ष: इस चर्चा में टैरिफ कहां से आ गया ।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, यह टैरिफ क्यों आ गया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं । यह टैरिफ ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, यह टैरिफ टैक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, यह टैरिफ जैम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, यह टैरिफ स्टील-नट्स के साथ जुड़ा है, यह टैरिफ किसानों के साथ जुड़ा हुआ है । हमें अपने किसानों को बचाना है । हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर टैरिफ्स घटाने

के लिए अमेरिका को सूचित किया है । यह बात मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा क्योंकि बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री जी का पसर्नल मैटर होता है ।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए ।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, इसमें अनपार्लियामेंटरी क्या है?

माननीय अध्यक्ष: जिस विषय पर डिबेट हो रही है, आप उस बात कीजिए । क्या आप पॉलीटिकल बात करेंगे? क्या यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा है, बजट पर चर्चा है । यह तरीका ठीक नहीं है, आप उप नेता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है । आप उपनेता हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है । आप बजट पर चर्चा कीजिए, सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पर चर्चा कीजिए । आप मणिपुर की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पर चर्चा कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, माइक बंद है ।

माननीय अध्यक्ष : हां, माइक बंद हो जाएगा, अगर ऐसी बात बोलेंगे तो ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, हमें किसानों की बात करनी है । ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके बारे में बात करनी है । टेक्सटाइल सेक्टर में जिन लोगों को रोजगार मिलती है, हमें उनके बारे में बात करनी है । हम उन्हीं के हित के बारे में बोल रहे हैं । कौन-से क्षेत्र में टैरिफ घटा है, यह बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं? क्योंकि बहुत से मामले में वे व्यक्तिगत रूप से नेगोशिएट करते हैं । राफेल के मामले में भी उन्होंने नेगोशिएट किया था । इसलिए, हम जानना चाहते हैं कि कौन-से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा । सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलेगा । नियम-216 में क्लीयर नियम-प्रक्रिया है । मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं और आप बार-बार विषय को डायवर्ट करते हैं । आप फिर कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया गया । सदन तो नियम-प्रक्रियाओं से चलेगा ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, पूरा देश देख रहा है । पूरा देश जानना चाहता है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या जानना चाहता है? आप आइटम नम्बर-15 से आइटम नम्बर-19 के बारे में बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित है । ट्रेड डिफिसिट को लेकर पूरा देश चिंतित है ।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको अंतिम बार बोल रहा हूं । अगर आप इधर-उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना पड़ेगा । ? (व्यवधान)

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, पूरा देश देख रहा है ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन तो नियमों से ही चलेगा । अगर आपको नियम के अनुसार बोलना है तो ठीक है । हम आपको नियम से बाहर नहीं बोलने देंगे ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, बार-बार ऐसे उदाहरण आते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आप बीच-बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए । सदन के अंदर गुस्सा मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

***m29 श्री गौरव गोगोई:** सर, बार-बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि सरकार एक कदम उठाती है और फिर दो कदम पीछे जाती है । इसका एक उदाहरण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है । यह सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वर्ष 2015 में लाई थी । अभी हाल के बजट में जब इनका यह स्कीम फियास्को हो गया, पूरा स्कीम फ्लॉप हो गया तो ये स्कीम को बंद करना चाहते हैं । क्यों? इनकी मंशा यह थी कि बाहर से जो गोल्ड का इम्पोर्ट आता है, वह घटना चाहिए । जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया था तो सरकार के प्रेस रिलीज में यही बात थी । Now, I would like to know from the hon. Finance Minister whether gold imports, since 2016, have gone up or gone down. Which one of your objectives of the Sovereign Gold Bond Scheme have you achieved? We want to know about this. You have got the Sovereign Gold Bond Scheme thinking that it will help Government borrowings. But now, your liabilities are such that even in this Budget, you have to pay around Rs. 8,900 crore. Over the past few years, the Government's liabilities have exceeded by 930 per cent, and you have to pay close to Rs. one lakh crore. This is why close to 67 tranches of sovereign gold bond payments have been withheld by this Government. In this Government, they only care about headlines; they only care about speeches; they only care about optics; and they do not understand what is happening on the ground.

अब बात जीएसटी की बात आती है । जीएसटी के बारे में तो हम बोल सकते हैं न? अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is the discussion on Supplementary Demands for Grants.

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, please have patience. ? (*Interruptions*) You can say all this in your reply. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Please speak on the topic. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI : Madam, you hear your speakers also. ? (*Interruptions*) When your speakers would speak, please tell them the same thing. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Please speak on the topic. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: If I am saying anything which is not related to finance or economy, please tell me. ? (*Interruptions*)

अब जीएसटी के बारे में बोलना चाहता हूं । कारमेल पॉपकॉर्न अलग, नॉन-कारमेल पॉपकॉर्न अलग, जीएसटी में फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन्हीं के सरकार के समय में, फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि सिर्फ रेट कट से नहीं होगा । आपको जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार लाना पड़ेगा । लगभग 100 रेट्स हैं । इतने सारे असेसेज हैं, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं ।

सर, आप यह जानकर हैरान होंगे कि आज मंदिर पर भी जीएसटी है । यह सरकार धर्म को लेकर देश के लोगों के बीच में जाती है ।

उन्होंने कुछ वर्षों पहले मंदिरों पर भी टैक्स लगा दिया है, जो हिन्दू धर्म और चेरिटेबल एन्डाउनमेंट्स में आते हैं । एक स्कूली पेंसिल, एक स्टेशनरी और यूनिफॉर्म पर भी इन्होंने जीएसटी लगाई है । GST has become a new tool for blackmail, extortion and evasion. The GST rates have become a new architecture for harassment. Moreover, tax evasion has also become easy and increased during the last few years. In 2023, evasion of GST has doubled to Rs.2 lakh crore.

अब ये हैरासमेंट का एक और टूल निकाल रहे हैं । वह आयकर विधेयक है, जो फिलहाल सेलेक्ट कमेटी में है । आयकर विधेयक में एक प्रावधान है कि आज एक आयकर अधिकारी आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर सारी चीजें देख सकता है । आपका पूरा सोशल मीडिया देख सकता है । हमारी सरकार के द्वारा लाए गए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में जितनी ताकत नहीं है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 में जितनी ताकत नहीं है, आज ये उतनी ताकत आयकर अधिकारियों को देना चाहते हैं । इनकी क्या मंशा है? हमें सब पता है । They are using income-tax to harass people, shopkeepers, small traders, and small businesses. आज लोगों के बीच यही चिंता है ।

माननीय अध्यक्ष: आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलिए, आप वित्त विधेयक पर बोलिए।

श्री गौरव गोगोई : महोदय, मैं एक और उदाहरण देता हूं । ये क्यों भाषण पर इतना निर्भर हैं? इनके भाषणों का जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं है । इन्होंने भाषण में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25 प्रतिशत बनाना है । ये कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी पीएलआई की बात करते हैं, कभी शेर दिखाते हैं । हां, इन्होंने हैडलाइन मैनेज की है । वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें तो हैडलाइन मैनेज हो गई है । उसमें वर्ष 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी, आपने वर्ष 2019 में उसको 63 किया है । आपने इस रैंकिंग को इम्प्रूव किया है, यह हमने माना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की वास्तविक स्थिति क्या है? There has

been a drop in the value-added manufacturing in GDP. In 2010, manufacturing was 17 per cent of the GDP which today has dropped to 12.9 per cent. यह वास्तविक स्थिति है । ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना मैनेज करने के बाद भी आज मैन्युफैक्चरिंग घटी है, as a percentage to GDP.

आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट घटा है । आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहां पर होना चाहिए? उन सेक्टरों में जहां पर हमारे लोगों को मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है । वे सेक्टर्स क्या हैं? वे सेक्टर्स हैं ? अपेरल, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स और वुड पेपर है । यहां पर जिस प्रकार की सहायता देनी चाहिए, वह नहीं मिली है । वहां पर जिस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । वास्तविकता में क्या हो रहा है? जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनको जहां-जहां निवेश करना होता है, उनको जहां-जहां अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, उन जगहों पर पीएलआई स्कीम्स और सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार का समर्थन दिया जाता है ।

आज जो मध्यम वर्ग है, उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर है । इसीलिए क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है । आप देख रहे हैं, मुझे भी बहुत दुख होता है कि पलायन हो रहा है । हर वर्ग में पलायन हो रहा है । आपने देखा होगा कि कोविड और रशिया-यूक्रेन युद्ध के समय क्या हुआ था? उनको कम पैसों में शिक्षा मिल सके, इसलिए आज वे चीन जा रहे हैं, आज वे यूक्रेन जा रहे हैं । यह पलायन है । आज हमारा जवान अग्निवीर योजना में नहीं जा रहा है, बल्कि वह रशिया-यूक्रेन जाकर वहां के युद्ध में भाग ले रहा है, ताकि उसको थोड़ी पगार मिल सके, ताकि वह अपने घर में कुछ पैसे भेज पाए ।

महोदय, आप कभी पूछिए कि जो बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी हैं, आज उनके बेटे-बेटियां भी उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जा रहे हैं । सबसे दुख की बात यह है कि एक मजदूर को सपना दिखाया गया था कि आपको हर साल दो करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आज वह अपनी जमीन बेचकर अमेरिका जा रहा है । अमेरिकी सरकार उसको पकड़ती है । उसके हाथ और पैर को बेड़ियों से बांधा जाता है और उसको वापस आना पड़ता है । आज हमारा निवेशक भी भारत छोड़कर जा रहा है ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ नेता हैं । आज जिन विषयों पर बोल रहे हैं, क्या वह अनुदानों की मांगों पर है? आप बजट पर बोलिए, वित्त विधेयक पर बोलिए, टैक्स एंड पॉलिसी पर बोलिए । आप एक वरिष्ठ नेता हैं ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, जब उनकी तरफ से बात आए, तब सुनिएगा ।

माननीय अध्यक्ष : उनका जवाब तो देना पड़ेगा ।

श्री गौरव गोगोई: सर, इतना करने के बाद भी आज प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी भाग रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स में भी पलायन है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल में भी पलायन हो रहा है और मजदूर पलायन कर रहे हैं । आज पंजाब का किसान कनाडा में जाकर खेती कर रहा है, लेबर मिडिल ईस्ट में हैं, छात्र यूक्रेन और चीन में है । यह वास्तविक स्थिति है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे दूसरे वक्ताओं को बुलाना है । आप अनुदानों की मांगों को पढ़कर नहीं आए हैं ।

श्री गौरव गोगोई : सर, वह आपका निर्णय है ।

माननीय अध्यक्ष : आप अनुदानों की मांगों पर बोलिए ।

श्री गौरव गोगोई: सर, वह आपका निर्णय है । हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं । Private investors pulled out maximum funds in 2024 as they sold USD 27.9 billion via 224 exits. सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा है? सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को कितना कुछ दिया है । उनका लोन माफ कर दिया, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया है, उनको लैण्ड दे रहे हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट समिट दे रहे हैं । उसके बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा है और रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका एक ही कारण है ? वीक कंजम्प्शन, वीक डिमांड । जब पेट पर लात पड़ती है, जब हर चीज पर जीएसटी लगता है, जब महंगाई पूरे महीने के बजट को खा जाती है तो आम आदमी बाजार से क्या खरीदेगा? यह खरीद नहीं हो रही है, उसके कारण आज निवेश घट रहा है ।

मैं चाहता हूं कि सरकार भाषण और हैडलाइन मैनेजमेंट में अपनी पार्टी के मंच पर बात करे, लेकिन सदन के अंदर और देश के सामने देश की जो वास्तविक स्थिति है, उस पर बात रखे । आज इन्फॉर्मल सेक्टर भी बढ़ रहा है । इन्फॉर्मल सेक्टर में 85 परसेंट लेबर है । आज उस इन्फॉर्मल सेक्टर में भी मैन्युक्चरिंग की जगह नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आज आप बजट पर चर्चा की तैयारी करके आ गए हैं?

श्री गौरव गोगोई: सर, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं । आपके कोटा क्षेत्र में बहुत इन्फॉर्मल सेक्टर्स हैं । आप कोटा में जाइए, मैं उनकी बात कर रहा हूं । वे लोग बोल रहे हैं कि ढाबे पर काम करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, होटल में टेबल साफ करने के अलावा कोई चारा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है । The share of the manufacturing sector in the total number of informal enterprises fell from 31 per cent in 2015 to 27.4 per cent in 2023-24. सवाल बस इतना है कि मेक इन इंडिया कहां गया, मेक इन इंडिया क्या काम कर रहा है? मेक इन इंडिया से आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा पाएं है, न ही आप मेक इन इंडिया से इन्फॉर्मल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाएं हैं और न ही मेक इन इंडिया से आपने लोगों को रोजगार देने की बात की है ।

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, कुछ अनुदानों की मांगों पर बोल लीजिए ।

श्री गौरव गोगोई: सर, आपने ठीक कहा है । मैं अब डिफेंस पर आता हूं । ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे: सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको नियम बता दिया है, वही नियम है ।

श्री गौरव गोगोई: सर, मैंने कुछ नहीं बोला है । आप उनको अनुमति क्यों दे रहे हैं? आपने अभी मुझे सुझाव दिया है और मुझे बोलने के लिए बोला है तो आप मेरी बात सुनिए ।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए और अपनी बात को खत्म कीजिए ।

श्री गौरव गोगोई: सर, यहां पर जो नई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आई है, इस पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात है । पूरे देश में सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमारे लिए पुरानी पेंशन स्कीम लाइए । आज हम उनकी मांग सदन के अंदर रख रहे हैं । आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं और डिफेंस पेंशन का उल्लेख किया गया है, लेकिन डिफेंस का व्यक्ति भी यह कह रहा है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वह मात्र 25 परसेंट है । आज डिफेंस का टोटल बजट लगभग 79 बिलियन डॉलर है,

लेकिन मैं तुलना के तौर पर कह रहा हूं कि चीन जैसे देश का 256 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है । दुनिया के हर कोने में विभिन्न देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं । यूके में बढ़ा रहे हैं, जर्मनी में बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में डिफेंस बजट मात्र चार परसेंट है । अग्निवीर और डिफेंस के पेंशन बजट में आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसको आप परे रखिए । आप राष्ट्रीय सुरक्षा को अकाउंटिंग एक्सरसाइज मत बनाइए, राष्ट्रीय सुरक्षा को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नजर से मत देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को टेरिटोरियल इंटिग्रिटी से देखिए ।

सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं । आपने हमें बहुत समय दिया है । आपने यह भी देखा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बहुत समय लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ नाइंसाफी न हो, हमारी पार्टी के सदस्यों को पर्याप्त समय मिले । मैं बार-बार उसी चीज पर आऊंगा, क्योंकि मणिपुर का बजट आज क्लब हुआ है । गृह मंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा और मैंने कई बार गौरव गोगोई जी को भी कहा है कि हम प्रयास करें कि जिन विषयों पर चर्चा हो, उन विषयों के इर्द-गिर्द ही अपने विषय को रखें तो उचित होगा ।

श्री बिप्लब कुमार देब ।

श्री बिप्लव देब जी ।

? (व्यवधान)

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर मुझे बोलने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं । सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलते हुए मैं पहले माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो देश की अर्थ मंत्री हैं, को बधाई देता हूं । वर्ष 2025-26 का जो बजट उन्होंने पेश किया है, वह सराहनीय है । वह देश की ग्रोथ रेट को दिखाता है । इसमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के आसपास का बजट पेश किया गया था और पिछले बजट से 7.4 परसेंट ज्यादा इन्क्रीज किया गया है । अनुमानित जीडीपी का जो नॉमिनल ग्रोथ इन्फ्लेशन के साथ है, वह 10.1 परसेंट रखा गया है ।

महोदय, इस बजट में 7.4 परसेंट इन्क्रीज किया गया है और साथ ही साथ जीडीपी रेट 10.1 परसेंट तक लेकर जाने की जो हिम्मत है, वह नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है और श्रीमती निर्मला सीतारमण जैसी महिला ही कर सकती है, जिनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं कहना चाहता हूं । उन्होंने इसे प्रस्तुत करके इस देश को सशक्त व आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए हमारे देश के भविष्य, हमारे नौजवान भाई-बहनों को नई दिशा देकर सशक्त अर्थनीति की तरफ जाते हुए दिखाया है । इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक विकास, सशक्त आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ, कांग्रेस, जिसकी सरकार ज्यादातर समय भारत में रही है, हमारी जो लायबेलिटीज तैयार की गई थीं, ज्यादातर लायबेलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबेलिटीज इनके समय ही हुई थीं । उनको भी कम करने के लिए बजट में, वर्ष 2031 तक 50 परसेंट लायबेलिटीज कम करेंगे, इस बजट में दर्शाया गया है ।

महोदय, केवल बढ़ाना ही नहीं है । आर्थिक व्यवस्था को केवल सशक्त ही नहीं करना है, जीडीपी रेट को केवल बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि साथ-साथ लायबेलिटीज, जो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से रखी गई थीं, वे भी हमारे 140 करोड़ जनता के ऊपर से कम हों, इसका रास्ता भी माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस

बजट में रखा है । मणिपुर में क्या हुआ? गोगोई जी अभी यहां बोल रहे थे । मुझे मालूम है कि मणिपुर का आयतन कितना है । हो सकता है कि बहुत सारी विधान सभाओं को इसकी जानकारी भी न हो, क्योंकि यह नॉर्थ-ईस्ट का एक छोटा-सा स्टेट है ।

नॉर्थ ईस्ट के छोटे-छोटे स्टेट्स हैं । मैं भी त्रिपुरा से आता हूँ । 22 हजार स्क्वायर किलोमीटर का मणिपुर है । वहां पर 38 लाख लोग रहते हैं । मणिपुर में चुराचांदपुर कहां है? इम्फाल कहां है? कितना डिस्टेंस है? कितने नेशनल हाइवेज़ हैं? मणिपुर में पहला रेलवे स्टेशन किसने बनाया था? मणिपुर को इतने कम्युनिकेशन्स के साथ किसने जोड़ा है? मणिपुर के तीन नेशनल हाइवेज़ को किसने बनाया है? चुराचांदपुर का पहला नेशनल हाइवे किसने बनाया है? क्या इन सबका जवाब कांग्रेस के पास है?

मणिपुर में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है । चुराचांदपुर में जो ... * है, वहां पर एक भी नेशनल हाइवे कभी नहीं रहा । वहां पर नेशनल हाइवे का काम नितिन गडकरी जी को जाकर, वहां खड़े रहकर करवाना पड़ा । चुराचांदपुर में हमारे ट्राइबल लोग हाइवे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे । आज मणिपुर की बात होती है । वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक मणिपुर के लिए जो बजट होता था, उसे वर्ष 2014 से 2025 तक माननीय प्रधान मंत्री जी ने 143 गुना इंक्रीज किया है । ये लोग मणिपुर के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं । मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो संविधान के तहत ही हुआ है । छः महीने के अंदर सेशन बुलाना पड़ता है । सेशन नहीं हो पा रहा था इसलिए उस कारण से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । हमने बलपूर्वक लागू नहीं किया है । वह संवैधानिक व्यवस्था है और लागू करना पड़ता है । दोनों तरफ के सदस्य चाहते हैं कि मणिपुर में शांति आए । ट्रेज़री बैंच तो चाहती ही है, लेकिन विरोधी पक्ष भी चाहता है कि मणिपुर में शांति आए । नार्थ ईस्ट में शांति रहनी चाहिए । गौरव गोगोई जी नॉर्थ ईस्ट से ही हैं । उनके पिताजी असम के लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहे थे । उस समय नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, वह सबको मालूम है । आज नॉर्थ ईस्ट के 75 परसेंट एरिया में AFSPA नहीं है । यह नरेन्द्र भाई मोदी जी के कारण ही हुआ है । मैं त्रिपुरा के जिस स्टेट से आता हूँ, वहां भी लंबे समय से AFSPA रहा है, इंसर्जेंसी रही है । उसका भी नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद ही समापन हुआ है ।

अब नॉर्थ ईस्ट में शांति और डेवलपमेंट है । ये दोनों चीजें नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकी हैं । सरकार आने के बाद ही आज नॉर्थ ईस्ट के मुख्य मंत्री को लोग जानते हैं । आज लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जानते हैं । इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को असम ही माना जाता था । हम जब कभी किसी को दिल्ली में बोलते थे कि हम त्रिपुरा से हैं तो लोग पूछते थे कि त्रिपुरा कहां पर है? मैं बोलता था कि मैं अगरतला से हूँ तो लोग पूछते थे कि अगरतला कहां पर है?

माननीय अध्यक्ष : अब तो आपके यहां मुख्य मंत्री बनने के बाद लोग जानने लग गए है न?

श्री बिप्लब कुमार देब : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है । साथ ही साथ मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । इस बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ । बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में 20 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं ।

13.54 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

यह प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है । हमारे थर्मल पावर कोयले से संचालित होते हैं । इसकी एक सीमा है । एक सीमा के बाद हमारे थर्मल पावर्स कोयले के द्वारा नहीं चल सकते हैं । इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसके तहत उन्होंने न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के मिशन की घोषणा करके 20 हजार करोड़ रुपये उस मिशन के लिए रखे हैं । इसमें स्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था होगी । इस स्कीम के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है । पावर के बिना कोई भी सेक्टर नहीं चल सकता है, न एग्रीकल्चर सेक्टर चल सकता है, न प्राइमरी सेक्टर चल सकते हैं और न इंडस्ट्रीयल सेक्टर ही चल सकते हैं । बिजली के बिना तो हमारे घर की लाइट भी नहीं जल सकती है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने 20 हजार करोड़ रुपये की घोषणा करके न्यूक्लियर पावर की तरफ भारत को ले जाते हुए, नौजवानों के भविष्य के लिए एक अच्छी शुरूआत की है ।

सभापति महोदय, इसमें निवेश के लिए सरलीकरण किया गया है । प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स मिल कर काम कर सकते हैं । इस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने काम किया है ।

सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या रखा गया है, तो इसमें एक यह है कि किसी को भी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है । स्वाभाविक तौर पर इससे मिडल क्लास लोगों को ही सुविधा मिलेगी । इसके साथ-साथ 36 लाइव सेविंग ड्रग्स को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है । यह एक बड़ी रिलीफ है, जो हमारे मिडल क्लास और अंतिम छोर के लोगों के लिए किया गया है । साथ ही साथ, 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, वे चाहे किसी भी जाति के हों, उनकी कोई भी इनकम हो, उन सभी को पांच लाख रुपए की इंश्योरेंस की योजना के तहत रखा गया है ।

प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना इस देश के लोगों के लिए लायी गयी है । जब हम छोटे थे, तो यह सुनते थे कि यूरोपियन देशों में लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है । सरकार लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचती है । यह हमारी कल्पना होती थी कि हमारी सरकार कभी हमारे हेल्थ के लिए भी सोचे । मैं माननीय प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस देश में किसी के पैदा होने के बाद, उनके परिवार, माता-पिता, पहले बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे रखते थे, बेटी की शादी के लिए पैसे रखते थे और इलाज के लिए पैसे जमा करते थे । हमारे जैसे गरीब परिवार के लोग इन तीन चीजों के लिए बैंक्स में पैसा जमा करके रखते थे, क्योंकि बेटी का विवाह करना है, बेटे को पढ़ाना है और उनका इलाज कराना है । आज ये तीनों दायित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने ले लिए हैं । अभी बेटों की पढ़ाई के लिए पैसे रखने की जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई है । अगर आपके बच्चों में मेरिट है तो वे विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं । आपको पैसे जमा करके रखने की जरूरत नहीं है । आपको इलाज के लिए पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को इलाज के लिए पांच लाख रुपए की दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी है । भारत में बेटियों के विवाह के लिए भी पैसे रखे जाते थे । एक प्रावधान था कि बेटी बड़ी होगी, तो उसकी शादी के लिए पैसा जमा करें । आज इस सोच से भी भारत मुक्त हो चुका है । इसलिए निर्मला सीतारमण जी जैसी महिला देश की अर्थ मंत्री हैं । जो सोच अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, उस सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है । आज किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस प्रथा को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूला दिया है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज एमबीबीएस की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में की जा सकती है । पहले हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी में पढ़ाई करनी पड़ती थी । भारत के गांवों में कितने इंग्लिश मिडियम स्कूल्स हैं, वे वहां कैसे जाएंगे,

वे कैसे हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे? अंत्योदय परिवार के बच्चे कैसे एमबीबीएस, एमडी, इंजीनियरिंग और, आईआईटीज में पढेंगे? उनको कौन अंग्रेजी पढ़ाएंगे? आज नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं गर्व करता हूं कि कोलोनियल लॉ को खत्म करते हुए, देश में एमबीबीएस-एमडी की पढ़ाई भी क्षेत्रीय भाषा में की जाती है । इसमें बहुत देरी हुई है । अगर यह बहुत पहले होता तो आज भारत में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहता ।

साथ ही साथ, इस बजट में यह भी है कि अगले वर्ष एमबीबीएस की दस हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी और अगले पांच सालों तक 75 हजार सीट्स बढ़ाई जाएंगी । इन सीट्स पर पढ़ने वाले कौन व्यक्ति होंगे, वे जो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेने वाले होंगे, कॉर्पोरेट-पॉलिटिकल खानदान वाले होंगे, उनमें ये नहीं होंगे । उनमें गरीब व्यक्ति पढ़ने आएंगे ।? (व्यवधान) वे बंगाल से भी होंगे ।? (व्यवधान) दीदी भी गरीब हैं ।

14.00 hrs

दीदी भी गरीब घर से उठकर आई हैं । ? (व्यवधान) मैंने देखा है, इस तरीके से किया गया ।? (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन लाए हैं । सोनिया गांधी जी खुद यूपीए चेयरपर्सन रही हैं, उन्होंने इस रिजर्वेशन बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं के दल के लोगों ने यहां उसे फाड़कर रख दिया । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण पर काम किया गया है और 33 परसेंट महिला रिजर्वेशन लाकर मोदी जी ने दिखा दिया कि मोदी जी शेर हैं, मोदी जी अकेले ही सब काम कर सकते हैं । मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते   हैं ।

इस बजट में 5 लाख महिला उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक सहज किश्तों में लोन देने का प्रावधान किया गया है । इसका मतलब है कि महिला सशक्तिकरण का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है । एसएचजी ग्रुप के लिए बड़ी मात्रा में सरलीकरण करके लोन की व्यवस्था की गई है । इस बजट में देश में गरीब किसानों के लिए तीन यूरिया प्लांट्स का प्रावधान रखा गया है । मैं नार्थ-ईस्ट से आता हूं । मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूं कि असम के कामरूप में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा । पूर्वी क्षेत्र में यूरिया प्लांट लगने से किसानों का भविष्य अच्छा होगा । किसानों की उपज का उत्पादन बढ़ाने का स्थायी काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश में किसानों के लिए सबसे बड़ी स्कीम ?किसान सम्मान निधि? के तहत 6000 रुपये तीन किश्तों में यानी 2000 रुपये किसानों को देने का काम किया है । इस बजट में केसीसी लोन को बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया गया है । ये किसानों की बात करते हैं । ? (व्यवधान) आज यहां देखो सब सीटें खाली हैं क्योंकि ये किसानों की बात सुनना नहीं चाहते हैं, सब चले गए हैं । ? (व्यवधान) इनके सामने सिर्फ चीन की बात करो, पाकिस्तान की बात करो तब तो सब बैठे रहेंगे, जैसे ही किसानों की बात होगी, नहीं बैठेंगे । महिलाओं की बात करो तो नहीं बैठेंगे । ? (व्यवधान) कल्याण दा, आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है । आपके युवराज बजट पर बोल रहे थे, मैंने देखा था । वह बोल रहे थे कि मोदी जी की सब स्कीम्स हॉफ होती हैं । युवराज भी अभी हॉफ मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको सब कुछ हॉफ दिखता है । ? (व्यवधान) नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो काम किसानों के लिए किया है, आज इसे सुनने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हैं । गोगोई जी भी चले गए हैं क्योंकि इस पर उनका इन्टरस्ट नहीं है । ? (व्यवधान) जनता को क्या देना है, क्या लेना है ।? (व्यवधान)

देश के स्वाधीन होने के बाद भी अंग्रेजों के तीन कानून पड़े हुए थे । डेढ़ सौ साल पुराने तीन ब्रिटिश कानून इस देश में लागू किए गए थे क्योंकि ये कानून एक परिवार को सुरक्षा दे रहे थे । ? (व्यवधान) इन कानूनों के माध्यम से इमरजेंसी लगा सकते थे । देशद्रोह का केस उस समय ब्रिटिश कानून था । देशद्रोही केस की डेफिनेशन थी, सरकार के खिलाफ, सरकार के व्यक्ति के खिलाफ कोई बोलेगा तो राजद्रोह का केस लगता था । आज माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तीन नए कानून लाए हैं, देश के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह का केस होगा, व्यक्ति के खिलाफ बोलने पर, सरकार के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह का केस नहीं होगा । लेकिन यह कांग्रेस को सूट करता था क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार को सुरक्षित रखना था । आप उस परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो राजद्रोह का केस लगाएंगे । आज इसका समाधान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है । ? (व्यवधान) कल्याण दा, हम और आप एक ही जैसे हैं । आप मेरे से बड़े हैं । ? (व्यवधान)

इस बजट में उड़ान स्कीम में पांच साल में 120 नए डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे ।

क्या एविएशन सेक्टर देश का उन्नयन दिखाता नहीं है? मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं । हमारे स्टेट में लम्बे समय तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से अगरतला के लिए नहीं थी । आज मैं खुशी के साथ बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा के अगरतला में डायरेक्ट दो-दो फ्लाइट्स दिल्ली से जाने वाली हैं । यह नरेन्द्र भाई मोदी जी के समय हुआ और यह दिखाता है कि त्रिपुरा के लोगों की इनकम बढ़ी है । उसका प्रमाण यह है कि त्रिपुरा के लोगों की पर-कैपिटा इनकम 1 लाख 77 हजार रुपये हो चुकी है । वर्ष 2017-18 में जब कम्युनिस्ट की सरकार वहां चलती थी तो सिर्फ 1 लाख रुपये पर-कैपिटा इनकम थी और आज 1 लाख 77 हजार रुपये पर-कैपिटा इनकम हो चुकी है । नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद यह दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, चाहे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सभी क्षेत्रों का समान तरीके से विकास किया और डोनर (DONER) मंत्रालय भी हमारी सरकार के समय ही बना है । जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था । इससे पहले वह नहीं बना था और उसी दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने काम किया है । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विषय रखा गया है । इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है और उसके रिसर्च के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है । आज देश किस दिशा में चल रहा है? क्या हमारे देश की जनता को, नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लस और माइनस दोनों हैं । आप उसमें कुछ भी डालिये, कुछ भी लिखिये, आपको बहुत सारी भाषाओं में उसका जवाब तुरंत मिलता है । क्या उसका जवाब जानने का अधिकार गरीब को नहीं है? इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक दूरदर्शी तरीके से 2 हजार करोड़ रुपये रखे हैं । साथ ही साथ इस बजट में स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी । गांव के स्कूलों में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी । स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गूगल चलाकर, इंटरनेट चलाकर, उनको कोटा में जाकर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडबैंड के माध्यम से गांव के स्कूलों में बैठकर उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था होगी । वे लोग वहां से एमबीबीएस डॉक्टर्स बनेंगे, वहां से इंजीनियर्स बनेंगे । यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है । ? (व्यवधान)

मैं डिजिटल इंडिया के बारे में कहना चाहता हूं । मैंने देखा कि गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि मोदी जी तो लॉयन ही लॉयन दिखाएंगे, शेर का मुंह दिखाया है । आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में दुनिया में

तीसरे स्थान पर है, जिससे 12 परसेंट जीडीपी का लाभ भारत सरकार और 140 करोड़ जनता को होता है । उसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी को जाता है । ? (व्यवधान) दादा, आप युवराज को मुख्य मंत्री बनाओ, दीदी को जाकर बोलो । वह अच्छा काम होगा । मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने नए कानून के साथ-साथ, पराधीन भारत का जो चेहरा दिखाता है, याद कराता है, हमने राजपथ का नाम बदलकर, कॉलोनियल सोच को बदलने के लिए उसका नाम कर्तव्य पथ रखा है । रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा है । दादा, रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर आपके नाम से लोक कल्याण मार्ग रखा गया है । यह तृणमूल ने नहीं किया । मोदी जी ने लोक कल्याण मार्ग रखकर कल्याण जी को पूरी दुनिया में पहचान दिया है । ब्रिटिश की जो व्यवस्था थी, हमने उससे मुक्त कराया है । 1500 कानूनों को माननीय प्रधान मंत्री जी ने समाप्त किया है । देश स्वाधीन होने के बाद पहले प्रधान मंत्री जी को ही वह काम करना चाहिए था, किन्तु वह काम नहीं किया गया । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिप्लव जी अच्छा बोल रहे हैं । आप बोलने दीजिए ।

श्री बिप्लब कुमार देब : महोदय, जब किसी का जन्म होता है, तो माता-पिताजी बच्चे के लिए क्या सोचते हैं?

वह कल्पना करता है कि मेरा बेटा-बेटी दुनिया में नाम करें, मेरा नाम रौशन करें, यही कामना करता है । यहाँ बैठकर अपॉजिशन बेंच के हमारे बहुत सारे साथी कल्पना करते हैं कि खुद के घर में कोई संतान पैदा हो, तो इंजीनियर पैदा हो, वह डॉक्टर बने और आम जनता के घरों में कोई संतान पैदा हो, विशेष कर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र सोचते हैं कि वह श्रमजीवी तैयार हो । मनरेगा में काम करने के लिए किसी का जन्म हो, क्या दुनिया में ऐसे माता-पिता हैं, जो अपने बच्चे के लिए सोचते हों कि जन्म लेने के बाद मेरा बेटा बड़ा होकर मनरेगा का काम करे? मेरा बेटा बड़ा होकर श्रमिक बनेगा, क्या कोई कम्युनिस्ट के नेता ऐसा सोचने वाले हैं? अपने बेटे-बेटी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा, लेकिन भारत की जनता को श्रमिक बनाकर उनका शोषण करने का काम कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने लम्बे समय तक किया है । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसकी समाप्ति हुई है । आज स्कूल, कॉलेज और सभी व्यवस्थाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए नौकरी, पढ़ाई और ट्रेडिंग आदि की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की है ।

महोदय, हमारे देश में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग एक सौ स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज भारत में लगभग 1,59,000 स्टार्टअप्स हैं । हम इस पर गर्व करते हैं कि नहीं? हमारे देश में, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए, उनमें जॉब क्रिएटर्स तैयार हुए हैं । आपने रोजगार की बात की, तो स्वरोजगार बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी की आर्थिक पॉलिसी ने किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स शुरू हुए । उनमें बड़ी संख्या में जो नौजवान काम करते हैं, उनमें से 16.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिले हैं । यह काम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय में, केवल एक परिवार के लिए काम किया जाता था । एक ही परिवार के नाती-पोते आदि सबको कैसे एकोमोडेट किया जाता है, इसके लिए काम किया जाता था । लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, राज्यों को जो 32 परसेंट शेयर दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 42 परसेंट किया गया है । यह बंगाल, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश आदि सभी राज्यों को दिए गए । इसके साथ ही, राज्यों को 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बॉरोइंग पावर दी गई है, इस बजट में इसका भी प्रावधान किया गया है । अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है ।

मैं आशा करता हूँ कि इस बजट से पूरे देश को लाभ होगा और नौजवानों के लिए एक नया भविष्य देखने और तैयार करने की जो आशा-आकांक्षा है, उसके साथ ही आर्थिक विकास को पूरा करने का सपना, जो हमारे देश के नौजवानों, किसानों और मिडिल क्लास के लोगों ने देखा है, मैं आशा करता हूँ कि इससे सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश का कल्याण होगा । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 में, भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा ।

महोदय, मेरा समय समाप्त हो गया है, आपने इसका इशारा दे दिया है । इसलिए मैं अपने विषय को कंक्लूड करता हूँ । इसके साथ ही, इस सप्लीमेंटरी ग्रांट्स और बजट को हम सब मिलकर सपोर्ट करें एवं हम सब देश की तरक्की में एक साथ आएं, मैं ऐसी आशा करता हूँ ।

आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अनुपूरक मांगों और मणिपुर के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

मान्यवर, मैं पहले अनुपूरक मांगों के बारे में चर्चा करूँगा । मैं देख रहा था कि अनुपूरक मांगों के माध्यम से बहुत ही लम्बी-चौड़ी डिमांड आयी है ।

इसमें तमाम विभाग लिए गए हैं । 2024-25 के फाइनेंशियल इयर का यह अंतिम महीना है । इसमें जो इतने अनुदान मांगे गए हैं, उनसे कुछ शंका भी पैदा होती है । इसमें सबसे पहला जो मद लिया गया है, वह कृषि और कृषि कल्याण विभाग का लिया गया है । आज कृषि के क्षेत्र में, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे किसान हैं, वे बहुत दुखी और परेशान हैं । वे सिर्फ यह सपना ही देखते रह गए कि हमारी आय कब दोगुनी होगी? आज किसान बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ।

कृषि अनुसंधान तो कहीं हो ही नहीं रहा है, उल्टा, जो किसान है, वह गाय से परेशान है । गाय के प्रबंधन के लिए गौशाला बनाने की बात हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ । माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम इससे छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । इसमें पेंशन का मद भी है । पूरे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे लगातार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं । उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लगातार इसकी मांग आ रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं । लेकिन इस सबके बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है । जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन उनके बुढ़ापे का सहारा होती थी । आज कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा का संकट भी इससे पैदा हो रहा है । इसलिए, जो पेंशन इसमें रखी गई है, तो सरकार इस पर भी विचार करे कि उसको पुरानी पेंशन लागू करनी है ।

इसमें उर्वरक का मद भी है । अभी जब गेहूं की बोवाई हो रही थी, तो खाद की इतनी किल्लत थी कि जब किसान खाद लेने के लिए जा रहा था, तो वहां खाद थी ही नहीं, लोगों को लाठियां मिल रही थीं ।

मान्यवर, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बारे में भी इसमें बजट की मांग की गई है । उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार ने बना ली है । जब स्कूल बंद करने की बात हो रही है, तो यह बजट कहां ले जाएंगे? स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया कि सरकारी स्कूलों में संसाधन नहीं हैं । बड़े-बड़े लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में संसाधन नहीं हैं और वहां गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं । अत: मान्यवर, यह जो बजट जा रहा है, यह स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए जा रहा है या

स्कूल को बंद करने के लिए जा रहा है? इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि जब तक पीडीए के लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, गांव के किसान, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तब तक कैसे भारत विकसित होगा? अगर विकसित भारत बनाना है, तो एक देश, एक शिक्षा लागू करनी चाहिए । यदि एक प्रकार की शिक्षा की सबके लिए शिक्षा व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जरूर विकसित भारत बनेगा ।

मान्यवर, इसमें पुलिस विभाग के लिए भी पैसा मांगा गया है । पुलिस विभाग का भी बजट इसमें मांगा गया है । पुलिस की क्या स्थिति है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अभी बनारस में ?नीट? की तैयारी करने के लिए बिहार की एक बिटिया स्नेहा कुशवाहा आई थी । कितनी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई । जब पोस्टमॉर्टम हाउस में पीएम हो रहा था, तो पुलिस ने वहां जाकर जिस तरह का व्यव्हार किया, जिस तरह की बर्बरता की, मुझे लगता है कि इस पर भी सदन को और सबको चिंता करनी चाहिए और उस बिटिया को न्याय कैसे मिले, इस पर भी चिंता होनी चाहिए । जब तक जमीन पर व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक जमीन पर काम नहीं होंगे, तब तक सिर्फ बजट मांग लेने से कुछ नहीं होगा ।

अभी श्री बिप्लब कुमार देब जी बोल रहे थे, अब वे चले गए हैं । उन्होंने बड़ा गुणगान किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, पास कराया गया । क्या रखने के लिए पास कराया गया है? यह सरकार सदन को बताए कि वह उसको कब से लागू करेगी? केवल महिलाओं को बरगलाने से काम नहीं चलने वाला है । हमारे यहां की महिलाएं स्वावलंबी बनें, हमारे यहां की महिलाएं भी यहां, सदन में आएं, इसके लिए आपने यह कार्य किया है । आपके इस कार्य का स्वागत है, लेकिन यह लागू कब होगा? क्या यह केवल भाषणों में चलता रहेगा? इसलिए, उसको लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, इसमें मणिपुर का बजट भी शामिल है । मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है । यहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है । यहां की अर्थव्यवस्था कैसी और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है । मणिपुर में उच्च शिक्षा की भी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन सब ठप पड़ी हुई हैं । यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं थीं, परंतु डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण केवल दंगे हो रहे हैं और हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर समाधान का इंतजार कर रहा है । मणिपुर और मॉरीशस, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मॉरीशस से आएं तो मणिपुर भी चले जाएं । वे मणिपुर जरूर चले जाएं । मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, माननीय वित्त मंत्री जी को यहां उसका बजट रखना पड़ रहा है, अच्छा होता कि यह बजट वहां की विधान सभा में पास होता । यह अच्छा होता कि वहां के लोग इसको तय करते, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मणिपुर का बजट यहां लाना पड़ रहा है ।

मान्यवर, पिछले दिनों वहां की सरकार ने जो बजट पास किए हैं, एक बार उनकी भी जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं वह बजट इन दंगों को भड़काने में तो नहीं इस्तेमाल कर लिया गया । जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसका हल ढूंढने में ना तो केंद्र की सरकार ने और ना ही राज्य की सरकार ने कभी कोई राजनीतिक इच्छा का इजहार किया । मणिपुर के हालात बेहद खराब रहे हैं । गृह मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023 से समूचे पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसाएं हुई हैं, उनमें लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा हिंसाएं मणिपुर में हुई हैं ।

मान्यवर, मणिपुर में हुई हिंसा में सैंकड़ों नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है । महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी शब्द समझ के मुंह पर तमाचा है । वह बहुत बड़ा तमाचा

है कि ऐसा वीडियो आया । मणिपुर मई 2023 से अभी तक बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा का शिकार बना हुआ है । हिंसा का दौर अभी जारी है । सरकार लगातार दावा करती आ रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत देर के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है । उन्होंने गलती मानने में बहुत देर कर दी । आज वहां के जो हालात हैं, जातीय संघर्ष में जिन हजारों लोगों की जान चली गई है, जो हजारों परिवार बेघर हुए हैं, उनके लिए भी इस मणिपुर के बजट में चर्चा आयी है कि हम उनको बसाएंगे, लेकिन उससे पहले यह याद रखा जाना चाहिए कि जो हिंसा की ये घटनाएं हुई हैं, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियाँ बनी हैं और जो बीरेन सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार के स्तर पर जो चुप्पी रही, पूरे भारत के लोग अब तक यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाओगे, लेकिन वे इस पर चुप हैं । प्रधानमंत्री जी इस पर चुप हैं । इसलिए गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राजधर्म का पालन करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मणिपुर शांति की तरफ चले । पूरा देश यह कहता है कि वह पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते । इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है । अब जबकि वहाँ का समाज बुरी तरह से बँट गया है और समरसता दूरी की कौड़ी हो गई है, सरकार ने वहाँ के लोगों को भरोसे में लिये बगैर दो फैसले लिए, जो विवादित रहे । भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना ।? (व्यवधान) इन फैसलों का मणिपुर के कई आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था ।? (व्यवधान)

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : सभापति जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है । इससे पहले भी चेयर से कहा गया कि रूल के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए । यहां रूल खंडित किया जा रहा है और हम सुन रहे हैं । यहां एक-एक जो वाक्य कहा जा रहा है, वह शायद हम समझ रहे हैं या नहीं रहे हैं, लेकिन इसके कारण मणिपुर में स्थिति बिगड़ने की परिस्थिति आ सकती है । एक-एक सेंटेंस का महत्व है । इसकी संवेदनशीलता को बनाए रखा जाए, इसकी संवेदनशीलता और सेंसेटिविटी के लिए हम सभी रिस्पोंसिबल हैं । मणिपुर जितना हमारा है, उतना आपका भी है । हम सभी सांसदों का यह दायित्व है कि वहां जान-माल की हानि हमारे किसी सेंटेंस के कारण न हो ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मौर्य जी, आप अपनी बात कंटीन्यु कीजिए, लेकिन थोड़ा विषय का ध्यान रखिए ।

श्री नीरज मौर्य: सभापति जी, अगर इतनी चिंता इन्होंने पहले की होती और वहां एक बार चले जाते, तो वहां व्यवस्था ठीक हो सकती है ।

मान्यवर, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया और निगरानी कमेटी बनाई है । मणिपुर बहुत बड़ा और जटिल राज्य नहीं है कि वहां की स्थिति से निपटना मुश्किल हो । यह परिस्थिति एक भ्रम की वजह से पैदा हुई है । अगर सरकार संजीदा होती, तो दोनों समुदायों के लोगों को आमने-सामने बैठा कर मसले का हल निकाल चुकी होती ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप आज के विषय पर बात कीजिए । आप लॉ एंड आर्डर की बात न करके आज के विषय पर बात कीजिए ।

श्री नीरज मौर्य: महोदय, बजट के अंदर लॉ एंड आर्डर सब्जेक्ट है इसलिए मैं लॉ एंड आर्डर पर बोल रहा हूं ।

माननीय सभापति : ठीक है, बोलिए ।

श्री नीरज मौर्य: मान्यवर, मणिपुर में गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है, उसे हाथ पर हाथ धरे सरकार कैसे देख सकती है? वहां शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों का आम सहमति पर आना जरूरी है । वहां जिस तरह से विवाद से जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल और दूसरे कानूनी पहलू बढ़ते जा रहे हैं, उनसे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चों पर है । इन सभी मुद्दों पर काम करने की जरूरत है । केवल भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा । संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ कदम उठाने की जरूरत है ।

सभापति जी, मेरा सरकार से निवेदन है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी का सहयोग और सुझाव लेकर मणिपुर में शांति की बहाली करनी चाहिए । अगर सरकार इस विषय में पहल करती है, तो पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ देने के लिए तैयार है और डाक्टर पात्रा जी इसकी पहल करें । डाक्टर साहब को यहां सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन सोचिए कि पूरे देश के लोगों कितना बुरा लगा होगा, जब वह विडियो आया था ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मणिपुर राज्य के लिए जो अनुपूरक बजट आया है, उसके लिए वित्त मंत्री जी से मैं और पूरा देश जानना चाहता है कि अमरीका के दवाब में जो टैरिफ कम किया गया है, वह टैरिफ कहां-कहां कम किया जा रहा है? टैरिफ आज कल चर्चा का विषय बना हुआ है । जो टैरिफ कम होगा, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी को सदन को देनी चाहिए? इन्हीं बातों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : सभापति जी, मैं अपनी नेत्री ममता जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से मुझे आज सदन में अपनी बात रखने का मौका मिला है । अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ कितनी एम्पावरमेंट हुई है, मुझे पता नहीं है । हालांकि मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई नहीं जानता है । जितने यहां बैठे हुए हैं, संभवत: उन सभी में से सबसे पुराना मैं ही होऊंगा । मैं उन्हें भली-भांति पहचानता हूं । वे बात भले ही महिला की करेंगे, लेकिन महिला के लिए कुछ नहीं करेंगे । यह हमारी लीडर ही हैं, जिन्होंने 40 प्रतिशत महिला सांसद इस लोक सभा में भेजे हैं ।

सभापति जी, हमने सुना था कि वर्ष 2022 में भारत पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा । वर्ष 2014 में जब सरकार आई थी, तब मैं भी उसी तरफ था । मैंने सुना था, जब यह कहा गया था कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, तब मैंने चार सौ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार उजागर किया था । जिस खेल ने मुझे आन-बान-शान दी, मैं जिस खेल में देश के लिए खेला था, वहां पर चार सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था । मैं इनके पास ले कर गया था । लेकिन उस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई । जिस प्रकार से विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, मुझे भी उसी विभीषण की तरह उस लंका से बाहर निकाल दिया गया था । मैं एक-एक चीज़ और राज़ इनके जानता हूँ । मैं उस विषय पर अधिक नहीं जाऊंगा । महिलाओं के बारे में इनकी क्या राय है, वह भी मैं जानता हूँ । वर्ष 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम सामने देखते रहे हैं । उन हसीन सपनों को कब पूरा होता हुआ देखेंगे, यह मालूम नहीं है । क्योंकि लक्ष्य यह था कि वर्ष 2022 में, जब अमृत काल होगा, हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब सबके सर पर छत होगी । सबके घरों में नल होगा । नल में जल होगा । गैस होगी, बिजली होगी ।

<u>**14.31 hrs**</u> (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

लेकिन यह लक्ष्य वर्ष 2047 पर चला गया है । जो वर्ष 2022 में होना था, वह वर्ष 2047 पर चला गया है । इस सदन में कितने ज़िदा होंगे, नहीं होंगे, मालूम नहीं, वे लक्ष्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, पता नहीं । यह

रूप है, स्वरूप है कि इतना आगे बढ़ा दो कि इंसान पूछने वाला न रहे । पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात है । बात यह भी थी कि दो करोड़ नौकरियां हर साल लगेंगी । यानी मैं 11वां साल न ले कर केवल दस साल ही ले लूं तो आज 20 करोड़ नौकरियां होती और एक परिवार में पांच व्यक्ति ले लूं तो सौ करोड़ लोग इज़्जतदार ज़िंदगी जी सकते थे । 20 करोड़ लोग नौकरी करते और उनके साथ पांच-पांच लोग परिवार में रहते तो सौ करोड़ लोगों का आराम से जीवन-पोषण हो सकता था । लेकिन बार-बार सुनने को यही मिलता है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन दे रहे हैं । 25 करोड़ लोगों को अभी गरीबी रेखा से निकाला गया है, यानी कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे । मैं यह कहना चाहता हूँ कि पैसा किसका है? जो राशन आ रहा है, वह पैसा किसका है? वह पैसा 140 करोड़ लोगों में से उन दो प्रतिशत लोगों का है, जो इनकम टैक्स देते हैं । कम से कम उन टैक्स देने वालों को धन्यवाद कर दीजिए कि आपसे जो कर लिया जा रहा है, उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है । लेकिन वह नहीं करेंगे, बात करेंगे मोदी जी की । देश में जो लोग हैं, उनको कभी भी धन्यवाद किया जाए, सो नहीं होगा । पांच ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है । पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़े को माफ कर दिया जाता है । उन पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है । हम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है । अगर कोई 36 लाख रुपये महीने में कमाता हो, अगर उस पर 30 प्रतिशत टैक्स आप पूरे साल का लगा लें तो दस लाख रुपये उसके चले गए, यानी सवा तीन महीने का टैक्स गया । उसके ऊपर जीएसटी लगा ली, तो डेढ़ महीने की सैलरी, जीएसटी भी 18 पर्सेंट खाने-पीने आदि सब पर लगी हुई है, वह चली गई है । मतलब पांच महीने की उसकी जो आमदनी है, वह टैक्स में चली जाती है । पूंजिपतियों का 14 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया जाता है, लेकिन वे किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहदत हुई, वह जब अपनी माँग करने के लिए आते हैं, तो उनसे पूछा नहीं जाता । यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है, और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आ कर आ कर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर ले जाते हैं और वह बेचारा किसान असहाय रह जाता है और अपने लोन की पूर्ति नहीं कर पाता है । जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकल खरीदता है, और हमारे घर में आ कर, लोगों के यहां खाना बांटता है, आप लोग भी स्वीगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट से मंगाते होंगे । वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसकी मोटरसाइकिल ज़ब्त कर लेते हैं । उसके रोज़गार का ज़रिया खत्म, उसका परिवार फिर भूखों मरता है । यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है ।

30 प्रतिशत टैक्स, दो प्रतिशत यानी 140 करोड़ लोगों में 2.8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं । 2.8 करोड़ यानी समझिए कि साढ़े तीन या चार करोड़ लोग टैक्स देते हैं । उनको 30 प्रतिशत में आप 12 लाख रुपये की छूट देते हैं । लेकिन, एक गरीब आदमी, जिन 80 करोड़ लोगों को आप पांच किलो अनाज देते हैं, उसको न तो तेल मिलता है, न मसाला मिलता है, न उसके पास गैस खरीदने की क्षमता है । वह बेचारा क्या करेगा? ऐसे में जीएसटी पर, चाहे तेल हो, साबुन हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, आटा हो, चावल हो, इन सब पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है । वह जीएसटी, चाहे पूंजीपति हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सब बराबर देते हैं ।

डारयेक्ट टैक्स में फायदा केवल उन दो प्रतिशत लोगों को हुआ, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं । अगर इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी जीएसटी में कमी की जाए तो सभी 140 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है । उनके खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचेंगे । मैंने एक बार पूछा था । अभी यहां राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं । इनसे मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, जीएसटी में कमी क्यों नहीं लेकर आते हैं, तो इन्होंने खड़े होकर मुझे जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल का भी नाम जीएसटी में है ।? (व्यवधान)

सर, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने उनको दिखाया । हुजूर, आपके बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूं । आपके बिना हम कहां जाएंगे? इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है । बिल्कुल, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है । टोटल 31 राज्य है । इनमें से 20 राज्य, यानी 16 राज्य में बीजेपी तथा चार और मिला दे तो एनडीए मिलाकर 20 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है । 11 राज्य गैर भारतीय जनता पार्टी के हैं । टोटल 31 राज्य हुए । इन्होंने जीएसटी में प्रावधान किया हुआ है कि केंद्र सरकार, जिस दिन जीएसटी की मीटिंग होगी, जितने सदस्य बैठे होंगे, उन सदस्यों की एक-तिहाई वोट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी । मान लीजिए कि अगर 31 राज्यों का फुल हाउस हो, उसमें से एक-तिहाई इनका है, तो 10 हो गया । 21 और 10 राज्य मिलाकर 31 हो गया । 11 राज्य इधर हैं । आपके हाथ में इतनी ताकत है, आप जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यही बात कह रहा हूं । आपने बिलकुल सही बात कही । आपने कील के माथे पर हथौड़ा मारा है । You have hit the nail on the head. अगर इनके वोट में 10 मिला लूं तो इनके 31 लोग हैं । इनके 20 राज्य हैं । उसके ऊपर 10 राज्य आए । जब ये 30 लोग बैठे हुए हैं तो फिर तेल, पनीर, घी, दूध, आटा, चावल का रेट कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां इनकी ही मेजॉरिटी है । जीएसटी काउंसिल में तो इनको ही मेजॉरिटी बनानी है, किसी और को थोड़े ही बनानी है ।

सभापति महोदय, आपने जो कहा, उसके अनुसार मैंने भी सही कहा । यहां कंसेंसस है । आपने जो कहा, वही फैक्ट मैंने आपके सामने कही । एक बार हमने प्याज की बात सुनी । माननीय वित्त मंत्री महोदया से कहा गया कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं । तब उन्होंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती हूं, इसलिए मुझे प्याज का दाम नहीं मालूम है ।

सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल तो हम भी नहीं खाते हैं, लेकिन दाम तो मालूम है । ? (व्यवधान) We do not eat petrol and diesel like she does not eat onions, but yet we know the price. हमें पेट्रोल और डीजल का प्राइस मालूम है । सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर 19.9 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगायी हुई है । डीजल पर 5.8 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगायी हुई है । इन्होंने इन दिनों इसको बढ़ाया हुआ है । जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी । मैं दिल्ली की बात करता हूं । उस समय पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर था । जिस समय माननीय नरेन्द्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बन कर आए, उस समय कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल थी ।

उस समय जब बात चलती थी, तब हम भी खड़े करके चिल्लाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल की मार, अबकी बार टन, टन, टन सरकार । ? (व्यवधान) अब वही बोलना पड़ेगा न, क्योंकि हुआ कुछ नहीं । हम यही बोलते थे । पेट्रोल तब 60 रुपये प्रति लीटर था । ? (व्यवधान) मनमोहन सिंह जी के समय 112 डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 65 रुपये था । आज वर्ष 2025 में 80 डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार रहे हैं, बेचारे विराट कोहली और रोहित शर्मा को सेंचुरी मारने में बहुत मुश्किल हो रही है । तीन सालों से सेंचुरी पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं? कर दें कम और नहीं तो ले आइए जीएसटी में । इन्हीं की मेजोरिटी है । ?(व्यवधान) सभापति जी, अगर आप कहें तो इनका जवाब दे दूं ।

माननीय सभापति : नहीं, आप जवाब मत दीजिए । आप अपनी बात कहिए ।

श्री कीर्ति आज़ाद : सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में हैं, तो वह पश्चिम बंगाल के अंदर हैं ।? (व्यवधान) गिरिराज जी, अपने बिहार से जाकर हमारे यहां भरवा लीजिए । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा है, इसलिए आप अपनी बात कहिए ।

श्री कीर्ति आज़ाद : ये मेरे घर में आकर, वर्ष 1999 में मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे । मैं क्या बोलूं?

माननीय सभापति : यह बात नहीं, पर्सनल नहीं ।

? (व्यवधान)

मान**नीय सभापति :** आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : ये मुझे बताएंगे । इनको बात करने का तरीका नहीं ।

माननीय सभापति : माननीय कीर्ति आज़ाद जी, आप अपनी बात करिए ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : इनको बात करने की तमीज नहीं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : क्या ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं? इनको बात करने की तमीज नहीं । अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है, इन्हें यह नहीं मालूम । सदन में किस तरीके से बात की जाती है, इनको यह नहीं मालूम । ये तुम-तुम करके बात कर रहे हैं । मैं इनसे आप-आप करके बात कर रहा हूं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय कीर्ति आज़ाद जी, आप अपनी बात रखिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता । ? (व्यवधान) ये देखिए, तुम करके बोलते हैं । यह तमीज है । मैं आपसे बात कर रहा हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय कीर्ति आज़ाद जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप भी वरिष्ठ हैं ।

श्री कीर्ति आज़ाद: मैं आपसे बात कर रहा हूं ।? *? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप फिर वही बात कह रहे हैं ।

? (व्यवधान)

मान**नीय सभापति :** यह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

? (व्यवधान)

मान**नीय सभापति :** माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : ? * ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह गलत बात है । यह सब बिल्कुल रिकार्ड में नहीं जाएगा । इस तरह के आक्षेप की आपसे अपेक्षा नहीं है । माननीय कीर्ति आज़ाद जी, इस तरह का आक्षेप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं लगा सकते ।

? (व्यवधान)

मान**नीय सभापति :** आप बजट पर बोलिए । माननीय कीर्ति आज़ाद जी, आप बजट पर बोलिए । इस तरीके की बात या किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप न करें ।

श्री कीर्ति आज़ाद : आप सुन रहे हैं कि वे क्या बोल रहे हैं ।

माननीय सभापति : उनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है । आप क्यों संज्ञान में ले रहे हैं? रिकार्ड में नहीं जा रहा है । आप संज्ञान मत लीजिए और अपनी बात कहिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए । कीर्ति आजाद जी को मैंने अवसर दिया है ।

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति जी, 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया है, वह वर्ष 2022 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, जिसमें एक जीएसटी है । 1 लाख 70 हजार करोड़ रूपया, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वर्ष 2022 से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया । उसमें जीएसटी का भी हिस्सा है । फेडरल इकोनामी है तो फेडरल जीएसटी तो आना चाहिए । आपने आवास का पैसा नहीं दिया, तो पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने लोगों को आवास का पैसा दिया । इन्होंने स्कूलों के लिए पैसा नहीं दिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए नहीं दिया । वह भी पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने अपने बजट से दिया । घर नहीं मिले, उसका भी बजट पश्चिम बंगाल की नेत्री ने दिया । इन्होंने आपत्तियां उठाईं, आपत्तियों का जवाब दिया गया । यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया, सब कुछ हो गया, जीएसटी काउंसिल में बैठक हुई, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर सब बातें हुईं ।

?स्वास्थ्य साथी?, ममता बनर्जी की सरकार वहां चलाती हैं, उसे सबसे बढ़िया स्कीम कहा गया । ?स्वास्थ्य साथी? जो किसी परिवार में सबसे बड़ी महिला होती है, उसके नाम से यह कार्ड होता है, प्राइवेट हो या पब्लिक अस्पताल हो, महिला, उसका पति, माँ-बाप, सास-ससुर और उनके बच्चे किसी भी निकटतम अस्पताल में जा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं । डायरेक्टली सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में पैसा दिया जाता है ।

केन्द्र सरकार से जो मिलता है, उसमें अनेकों मानक हैं, छत है तो नहीं मिल सकता है, मोटरसाइकिल है तो नहीं मिल सकता, साइकिल है तो नहीं मिलेगा, यह सुविधा 2011 के सेन्सस से है ।

माननीय सभापति : कृपया संक्षिप्त करें, आपको बोलते हुए पन्द्रह मिनट हो गये हैं ।

श्री कीर्ति आज़ाद : सभापति महोदय, संविधान के किस प्रावधान या किस धारा में यह लिखा हुआ है कि किसी एक रंग में अगर स्कूल या अस्पताल को रगेंगे तो पैसा मिलेगा । क्या हिन्दू धर्म में एक ही रंग है, हिन्दू धर्म में अनेकों रंग हैं । हमारे सनातन में अनेकों रंग हैं । ये चाहते हैं कि केवल भगवा में रंग दें । लेकिन भगवा के भी अनेकों रंग हैं । महादेव के सिर में चन्द्रमा इठलाता है, वह सफेद है, सोमवार सफेद है, चन्द्रमा का सफेद रंग है । मंगल हनुमान जी का है तो लाल है । बुध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरू हैं तो पीला है । शुक्रचार्य राक्षसों के गुरू हैं तो राख है । शनि महाराज का काला या नीला है । हमारे सूर्य देव इंद्रधनुषी हैं, सतरंगे हैं । उत्तर में शिव हैं तो सफेद हैं, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूरब में माँ काली हैं तो लाल सिंदूर और लाल टीका है । पश्चिम में गणेश हैं तो पीला है, फिर केवल भगवा कैसे मेरा हिन्दू धर्म का रंग है, मुझे समझ नहीं आता है । क्या आप चन्द्रमा को भगवा करेंगे? क्या हनुमान जी को भगवा करेंगे, क्या मेरी बहन, बेटी और माँ के लाल सिन्दूर को भगवा करेंगे?

मेरे पश्चिम बंगाल का रंग सफेद और नीला है । नीला शनि महाराज का रंग है । ये नीले को भगवा करना चाहते हैं । वर्ष 2021 में जब नीला करने के लिए आये थे, जब अपना ध्वज गाड़ने आये थे तो वर्ष 2021 में शनि महाराज का ढ़हिया लग गया । इस बार वर्ष 2026 में आएंगे तो साढ़े सती लगने वाली है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद । बोलने के लिए बहुत कुछ था लेकिन मेरे साथी ने समय ले लिया, इस कारण मुझे अपने वक्तव्य को छोटा करना पड़ रहा है । मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Hon. Speaker, Sir, thank you for this wonderful opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants.

I would like to start with something that is very fundamental to democracy which is ? cooperative federalism?. That is the foundation on which this democracy is being run; democracy is being executed as we speak today.

Sir, with cooperative federalism, revenue and burden have to be shared equally between the Centre and the States. Today, according to the structure that is there already, 60 per cent of the expenditure of the common citizenry is being borne by the States and the local bodies, whereas by law, they are only able to collect 40 per cent or less. So, the balance has to be taken via debt or other bonds that are available there. There is nothing wrong in taking a debt or a bond, but what happens is that in the last 12 years, there has been so much power that has been centred or taken to the Union Government, that for every reason, you have to have the approval of the Union Government for the Urban Local Bodies and the local bodies to function. Now, what this establishes is that it weakens the cooperative federalism that is needed for the proper running of this country, and it

establishes a more master-slave relationship, which, you know, in a democracy, is bound to fail.

Now, my colleagues also spoke about the divisible pool of resources getting reduced; more towards the Centre and less towards the states, which is currently at 42 per cent. They want to reduce it to 40 per cent. Again, we iterate that it is going to lead to more failures in the relationship between the States and the Centre because it is going against cooperative federalism. I take this opportunity also to iterate that Tamil Nadu contributes so heavily, and it only gets back 29 paise. This is for the record of the House. We are still very proud of the way that we contribute, and we still want to contribute more.

The next important point is about the income tax, the revenue and the basic revenue-expenditure section of this Government. The Union Budget has given the benefit of approximately Rs. 72,000 as tax benefit to people who pay taxes of up to Rs. 12 lakh. I also want to bring to the attention of the House that the average inflation rate for the last three years is six per cent ? retail inflation, food inflation, and other business-related inflation. Now, if you take 12 per cent of Rs.12 lakh at six per cent, it is almost Rs. 72,000.

What it does is that it nullifies all the benefits that the Union Government wanted to give to the citizenry, Sir. So, what we see is the benefit of inflation, which never accrues to the Union Government, State Government or the citizens. It is actually going to waste. The request from the Opposition is to properly take care of inflation and give the benefit that can actually lead to the reasons for withdrawal of the taxes, which is again the growth of the nation. Now, corporate tax is approximately 22 per cent of the overall collection and individual tax is at 24 per cent. It is a big shift. The burden of running the country is shifting from the corporates to the individuals. The individuals bear more responsibility in the running of the country, which again is not a good balance to be. Anywhere in the world, if you see, you have corporates taking up the burden of running the country because they are more capable. You still want individuals to create the wealth so that they can pass it on to the next generation rather than contribute to the growth of the economy through taxes. This is our point there, Sir.

Now, I would like to talk about the growth of direct taxes and indirect taxes. The growth of GST is going at approximately Rs.1.5 lakh to 1.8 lakh crore a year and income tax is at Rs.75,000 crore to Rs.1 lakh crore a year. This might be very healthy for showing that the country is growing with tax collection coming from other sources. If you go at the current rate, in the next three or four years, we are going to be at parity. Indirect taxes is going towards parity and is going to overtake direct taxes. Again, indirect taxes are tangential. It is not direct. It is not measurable. It has an iterative strain on the people who are doing

business, which is again not a good scenario. So, I want the Government to notice that this growth rate is going to affect the future growth of this country.

I also want to quantify the benefit of the tax cut the Government has given. There are approximately 122 million people who file returns and pay taxes. If you remove the business houses and the people, there are approximately 1.2 billion people. This 1.2 billion is not spoken about in excess or in the fair representation it needs across the budget. Of course, there is direct benefit transfer that is being accrued, that is being given to all those people. I also want to point out that 1.2 billion people live below 100 rupees a day. It is really difficult, but that is what we are. I also want to appreciate hon. Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin to start a direct benefit scheme for women, which is called the Magalir Urumai Thittam. The reasons why I am mentioning this here is that after the scheme was introduced, you had four States that followed the scheme ? Madhya Pradesh, Maharashtra, Delhi and the other northern State, which actually won the election for the ruling party. This means the scheme that is developed and implemented in the South has gotten to the North and has been successful. The reason is it actually enables very poor people to come up in life. The initiative of the southern governments to have social inclusion actually helps. That is the reason why the ruling party is actually winning elections in the North.

There is one point about Atmanirbhar. Atmanirbhar is about being self-sufficient. There is a lot of talk and appreciation about UPI. UPI is a very good scheme. It helps a lot of people. Today, it is cashless. But I also want this House to know that out of Rs.23 lakh crores of transactions that happens every day in this country under UPI, Rs.20 lakh crore are being cornered by two companies. These two companies are American-owned. So, what I am basically saying is that when I want to eat a vada pav or when I want to eat a dosa is known to the American companies before even NSSO captures it in the data points.

So, I want the House to know that the data of this country is actually being let out freely in the name of UPI.

Now, there is something called the Westphalian principle. Many able-minded men have helped me come to this principle. What it does and what it says is that the best form of governance or the best way to reach resource from point A to point B is through decentralization. I will give you an example also. Now, the Westphalian principle is highly applicable in countries like Germany and Switzerland. In Germany and Switzerland, they are called cantons. The Panchayat Raj that we call here is called cantons there. So, the Panchayat Raj there decides the resource allocation and the policy, industrial policy, local policy, expenditure, revenues etc. Today and in the last 50 years also, the rate of growth, the satisfaction or happiness index for the people in those two countries are much, much better than our country. I will also give the benefit of the doubt to the ruling Party. I will also learn

from the ruling Party if they can show me a democratically elected Government that overbeats or beats the Westphalian principle and establishes more social, economic and educational equality in the country. So, please take note that there is inequality in the system that is being developed. Your intentions are right, but at end of the day, it creates a more unequal society, which we still do not want or which any of us still do not want.

There is also another example of this. During the COVID-19 Phase-I, unfortunately, we had a lot of loss. Across the spectrum, we had lost people's lives. And of course, this is the first time, there was a pandemic, and the Central Government had believed that centralization of decisions would actually help, but what it led to happen was it was the highest mortality rate across regions, across places. I am not complaining, but I am just stating the facts here. In the second wave, the Union Government decided that the States can decide local regulations on what and how it has to be done. The result of that is you had better tracking, better control, and better control on the mortality rates overall. So, the real impact, even in our nation, even in this established relationship, will help if there is decentralization of power. With the resources that are being centralized across here in the Union Budget and the Union Government, States are pushed more towards borrowing now. Borrowing is not bad. It is good. It helps you grow faster than the resources. It helps you earn resources so that you can pay better.

I also want the House to note the debt to GDP ratio. The hon. Finance Minister, and the Treasury Benches have been talking about sustainable debt, debt that you can take and then pay back so that the next generation is not burdened with debt. Tamil Nadu's debt to GDP ratio is at 25.6 per cent. Today, Union Government?s ratio is at 57 per cent. So, if you earn something today, you are actually liable to pay Rs. 57 even today. I want the Union Government to notice that centralization of power and taking resource from the States is actually not helping the Union Government achieve the very same objective for which it is taking the money. So, decentralization is the way forward. I would want to bring it to the attention of the House.

Sir, a good amount of money is being spent on educating our future, sustaining our lead in education. Now in this budget, Rs. 1,200 crore were allocated to Sanskrit and up to 25 lakh people approximately have told that Sanskrit is their mother tongue. Now, if you take 25 lakh people and the Rs. 1,200 crore that is being allocated in this budget, it is approximately Rs. 50,000 per person who is knowing Sanskrit in this budget for this financial year. Now, Tamil got Rs. 40 crore. We are eight crore people. Sir, you are from UP. UP spends Rs. 4,000 per student per year, in educating them. I am not trying to judge or compare. I want this House to know that being unequal actually exacerbates being unequal. It is not going to equalize any one society against the other, and it is not going to help the nation grow. In

Tamil Nadu, even with Rs. 40 crore, we still do better. We still do far better because that is in our nature.

Tamil Nadu's Graduate enrolment ratio is at 47 per cent, whereas our national average is about 27 per cent.

15.00 hrs

What are we spending money for? We want our citizens to grow. We want our citizens to work. We want our women to get empowered so that they also contribute to the nation?s growth. Today, women?s participation in labour is at 44 per cent in Tamil Nadu. The national average is at 18 per cent. I leave it to you to decide what schemes of the Government of Tamil Nadu you can take it up at the Centre so that you can increase the average.

An important thing is the two-language policy. When we got Independence, UP, Rajasthan and Tamil Nadu were at the same level. Today, we are better because of the two-language policy.

HON. CHAIRPERSON: There is another speaker also. The time allocated is 15 minutes. Already, you have taken more than 12 minutes.

SHRI ARUN NEHRU: Sir, I will just finish in two minutes. The Central Universities were established under the Constitution to improve scientific temper. Everybody will agree that the Central Universities like IITs, IIMs are now given the mandate to improve scientific temper. We have incidences in certain universities in the South where very well-learned men are talking about how cow urine can actually be useful for human health. That is a wasteful expenditure of resources. There is a very good interaction about artificial intelligence and machine language. We have actually, in Tamil Nadu, moved from the two-language policy to a large language model. That is the language about which we talk. We are talking of those language models that can help workers to be more productive, rather than the policy of this Government which is actually giving AI to replace workers. So, I would like to draw your attention to this.

Tamil Nadu is not an adversary of the Union Government. We are partners in growth. We want to contribute. We are very proud to contribute. Your adversaries are outside this country. You name it anybody, we would like to be part of this Government.

Sir, I am just concluding. The Union Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman has time and again shown that she likes Tamil. She says, ?*Tamil en uier. Naan piranthathu Tamil Naduthaan.?* I come from Tamil Nadu. I represent the constituency where she was born. She was born in Musiri. It is a part of my constituency. All that I am asking the hon.

Finance Minister is to approve the dream of the constituency, which is actually to bring a simple railway line to the constituency and be like the Home Minister who is developing Ahmedabad and the hon. Prime Minister who is developing Varanasi. I hope that Madam can develop Musiri also by bringing there a railway line.

Thank you for the opportunity, Sir.

SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (HATKANANGLE): Thank you Sir, for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants ? Second Batch for 2024-25; Demands for Excess Grants of 2021-22; and discussion on the Budget of Manipur.

Through the Second Batch of Supplementary Demands for Grants, the Union Finance Ministry is seeking the Parliament?s approval for Rs. 6,78,000 crore as additional spending for the financial year 2024-25. This includes 52 Grants and three Appropriations. Of this net cash outgo, the actual additional spending requiring fresh funding amounts to Rs. 51,462 crore, while the rest is being offset by the savings and enhanced receipts across various Ministries. The latest allocation includes Defence pensions of Rs. 8,476 crore, Communications amounting to Rs. 10,910 crore; Finance amounting to Rs. 13,433 crore, and agricultural schemes amounting to Rs.6,400 crore. Meanwhile, Rs. 2,185 crore have been earmarked for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi along with Rs. 1,604 crore for the grants-in-aid under the scheme.

Sir, with regard to the Demands for Grants, I would like to bring to the notice of the House that the Government has been working for the welfare of the people of the country at large. The agricultural reforms, empowerment of farmers and strong value chain have made this possible. Now, we have to reach a bigger target by making full use of the agricultural potential of the country. In this direction, we have announced the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, whose aftershocks will be measured till the very end of the rural India.

विपक्ष की आदत है सरकार की हर योजना की आलोचना करना, लेकिन यह गवर्नमेंट ऐसी है, जिसने हमेशा ही देश के आम नागरिक को मद्देनजर रखते हुए योजनाओं का प्रावधान किया है और हर एक क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त करने का एक बड़ा प्रयास माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में चल रहा है । लेकिन आलोचनाओं के बीच शायद विपक्ष यह भूल रहा है कि आज देश नीतियों की बात कर रहा है । पहले देश सिर्फ स्कैम्स की बात करता था । इनके नेतृत्व में जब सरकार थी तब हमेशा ही स्कैम्स की बात होती थी । उनके द्वारा किए गए घोटालों की बात हुआ करती थी, लेकिन आज देश में नीतियों की बात चल रही है । जब नीतियां बनती हैं तो उसके लिए कारगर तरीके से काम करने वाली यंत्रणा महाराष्ट्र या देश के अन्य राज्यों में हो, पर्याप्त माध्यम से शुरू करने का काम करते हैं ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल विपक्ष के नेता ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने की कोशिश की । डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जब एक्सप्टेंस आ जाता है, किसी व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं तो विपक्ष के नेता भी उसी माध्यम से चुनकर इस सदन में आए हैं । लोगों के द्वारा जो मेंडेंट दिया गया है, उसको अपमानित और प्रताड़ित करने का काम विपक्ष की ओर से हमेशा किया जा रहा है । उनका यह कहना है कि ईवीएम में घोटाला है । ईवीएम की वजह से हम यहां चुनकर आए हैं, ऐसा कहना विपक्ष के लोगों का है । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम में घोटाला है तो जिस ईवीएम से हम लोग चुनकर आए हैं, वह अलग है और जिस ईवीएम से वे लोग चुनकर आए हैं, वह घोटाला वाला ईवीएम अलग है । हमारा ईवीएम यानी Economic Development Vision of Amrit Bharat and Mission for Viksit Bharat. ईवीएम का हमारा मतलब है कि लीडरशिप इस्टैबिलिश करके आगे ले जाने वाले एक अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए हम ईवीएम में आम आदमी को यहां मिशन की तरह देखते हैं और आम आदमी के डेवलपमेंट का मिशन लेकर प्रधान मंत्री जी आगे चल रहे हैं ।

मैं अपनी कांस्टिट्यूएंसी के कुछ मुद्दों को सभा के सामने रखना चाहूंगा और उसको मैं मराठी में कहना चाहूंगा ।

*In my constituency, there is a place called Ichalkaranji, which is a big textile hub. We need a technological upgradation for it urgently. The Central government started a very good scheme called TUF. Through this TUF scheme funding, technological gradation and modernization was going on in Maharashtra which was promoting this sector. But, today no funding is available through this scheme and that is why the power loom operators are facing difficulties. So, on behalf of the state Government, I would like to request central Government to provide funding through this TUF scheme once again for technological advancements.

The latest AI technological has already been introduced in textile as well as in agriculture sector. Hence, while imparting technical education to the textile students, we much train them for AI integrated techniques. Through this technical knowledge, we can take India to the next level in this sector.

I would like to add one more fact. Maharashtra is known for its cooperative movement and we have pioneered it. The people related to this movement took it to grassroots and extended its benefits to everyone and all.*

आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं । इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गन्ना किसानों की उनके पास है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है । गन्ने से आय को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें उसके लिए कुछ धोरण का निर्माण करना शासन के माध्यम से जरूरी है । मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि एथनॉल का यूज़ अभी जो 25 परसेंट है, अगर उसे 50 परसेंट कर दिया जाए और एथनॉल का एक स्टैंडर्ड रेट मैंटैन किया जाए तो किसानों को भी इससे ज्यादा आमदनी होने की संभावना है ।

दूसरा, जो पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के बारे में बात की जा रही है, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाने में हम सफल हो सकते हैं । डोमेस्टिक यूज के लिए कन्ज्यूमेबल शुगर यहां यूज़ की जाती है । घर पर लगने वाली शुगर बहुत कम रहती है । इंडिया की कुल पॉपुलेशन के हिसाब से जो शुगर निर्माण होती है, उसमें से केवल 30 परसेंट शुगर डोमेस्टिक यूज के लिए दी जाती है । 70 परसेंट शुगर कॉमर्शियल यूज के लिए दी जाती है । उसमें पेप्सी, कोला, कैडबरी जैसी कंपनियां हैं । दो अलग-अलग रेट्स पर यदि इन दोनों माध्यमों को लिया जाए, तो सस्ते दामों पर किसानों को मिले, आम जनता को मिले और जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री इसमें आ रही है, उसके लिए अलग रेट हो, तो निश्चित रूप से गन्ना उत्पादक किसान के लिए बहुत बड़ी सहूलियत इसके माध्यम से होने वाली है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में इसका इनक्लूजन करें, जिसके माध्यम से खेती में और अच्छी प्रोग्रेस हमारे यहां हो सके ।

तीसरा, एक महत्वपूर्ण विषय पैनगंगा नदी प्रदूषण का, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं । एक प्राधिकरण बनने की जरूरत है । आज हमने प्रयागराज में इतना बड़ा उत्सव मनाया, जिसके माध्यम से पूरे देश में अपनी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में पैनगंगा नदी को ग्लोबली रिवर ऑफ पॉयजन के नाम से पहचाना जा रहा है । हमारे यहां वर्षों से बहुत अशुद्ध पानी पीने की समस्या चली आ रही है । इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण को कांस्टीट्यूट करना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से इसकी मॉनीटरिंग हो और निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए यहां हमें प्रमोट करना पड़े ।

चौथा, अल्माटी नामक जो पुराना डैम है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है । मैं केंद्र सरकार को इस मामले में इन्टरवीन करने की विनती करता हूं, क्योंकि इससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बहुत सारे बाढ़ पीडित इलाकों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है । मेरे संसदीय क्षेत्र में हर साल बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो जाता है । उसका सर्वे होने की बहुत जरूरत है । निश्चित रूप से जो ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, उसका काम रुकना चाहिए ।

माननीय सभापति : कृपया कनक्लूड करें ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि ईपीएस-95 नाम से पेंशन दिए जाने की जो घोषणा की गई, जब मैं लास्ट टर्म में आया था, तब भी मैंने इसकी सूचना केंद्र सरकार को दी थी । हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे जवाब मिला था, लेकिन आज तक वे बेचारे पेंशनर्स यह आस लगाए बैठे हैं कि यह सरकार हमें न्याय देगी । उनकी यह मंशा है कि आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनकी पेंशन बढ़ेगी । इस मान्यता के साथ वे हमेशा आंदोलन करते रहते हैं । उन सभी लोगों की ओर से, मैं आपसे यह गुहार लगाना चाहता हूं कि बहुत दिनों से यह इश्यू पेंडिंग है । कृपया सरकार इसे अपने संज्ञान में लाए । निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है ।

माननीय सभापति : कृपया कनक्लूड करें ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: महोदय, मेरी पार्टी का टाइम है । मैं दो मिनट में कनक्लूड करता हूं ।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी का टाइम हो गया है, तभी मैंने आपसे बोला ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: महोदय, कोल्हापुर को दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है और टूरिज्म का एक बड़ा हब है । यह किलों का भी गढ़ माना जाता है और करवीर निवासिनी महालक्ष्मी जी का मंदिर भी वहां है

। तिरुपति जाते समय लाखों श्रद्धालु कोल्हापुर होते हुए जाते हैं । अत: एक टूरिज्म सर्किट यहां बनने की जरूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज की आवश्यकता है । आईटी, एक अच्छा सेक्टर, जो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, कोल्हापुर से बहुत सारे बच्चे आईटी सेक्टर में काम करते हैं । उनके लिए भी एक आईटी पार्क कोल्हापुर में यदि बन पाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका फायदा नवयुवकों को होगा तथा एक अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से चलती रहेगी । अत: आईटी पार्क, कोल्हापुर की जरूरत है, इस हेतु आपके माध्यम से सरकार को सूचना दी जाए ।

अंत में, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना भाषण खत्म करूंगा । हमारे यहां गडकरी साहब आए थे और उन्होंने ड्राईपॉड की घोषणा की थी । जमीन भी हमारे यहां उपलब्ध करने का काम नीचे चल रहा है । देश में अच्छे उपक्रम चल रहे हैं, जिनमें से एक ड्राईपॉड का उपक्रम है और लॉजिस्टिक्स के लिए सांगली, कोल्हापुर, आजू-बाजू के इलाकों के लिए एक मध्यवर्ती ठिकाना कोल्हापुर का है, जिसके माध्यम से इन सारे लोगों को इकोनॉमिक कॉरीडोर का दर्जा मिल जाएगा और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी संधि इससे उपलब्ध हो जाएगी । मैं आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की है, उसकी पूर्ति आने वाले समय में करें । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं । जय हिंद, जय महाराष्ट्र ।

SHRI ALFRED KANNGAM S. ARTHUR (OUTER MANIPUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you. I thank my Party for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants for 2024-25. At the outset, I would like to say that when I first stepped into this hall of democracy, I swore an oath that I would bear true faith and allegiance to the Constitution of India as per law established.

Today, I would like to point out to the august House that the State of Manipur has one Article which is enshrined in this Constitution. It is Article 371(C). I will read this out:

> ?Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the Hill Areas of that State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of such committee.?

It is a Constitutional provision. As per that, on the 20th June, 1972, a notification for Presidential Proclamation was issued by our former President Shri V.V. Giri. This notification is very clear. It has many paragraphs and schedules. Out of that, I would like to quote what is relevant to the Budget:

> ?Before any Five Year Plans or annual plans of the State are finalised by the Government of the State, proposals in this behalf shall show separately the plan schemes proposed to be taken up in the hill areas and the rest of the State and it shall be placed before the committee and the views of the committee shall be taken into account before the plans are finalised.?

Sir, I have belief in our Constitution and I am very certain that this House too believes in it. We have already bypassed our Constitution through this Budget. This is the Budget. It is in the Member?s portal. I have had it printed out. For the first time, I am seeing eight different forms of presentations. I have been in the State Legislature. That is why I am saying this. This is the second Budget Session for me in this Parliament. It is a very simple document. Why have you made it so complicated? What does the law of this nation say?

The disproportionate assets should not be created between the hills and the valley. About 95 or 98 per cent of the hills are occupied by the tribals in Manipur. When disproportionate assets are created, problems do occur. It is my duty to bring forth before this august House if there are any anomalies.

In the year 2021, somewhere around from August to October, we have had the privilege of calling on the hon. President, Shri Ramnath Kovind. Shri Amit Shah was the then Home Minister. The present Parliamentary Affairs Minister was the then Law Minister. We met with Shri G Kishan Reddy. We placed before them the problems that were being faced in the State of Manipur wth regard to administration of the hills. I was a part of that delegation. It was a full delegation of the Hill Area Committee.

When we met all our esteemed leaders of this nation, we were assured that all our grievances would be looked into. Though the State of Manipur may have made a nominal provision, I never expected that the Union of India today, when we are in the Opposition or in a position to ensure that the legislation of business with regard to the budget of Manipur, is clearly as by law established, has not yet adhered to that. I have already chaired six meetings of DISHA committees.

The marginalized and the poor of our nation, and so also of my constituency survive on NREGA. Do you know the status of NREGA today? These are reports from the District Collectors in the DISHA meetings from all departments. In 2023-24, 50 per cent of the material component of NREGA has not been released, and also in 2024-25, nothing has been released. The mandates that are being given are 25 per cent in a year. There is no increase this time in the Union Budget again. We are passing this Budget, there is no increase.

HON. CHAIRPERSON: It is a demand-driven scheme.

SHRI ALFRED KANNGAM S. ARTHUR: Sir, I agree. I know of this scheme.

When the Government is not releasing material component for 2023-24, how does the Government expect those poverty-stricken, marginalized people to create more? How are

they going to work more if this is a committed liability scheme? The Government is committed to pay. The Union Government does not even clear the dues of 2023-24.

HON. CHAIRPERSON: There is a clear-cut ratio 60:40 labour component.

SHRI ALFRED KANNGAM S. ARTHUR: Sir, that is why, I am saying. I know the facts and figures, and I am very clear in this, Sir. The Government has not released into There is an injustice to the State. The Government is not even increasing the budget, what to talk of clearing the dues. Two years dues are not yet cleared.

When the Government talks of the National Social Assistance Program, what is the status today? The last payment was made in the month of March 2023.

You talk of the National Old-Age Pension Scheme or the widow pension scheme. In all those schemes, the fund was released way back in 2023. Why are those schemes there when the most marginalized people are left to die. I have not seen the budget reflecting that, that they will pay off. Nothing is given here. You talk of all of these Centrally-Sponsored Schemes. You go scheme-by-scheme or program-by-program, and you will understand that they are the same replicas of what has been happening always.

Sir, the nation needs to grow. Manipur is the lowest per capita income generating State in the nation. I repeat, it is the lowest per capita income generating State in the nation. Why is this? Why has the NITI Aayog, or be it the Planning Commission at one point in time, or the State Government, today the Central Government, not made sure that course corrections have been made so that we also increase our GSDP? You are not focusing on the core areas. For agriculture and horticulture, there is no increase in the budget. There is no increase. The hills are redundant today. There is no income. Around 90 per cent of the State of Manipur is hills, lush green hills. We are an agrarian society which survives and we have been adapting to change because our forefathers have taught us what it is to survive through agriculture. There is no scope for growth. Where do we sustain? Are we depending on NREGA? If it is NREGA, even there also, you do not even release the funds? The Central Government is not releasing the funds, and the State Government is not formalizing the actual plans that will be required for inclusive growth. If you will go into the figures, it is dismal.

Today, I want to challenge the hon. Finance Minister, and so also the hon. Transport Minister. I would like him to come and see. Forget about Mumbai-Delhi highway where you have spent Rs. 50,000 crore. I have no problem. It is my nation, and we have to grow. Come to my constituency which is about 20,000 square kilometres. I will show him the sort of roads that his Ministry is making. You will say: ?Are these roads provided to you? You are citizens of this nation. Are you actually serious? Are the budgets being provided?? This time

when I had spoken to NHIDCL officials in the Disha Committee meeting, what did they say? They said the work orders are issued before the land is acquired. How can the Government start issuing work orders before completion of land acquisition process? Are we a society that is working on contractual basis or is it for a chain of delivery for the common man? Today there is no delivery. There is nothing.

The Government is talking about JJM Scheme. I am sure the hon. Finance Minister will come back later and say that जेजेएम में यह किया गया है, पीएमजीएसवाई में यह किया गया है, पीएमजेवीके में यह किया गया है I You are going to say about many things that you have done, and I will refute each one. I know I will not get a chance to rebut the hon. Finance Minister, but I am pre-empting her reply. I will say very clearly today that every single thing that she is saying today is only on paper. I challenge the sanctity of this House without damaging its integrity. I speak very clearly out of a clean conscience that building this nation includes building of Manipur also.

If you do not want to build my State, then you have no right to govern it. What has happened to my State today? Who is responsible for that? I know you have imposed the President's Rule today. What has happened to the man who has been running the show for nearly two years? Is he behind bars? The least I expected was for an inquiry to be initiated because the whole world knows he is on tape speaking about how he initiated this entire crime. Is it not shameful that the head of the Executive of a State can execute such a gruesome crime and yet remain unscathed? I did not expect this, Mr. Chairperson. I have had more faith and hope in my Prime Minister and my Home Minister. Today, that faith is diminishing by the day. There is still time, and my conscience is clear. Believing in a law that is enshrined in our Constitution, believing in a nation that goes by the rules of law, not by appeasement, you do not have the right to bring in legislation whenever you choose if it is not for the people. Today, this Budget that I speak of is anti-people in Manipur. Why is it so? It is because you talk of the 60,000 who have been displaced today. All of their homes are ravaged, burnt, broken, and damaged. They are all displaced. There is no reflection in the Budget for those displaced. The damage I hear, which was done by separate entities, has crossed Rs. 20,000 crore. I do not see anything of that sort. The entire Budget is not even worth that.

Mr. Chairman, Sir, while my State may be a small State, we are not small people. We are also equal in every way to this nation. I would implore upon the conscience of this House again, about my rising to speak again and again, if it is not making sense to this August House. Give me the privilege, opinion, and opportunity to relinquish my seat and not come back here again. Do you know how it feels to come here and speak repeatedly without being heard, without being executed at the ground level? Do you know how painful that is to go

back to an empty home, to people in the streets who do not have any place to go? And today, you bring in a Budget that does not address a single part of those affected today. I wonder, my blame was solely on one person in the State. I had concentrated everything there. I had hoped for more from the leadership of my nation. I still hope for more from the leadership of my nation.

Mr. Chairperson Sir, before I close, I would like to say that this Constitution is sacred to each Member present here in this august House. I need not remind anybody. I have quoted the rule of law. It is a point of order that cannot be bypassed. The Budget has to clearly say about this. This is a notification of the Ministry of Home Affairs. Today, the State is being run by the Ministry of Home Affairs. The hill-valley section separation is mandatory. There is no separation of that. How would we know what is going to the hills and what is going to the valley? Nobody would know anything. And for that reason, I would request the hon. Finance Minister to put this off, bring in the actual Budget and the Demands for Grants so that we can go into the discussion of what is going into the hills and into the valley, and understand a little bit of the pain and hardships that the State is going through. I wish, hope and pray that we, in this House together can solve this problem. Thank you.

श्री शशांक मणि (देवरिया) : माननीय सभापति जी, प्रणाम देवरिया । मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ।

मैं आज इस सदन में आदरणीय निर्मला जी द्वारा कल प्रस्तुत किए गए वर्ष 2024-25 के दूसरे अतिरिक्त अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें 6 लाख 80 करोड़ रुपये की मांग की गई है जो 52 अनुदानों और 3 आबंटनों में विभाजित है । इसमें शुद्ध नकद बजट 51,000 करोड़ रुपये है जबकि बाकी की पूर्ति मंत्रालय द्वारा बचत या वृद्धि के माध्यम से होगी । यह कुल केंद्रीय बजट का 1.2 प्रतिशत है । मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के बजट में हमारा राजकोषीय घाटा 2.48 प्रतिशत तक सीमित रहेगा । आने वाले समय में भी 4.4 प्रतिशत तक सीमित रहेगा ।

इसके लिए मैं वित्त मंत्रालय को, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं । इस समय हम प्रधान मंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, सब के प्रयास के माध्यम से एक अनोखे रास्ते पर चल रहे हैं । भारत एक ऐसे विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जो पूरे विश्व के लिए स्मरणीय है । आज की तारीख में विश्व की वैश्विक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं । आज टैरिफ वार चल रही है । आज पर्यावरण की बहुत गहन चिंता हो रही है । आज युद्ध भी चल रहे हैं । लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में हमारे देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है । आज की तारीख में जब विश्व की औसतन जीडीपी की बढ़त 3.2 प्रतिशत है, हम लोग 6.5 प्रतिशत तक बढ़ रहे हैं । चीन भी करीब 4.5 प्रतिशत पर सीमित हो गया है और इसमें भी मैं समझता हूं कि कृत्रिम सिमुलेशन की एक आभा लग रही है ।

आदरणीय सभापति महोदय, इस तेज विकास के लिए, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की याद आती है, जिसमें हम लोग 6.5 प्रतिशत से बल्लेबाजी भी अच्छा कर रहे हैं और गेंदबाजी भी अच्छा कर रहे हैं । हमारी जो डेफिसिट है, हमने उसको कंट्रोल में रखा है । इस बहुत शानदार प्रदर्शन के लिए मैं अपने मुखिया, अपने कप्तान

आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं । यह तभी संभव हुआ, जब 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं । भारत में आने वाले 23 वर्षों में 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम लोग आगे लाभ लेंगे । हमारे लिए जो अगले 23 वर्ष हैं, प्रधान मंत्री जी के द्वारा विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी की 10 प्रतिशत हो जाएगी । यह बहुत अनोखा उदाहरण है । यह तभी संभव है, जब पूरा देश साथ उठा है । यह तभी संभव है, जब हम लोग सरकार के साथ, समाज, प्राइवेट सेक्टर, सब लोग साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग अपनी इस सरकार पर जो बोझ है, उसको कम करें । इस व्यवस्था के होते-होते यह सदन वह दिन देखेगा जब हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे । दिल्ली के परिणाम इसी का परिणाम है कि हम लोग सुचारू रूप से अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जा रहे हैं ।

महोदय, कुछ सप्ताह पहले प्रतिपक्ष के नेता ने एक विचार प्रकट किया । उन्होंने बजट की बहस के दौरान सरकार को बोला कि एक परिवर्तनकारी आर्थिक नैरेटिव की मांग होनी चाहिए । मैं उनको और कांग्रेस के अन्य नेताओं को बताना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक चश्मे हटाएं । आज की तारीख में विकसित भारत का संकल्प पूरे भारत में जो चल रहा है, वह देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक नैरेटिव है । अगले 23 साल में अगर हम लोग 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में और बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव किसी ने रखा ही नहीं है । ? (व्यवधान) मैं इनके चश्मे को समझता हूं, क्योंकि इन्होंने हर समय देश को एक ऐसे तरीके से देखा है, देश की जनसंख्या को इन्होंने पहले से ही दीन-हीन समझा है । जब से कांग्रेस की उत्पत्ति हुई तब से समाजवाद करते-करते इन्होंने हरेक व्यक्ति को दीन-हीन समझा । अंग्रेजी का एक वाक्यांश है । उसको मैं बताता हूं । ?Soft bigotry of low expectations.? इसका अर्थ होता है कि कम आकांक्षाओं से ही असहजता का प्रयास । यही कांग्रेस की नीति रही है । इसी के कारण नेहरू-गांधी परिवार ने संभ्रांतवाद की सोच करके कभी भी अपने हाथ को करुणा का चिह्न नहीं माना है । अपने हाथ से छीना-झपटी की है । मेरे ही प्रदेश में सपा की सरकार ने साइकिल का चिह्न लिया है और साइकिल से संपदा लेकर भागते रहते हैं । इन दोनों पार्टियों ने आर्थिक रूप से देश का शोषण किया है । इसके विपरीत भाजपा की सरकार, जिसका नेतृत्व आज आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम किया है, आम आदमी में विश्वास किया है । इसमें हमने सब के प्रयास से ही, सब की भागीदारी से ही सांस्कृतिक पहचान से स्वच्छ भारत का निर्माण किया है, जल जीवन मिशन लाएं, मंगलयान की लैंडिंग करवाई, राम मंदिर का निर्माण किया ।

आदरणीय प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता के माध्यम से कहा है । 15 अगस्त का दिन कहता है?

?आज़ादी अभी अधूरी है सपने सच होने बाक़ी हैं, राखी की शपथ न पूरी है ।?

आज महिला अधिनियम के माध्यम से राखी की शपथ भी पूरी हो रही है और उसी से प्रेरित होकर मैंने भी अपने क्षेत्र में एक अमृत प्रयास का नारा दिया है । मैंने आने वाले दस साल के लिए रणनीति निकाली है, जिसको मैं गांव-गांव ले जा रहा हूं । हमारे विधायकों के साथ, हमारे किसानों के साथ, हर व्यक्ति के साथ मिलकर यह रणनीति हमने अपने गिलहरी जैसे प्रयास के माध्यम से की है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पांच प्रमुख अनुदान की मांगों पर अपनी बात रखना चाहता हूं । इसमें भी सबके प्रयास की भावना सरकार की है, वह प्रस्तावित होती है । इसी के साथ-साथ, मैं देवरिया क्षेत्र जैसे इलाके, जो छोटे शहर-गांव हैं उनमें भी कैसे ये अनुदान प्रभावशील होंगे, मैं इसके बारे में भी वृत्तांत देना चाहता हूं ।

कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2,200 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है । इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 600 करोड़ रुपए का और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 570 करोड़ रुपए का अनुदान है, जो यह दिखाता है कि हमारी सरकार पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए बराबर खड़ी रही है । वर्ष 2024 के चुनाव में, जो इंडी गठबंधन ने झूठ फैलाया था, उसके मुंह पर यह प्रखर तमाचा है । संविधान के 75 वर्षगांठ में, मैं भी अपने क्षेत्र में सबके प्रयास से संविधान-यात्रा कर रहा हूं । हम लोग बस्ती- बस्ती जा रहे हैं, इस बात का खंडन कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

दूसरा, संचार मंत्रालय से 11,540 करोड़ रुपए का अनुदान है । यह छोटे और पिछड़े जिलों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है । इस अनुदान में 7000 करोड़ रुपए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए है, जो अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल सर्विसेज को ले जाएगा, डिजिटल कनेक्शन को ले जाएगा । यह प्रयास छोटे जिलों में नागरिकों को बाजार से और धन से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयोग है और अमृत प्रयास में मैं भी इसका प्रयोग कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, 1,400 महिलाओं को हमने डिजिटल के माध्यम से व्यापार में सम्मिलित किया है, जिनमें से कुछ एआई के माध्यम से डेटा एनोटेशन भी कर रही हैं और कुछ ने वीआर कंपनियां भी शुरू की हैं । इस अनुदान में मेरे क्षेत्र में डिजिटल उद्यमी- अंजलि निषाद, पुरोधा त्रिपाठी, ममता कुशवाहा को शक्ति मिलेगी ।

तीसरा, रक्षा मंत्रालय का 16,700 करोड़ का अनुदान है । इस क्षेत्र में मेरी ज्यादा रुचि है । मुझे बहुत खुशी है कि पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए इसमें काफी अनुदान दिया गया है । ईसीएचएस में 960 करोड़ रुपए का प्रावधान है इससे हमारे सैनिकों का उत्थान होगा । लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इससे हो रही है कि युद्ध-कर्म में कंप्यूटर उपकरण की खरीदी के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है । आप जानते हैं कि नॉन-काइनेटिक वारफेयर से आज की तारीख में पूरे वारफेयर का परिदृश्य बदल गया है । मैं समझता हूं कि इसमें और अनुदान की आवश्यकता है ।

मुझे यह बताते हुए ऊर्जा मिल रही है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में एक ड्रोन का क्लस्टर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय से हम लोग अनुदान लेंगे और इसी संदर्भ में, मैं सभा को और आपके माध्यम से, पूरे देश को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि यदि आने वाले समय में ड्रोन में यदि कोई बटालियन बने तो उसका नामकरण मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई के नाम से किया जाए क्योंकि पूर्वांचल के ये योद्धा, जिनको आज की तारीख में आधुनिक युद्ध से जोड़ा जाएगा, तो पूरे देश का सम्मान होगा, पूर्वांचल का सम्मान होगा ।

चौथा, शहरी विकास और आवास मंत्रालय के लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान है । इसमें मुझे बहुत खुशी है कि 590 करोड़ रुपए मेट्रो और छोटे-छोटे शहरों में मेट्रो स्टेशंस के लिए दिए गये हैं । मैं समझता हूं कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में भी, हम लोग देवारण्य के माध्यम शहरीकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसानों की मदद ली जा रही है, स्थानीय सरकार के निजी उद्योगों की मदद ली जा रही है । इसके लिए मैं भी चाहता हूं कि मंत्रालय हमारी सहायता करे ।

अंत में, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि डेट रिटायरमेंट का बहुत अनोखा और सकारात्मक संदेश है क्योंकि इसमें संभवत सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे बड़े अनुदान की मांग सरकार ने की है । इस मामले में सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का बायबैक किया है । इसमें मुख्यत: मार्केट सिक्योरिटीज और टी-बिलों

को खरीदा गया है । इससे न केवल सरकार पर ब्याज का बोझ कम होगा, बल्कि इससे बाजार में आर्थिक तरलता भी बढ़ेगी । बिलों और बांड्स से रिस्क प्रीमियम कम होगा । इस प्रीमियम को कम करने से पूरी अर्थव्यवस्था में कम ब्याज और लागत का लाभ मिलेगा । ये दोनों ही कदम, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बहुत शानदार कदम हैं । यह सरकार आज की ही नहीं, बल्कि दूर की बात भी सोचती है । इसीलिए इसने सुनिश्चित किया है कि जैसे-जैसे हम बढ़ें, हम आगामी वित्तीय चक्रों में भी अगली वाली पीढ़ियों पर भी अतिरिक्त बोझ न डालें ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सराहना करना चाहता हूं कि सबके प्रयास के संदर्भ में, गरीबों के लिए विशेषकर दलितों और पिछड़ों की सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है, जो इस अनुदान में परिलक्षित है । लेकिन अमृतकाल में, उभरते हुए मध्यवर्ग को सक्षम करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए भी इस अनुदान में धन की मांग की गई है । कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने स्वतंत्रता के 55 साल तक एक ऐसी मानसिकता का प्रदर्शन किया, जिसमें निर्भरता झलकती थी ।

माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत का एक विशाल सामूहिक प्रयास आज चल रहा है । यह बिल्कुल उसी तरह है, जैसे 1857 में पूर्वांचल से पहली स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ था, जिसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली ।

हमारे पूर्वांचल के मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झारखंड के बिरसा मुंडा, तमिलनाडु के वीरप्पन कट्टबोमन, कर्नाटक की रानी किट्टूर जैसे महानुभावों ने इसमें हिस्सा लिया था । 90 सालों के बाद वर्ष 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली । तब, महाराष्ट्र के तिलक, तमिलनाडु के चिदंबरम पिल्लई, पंजाब के लाला लाजपत राय, गुजरात के गांधी, बंगाल के सुभाष, यूपी के चंद्रशेखर, पंजाब के भगत सिंह ने इस राजनीतिक क्रांति में हिस्सा लिया था । आज की तारीख में हम लोगों को भी इस प्रकार की क्रांति में हिस्सा लेना पड़ेगा । हर वर्ग को, हर प्रांत को विकसित भारत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा ।

आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकात्म मानववाद के दर्शन के माध्यम से हमें इस ऊर्जा को आगे तेजी देनी पड़ेगी । जो छोटे शहरों और जिलों में हो रहा था, अब वहां मध्यम वर्ग भी रहता है । इसके लिए अमृत प्रयास का मेरा भी छोटा सा, गिलहरी जैसा प्रयास है । इसी को हर दिन, मैं जब उठता हूं, तो मेरी पीली पोशाक इसको चिन्हित करती है कि अगले 23 सालों तक हम इस संग्राम में उसी तरह भागीदारी करें, जैसे हमारे पूर्वजों ने की थी ।

सभापति महोदय, जय शंकर प्रसाद की एक कविता से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

?कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा,
किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया है ।?

आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ही नहीं, प्राइवेट सैक्टर ही नहीं, बल्कि पूरा समाज इस कर्म यज्ञ में पुरोहित बनने के लिए आगे बढ़ रहा है । इस अनुदान से उस कर्म यज्ञ की भाषा को हम लोग वेग देंगे । इसके लिए मैं पुन: वित्त मंत्री महोदया को और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

प्रणाम । जय हिंद ।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत मणिपुर राज्य के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुदानों तथा अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मणिपुर की जनता को खुरुमजरी करता हूं । फिलहाल मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है । फरवरी माह से वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के त्याग पत्र देने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । मेरा सरकार से आग्रह होगा कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था में बहाली तथा पुन: लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राज्य में निर्वाचित सरकार की स्थापना हो । राज्य की जनता की भी यही मंशा है ।

सभापति महोदय, मणिपुर के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 35,104 करोड़ रुपए का बजट आया है । यह राज्य के लिए काफी अच्छा बजट है । मणिपुर काफी संवेदनशील राज्य है । इसके बर्मा सीमा से लगे होने के कारण यहां घुसपैठियों का काफी जोर रहता है । राज्य में अशांति के मुख्य कारण भी यही घुसपैठिए हैं । सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसके व्यय के लिए 2,866 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । हिंसा के कारण प्रभावित, विस्थापित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए अस्थाई आवास के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है ।

इसी के साथ विस्थापितों के आवास के लिए 35 करोड़ रुपए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए और मुआवजे के लिए सात करोड़ रुपए दिए गए हैं । सामाजिक क्षेत्र में परिव्यय पर 9,520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार राज्य के विकास और वहां की स्थाई शांति व्यवस्था के लिए बजटीय प्रावधान काफी महत्वपूर्ण हैं ।

महोदय, मणिपुर में करीब दो वर्षों से जातीय हिंसा के कारण वहां के निवासियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी सभी को जानकारी है । मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं । मेरा यही आग्रह है कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम हो । वहां के निवासियों को पहले की तरह अमन-चैन मिले । सरकार दोनों समुदायों को एक टेबल पर बैठाकर बातचीत करे और शांति बहाल करने की अपील आज जनता से की जाए । यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंसा के दौरान अविश्वास पैदा हुआ है । उसे पाटने की आवश्यकता है । राज्य सरकार ने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, इस विषय पर चर्चा का वक्त नहीं है । आगे राज्य में शांति व्यवस्था के लिए वहां के सभी पक्षों के प्रतिनिधियों से बात करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं वहां रहा हूं और मेरा परिवार भी वहां रहता है । मैं वहां की स्थानीय समस्या से अवगत हूं । वह बहुत अच्छा प्रदेश है, मेरे ख्याल से पूरे देश में इस तरह का प्रदेश नहीं होगा, जितनी हरियाली वहां है । वहां के लोग बहुत अच्छे हैं । अत: मेरा यही सुझाव है कि सभी पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा एक साथ बैठकर समस्या का हल निकल जाएगा । वहां की जनता काफी समय से जो परेशानी झेल रही है, वह समझ सकती है ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक माँगों के जरिए 6,78,508 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्चे की मंजूरी भी की है । ये माँगें डिफेंस, कम्युनिकेशन, कृषि, वित्त एवं अन्य विभागों में समान बजट के अनुमानों के अतिरिक्त खर्च के लिए माँगों की मंजूरी है । आशा है कि यह कदम देश को आगे बढ़ाने और प्रगति के पथ पर भारत को विश्व में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्षम साबित होगा । देश की जनता को केन्द्र सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं । सरकार भी आम जनता की जरूरतों/अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है । देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूँ और

देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने वाला है । विश्व में भारत की अपनी एक पहचान है । माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारा देश उच्च स्थान पर पहुँचा है ।

महोदय, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने दूसरे कार्यकाल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सदन में काम करने का मौका मिला है । मैं बिहार राज्य से आता हूँ । मेरा राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है । आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त राशि प्रदान करने की दिशा में काम करेगी । विशेष राज्य के दर्जे की माँग भी लंबित है । उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है ।

महोदय, बिहार राज्य प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में रहता है । इसके लिए नेपाल सरकार से बात कर इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ?वह धर्म, धर्म नहीं है, जो पग-पग पर मजबूर करता है, वह धर्म, धर्म नहीं है, जो पग-पग पर मजबूर करता है, वह धर्म, धर्म नहीं है, जो आदमी को आदमी से दूर करता है ।? वही निर्णय हमारे मणिपुर के लिए लेना पड़ेगा और मणिपुर में शांति बहाल होगी । मैं इस सदन के माध्यम से यही गुजारिश करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Sir, there is a total gross additional expenditure of Rs. 6.7 lakh crore, of which the net cash outgo is almost Rs. 51,000 crore, with the rest being matched by savings, receipts, and recoveries.

Sir, I would like to begin by thanking our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, for their visionary governance. I would also like to express my gratitude for the steps taken to revive the construction of the futuristic city of Amaravati in the State of Andhra Pradesh, reviving the Vishakhapatnam Steel Plant, the creation of the South Coast Railway Zone, as well as the revival and completion of the Polavaram Irrigation Project.

Hon. Chairman, Sir, I have been elected from a backward area called Bapatla in Andhra Pradesh, from the Telugu Desam Party, under the visionary leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu ji. Bapatla has been carved out of the backward areas of the Prakasam district and the Guntur district, with an extremely low literacy rate of only 55 per cent. Therefore, Bapatla faces a multitude of challenges in development and welfare. To this end, I have constantly sought the inclusion of Bapatla under the Aspirational District Programme, and I am surprised to note that none of the blocks of the district are included in the 500 aspirational blocks of the country. I appeal through you, Sir, to NITI Aayog and the hon. Minister of Planning, that my district and the blocks be added to the Aspirational Districts.

Coming to the grants, I would first like to draw your attention to the Ministry of Housing and Urban Affairs. At the outset, I thank the Government for its generous support in building Amaravati, the capital city. The Ministry has seen a 0.73 per cent increase in its allocation by way of the present Supplementary Demand for Grants.

Out of this, Rs.5888.50 crore have been sought for metro projects. I urge the Central Government to allocate part of this to Visakhapatnam Metro Project and Vijayawada Metro Project for the benefit of the people living there.

Another important scheme that is closely linked to sustainable housing is the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana under the Ministry of New and Renewable Energy. Rs. 2,700 crores have been sought for this scheme under this Supplementary Demand for Grants. I applaud the Government's revolutionary initiative that aims at connecting one crore households with domestic solar rooftop facility by 2027. In this regard, I would like to request the Government to initiate a special drive to saturate the scheme in my constituency of Bapatla which receives solar radiation of around 5.35 kilowatt-hour per square metre. The provision of selling surplus power back to DISCOMs everywhere in the country will create additional income for households. However, solar rooftop panels require strong structural integrity which may not be available in *kutcha* houses. I would request the Government to ensure coordination between the Ministries concerned to give 100 per cent housing in the entire country so that this scheme can also be fruitfully implemented.

Second, I would like to emphasise the importance of skill development and the MSME sector in employment generation for the youths of India. India has always fostered a spirit of encouraging entrepreneurship. This has helped India in developing its MSME sector, evolving from traditional cottage industries to a vibrant ecosystem of over 63 million enterprises, driving innovation, employment, and economic growth. But this growth is not incidental. It was the result of a vision. The Modi Government recognizes the sector's potential, introduces policies, initiatives, and reforms to expand and nurture it. The 'Make in India' initiative and the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' have played a key role in promoting business and local manufacturing in the country, giving special thrust to MSMEs.

To ensure our growing industries have sufficient skilled human resources, there has been a renewed emphasis on skill development as well. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and the National Skill Development Mission have been instrumental in transforming the skill landscape of the entire country. I have consistently emphasised the need for a skill development centre in every block of my district to ensure that the youths are empowered with marketable skills and can play their part in achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. It is the manifestation of the classic proverb: "Teach a man to fish and you feed him for a

lifetime". In this regard, I would also request that a world class skill development centre be built in my constituency of Bapatla.

Third, I would shift my focus to rural development and the flagship scheme of MGNREGA. I would like to congratulate the Government on the successful operation of the scheme which is also reflected in the 8.3 per cent increase in demand under the scheme in December 2024 as compared to 2023. Providing employment opportunities to people is the first step in ending the vicious cycle of poverty, which has always been a priority of the NDA Government. This is laudable. I would also urge the Government to ensure that the increase in work demand is met with commensurate funds to ensure the fulfilment of the wage component of the scheme.

Fourth, on the issue of health, to ensure nobody is left behind, the Government has also been strategizing a unified platform and digital marketplace for insurance products so as to amp up penetration and provide health services to the remotest corners of the country. Furthermore, the pioneering initiative of Bima Sakhi Yojana will provide employment to two lakh women and each of them would earn a potential Rs.1.75 lakh per year bolstering their financial empowerment. The much-awaited Bima Sugam portal along with the Bima Sakhi Yojana will serve the twin purpose of employment generation and a 'Healthy India'.

Under the leadership of hon. PM Shri Modi Ji, India has also established itself as a global powerhouse in healthcare production, supplying 20 per cent of the world's generic medicines and 60 per cent of the vaccines. During the COVID-19 pandemic, India administered over 2.2 billion vaccine doses by 2022. This leadership underscores its robust pharmaceutical and biotech industries, reinforcing its position as the pharmacy of the world.

At the same time, I would like to draw the Government's attention to a few pressing areas. The out-of-pocket expenditure on healthcare, while decreasing in recent years to 39.4 per cent, is still considerably high for the common man. I implore the Government to ensure adequate funding for health programmes which people have reposed their trust in, such as the National Health Mission.

As I conclude, I would like to highlight that the people of Andhra Pradesh have given a historic mandate to the NDA Government led by Shri Nara Chandrababu Naidu Ji. Andhra Pradesh is the youngest State in the country having undergone bifurcation ten years ago, out of which, unfortunately, five years were wasted due to the incompetence of the last Government in the State. Now, it is time to push forward with a renewed commitment not only to recoup the losses of the past five years, but also set new examples of success. I am sure with the cooperation between the State Government and the Union Government, the dream of Viksit Bharat and Viksit Andhra is not too far away.

Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Thank you Speaker Sir. Manipur has become a riot prone land. Those responsible for changing Manipur to a riot hit State should find a solution for this issue. That is the natural way of finding solution. The ruling dispensation always claimed that if there is Double Engine Government, there will be growth and development is all those States. But I wish to remind you that Manipur has become an example for how the governance would fail if there is a Double Engine Sircar. Those who are responsible for this should also find the solution. Prime Minister has the political responsibility to bring harmony among the two Groups of people of Manipur.

I urge that Hon Prime Minister should directly intervene in this matter and bring peace and normalcy in the State of Manipur. I wish to remind that as regards the Supplementary Demands for Grants, that those in power have forgotten the people of this country. There is nothing in the interest of the people of this country. Everything is in the interest of corporates. There is a large gap between the poor people and the millionaires. Understanding this I urge that the corporate tax should be levied at the rate of 70 percent. Then only, this gap can be reduced a little bit and bridged. I urge that the Government should act on this. Similarly since the inception of the new economic policy in the year 1991, till now the Union Government should submit an X-ray report or White paper on the functioning of the two important sectors such as MSMEs and farming. Contract system of labourers should be abolished. There should not be any contract system of labourer for jobs of permanent nature. Why are you appointing persons on contract basis for jobs of permanent nature? This is a crime. This Government should understand this.

The Government should legislate a suitable law to abolish contract system of labourers or workers in all the departments. I have some demands to put before this Government. MPLADS funds which are meant for the MP Local Area Development. This is Rs 5 Crore for one Parliamentary constituency having six assembly segments. In Tamil Nadu, Hon Chief Minister of Tamil Nadu allocates Rs 3 Crore for one Assembly constituency. In that way, a Parliamentary constituency consisting of 6 Assembly Constituencies get Rs 18 Crore altogether. But our Union Government is allocating only Rs 5 Crore per parliamentary constituency. This is gross injustice. This amount should be enhanced.

I urge the Hon Finance Minister to announce the increase in MPLAD Funds from Rs 5 Crore to Rs 18 Crore per year. Hon Finance Minister also belongs to Tamil Nadu. Those who are in power are targeting Tamil Nadu in various ways. How did they forget to see this? You are showing different perspectives to us. Would they be removing this disparity and bring justice to the MPs as regards enhancement of MPLAD funds. I urge that Hon Finance Minister should clarify about this in her reply to the discussion.

The Union Government should accept and implement the Old Pension Scheme. As promised in the election manifesto released during elections, Old Pension Scheme should be implemented for all. Unified Pension Scheme is not required. I wish to say that there is no need for considering the Unified Pension Scheme. Tamil Nadu remains as an example for the entire country. From North India, especially from different States of North India unemployed labourers come in lakhs to places like Tiruppur, Coimbatore and Erode of Tamil Nadu in search of employment. As a result of this, the infrastructure of Tiruppur is totally disturbed.

I urge upon the Hon Finance Minister to announce a special package for Tiruppur which earns a lot of foreign exchange to our country. Thank you, Vanakkam.

16.00 hrs

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : सभापति जी, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद । सबसे पहले मैं मणिपुर बजट पर बोलना चाहता हूं ।

16.03 hrs (Kumari Selja *in the Chair*)

हम सबको पता है कि मणिपुर में पिछले पौने दो सालों से क्या हो रहा है । 35 हजार करोड़ रुपये का बजट है । वहां जितना नुकसान हुआ, तबाही हुई, लोगों के घर जले, दुकानें जली और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई । इस बजट में जो पैसे रखे गए हैं, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं । मैं सदन के सारे सदस्यों से विनती करता हूं कि आप सभी ध्यान दीजिए । 15 करोड़ रुपये टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, जबकि हजारों लोगों को सहायता की जरुरत है । सात करोड़ रुपये मुआवजे के लिए है । 35 करोड़ रुपये डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए हैं । अभी तक हजारों-लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए । बहुत सारी मौतें हुई । उनके घर जलाए गए । लोगों की दुकानें जल गई । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतने पैसे से काम हो जाएगा? केंद्र सरकार ने इसमें एक भी पैसा नहीं दिया । यह सारा पैसा मणिपुर का है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं । यहां वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं । कृपया करके 500 करोड़ रुपये तो आप अपनी तरफ से दे दीजिए । आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत दे दिया है । यह स्टेट बहुत तकलीफ में है । मणिपुर के बारे में मांग रखकर अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

सरकार का हक है कि वह सप्लीमेंट्री बजट ला सकती है । 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट तब है, जब नया बजट पेश हो चुका है । मैं केंद्र सरकार से इतना पूछना चाहता हूं कि सारा साल निकल गया, बजट एस्टीमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है, आपको सवा लाख करोड रुपए फरवरी, मार्च में ही याद आए । सारे साल आपकी क्या प्लानिंग थी? आपके सारे डिपार्टमेंट कुछ क्यों नहीं कर पाए? इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपकी मेजोरिटी है, आप इसे ले लेंगे । यह आपकी कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह फिर लगाता है । आप जितने डिपार्टमेंट्स के लिए मांग रहे हैं, उसकी लिस्ट मेरे पास है, जो बहुत लंबी-चौड़ी है । इसका मतलब इसको पहले नहीं देखा गया । इसको सीरियसली देखना चाहिए कि आखिरी वक्त पर 1 लाख, 2 लाख करोड़ रुपये न मांगे जाएं ।

यह बजट सैशन है, सप्लीमेंट्री डिमांड है तो आर्थिक नीति पर बात तो होगी ही । आपका 11वां साल पॉवर में कंटीन्युअस चल रहा है । यह वह सरकार है, जिसने हिंदुस्तान में गैर-बराबरी का, इनइक्वैलिटी का इतिहास बना दिया है । वर्ष 1947 से लेकर हिंदुस्तान में किसी चीज में भी इतनी गैर-बराबरी नहीं थी । गरीब, गरीब हो रहा है और अमीर, अमीर हो रहा है । 1.6 पर्सेंट पॉपुलेशन, सारे कॉरपोरेट से ज्यादा टैक्स दे रही है । यह इस सरकार की कार्य प्रणाली है । इनको इसका जवाब देना चाहिए कि 1.6 पर्सेंट पॉपुलेशन सारे कॉरपोरेट्स से ज्यादा टैक्स क्यों दे रही है? आप ऐसी क्या व्यवस्था बना रहे हैं कि जिसमें इतनी ना बराबरी हो रही है । इनके राज में इतने बिलेनियर्स जुड़े हैं कि कमाल हो गया है, पर पर-कैपिटा इनकम में हमारा 141वां नंबर है । अमीर तो अमीर हो गया, लेकिन जब आम आदमी की इंकम देखते हैं तो 2,540 डॉलर्स पर हैं । इंटरनेशनल लेवल पर हमारा 197 मुल्कों में 141वां नंबर है । आप क्या कर रहे हैं, मुल्क को किधर ले जा रहे हैं?

मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है । ग्रेजुएट्स, एमबीएज़ और इंजीनियर्स चपरासी की नौकरी के लिए लाइनों में खड़े हैं । आप मुल्क को किधर ले जा रहे हैं? भाषण जो मर्जी करो, वह ठीक है । हर आदमी को भाषण करने का अधिकार है । इतने पढ़े-लिखे लोग लाइनों में क्यों खड़े हैं? 80-90 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, तो मुल्क की तरक्की कहां है? आप रोज बताते हैं कि ग्रोथ हो रही है । यह ग्रोथ सिर्फ आर्गेनाइज्ड सैक्टर की है । आप अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर की ग्रोथ हमें नहीं दिखा रहे हैं । स्टेट मिनिस्टर आफ फाइनेंस यहां बैठे हुए हैं । जो जीडीपी ग्रोथ 6.4 पर्सेंट दिखा रहे हैं, क्या वह ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर की ग्रोथ नहीं है? आप हमें अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर की ग्रोथ बताइए । 90 पर्सेंट मजदूर इसमें शामिल हैं । आप उनके बारे में हमें कुछ बताते ही नहीं हैं । जो ई-श्रम पोर्टल है, उसमें 94 पर्सेंट लोगों ने कंप्यूटर पर अपनी जानकारी चढ़ाई है कि हमारी इनकम 10 हजार रुपये से कम है । यह मुल्क की तरक्की है । The net household savings as a percentage of GDP have been at the lowest level for a very long time. हाउसहोल्ड कंजप्शन पिछले 50-60 सालों में इतनी कम नहीं होगी, जितनी अभी है । यह आपकी इकोनामिक पॉलिसी है, जो मुल्क को पता नहीं कहां ले जा रही है, लेकिन भाषण बहुत अच्छे चल रहे हैं । जहां तक टैक्स बर्डेन है, वह आप जनता पर बढ़ा रहे हैं । आपने जीएसटी ऐसा बनाया है कि उसमें 50 पर्सेंट टैक्स गरीबों से आ रहा है । जो लोअर 50 पर्सेंट पॉपुलेशन है, उनसे यह आ रहा है । जो अमीर है, उनसे 10 से 15 पर्सेंट ही टैक्स आ रहा है । यह आपने कौन सा टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया है? जीएसटी ने एमएसएमई का काम तमाम कर दिया है । वे बेचारे रो रहे हैं ।

आपने कॉरपोरेट टैक्स पांच साल में आधा कर दिया, करीब-करीब दस लाख करोड़ रुपये छोड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने दस लाख करोड़ रुपये की रियायत दी है, उसकी वजह से कितनी नौकरियां आईं और कितनी नयी इन्वेस्टमेंट आयी । हमें सरकार से इसकी जानकारी चाहिए, आपने इतनी बड़ी रियायत दे दी, नौकरियां कितनी पैदा हुईं और इनवेस्टमेंट कितनी आईं । रोज विकसित भारत का भाषण हो रहा है, लेकिन आप उसकी डेफिनेशन नहीं बताते ।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप यह बताइए कि विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है? मेरे पास जो जानकारी है, डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन पर-कैपिटा इनकम 14 हजार 500 डॉलर एक आदमी की आमदनी हो तो उसे डेवपलप्ड मानते हैं । अभी अपना 2540 डॉलर है, अगले पांच सालों में 2540 डॉलर को कहां लेकर जाएंगे । आप विकसित भारत बोलिए, अच्छी बात है, फाइव ट्रिलियन डॉलर नहीं बीस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाइए, लेकिन अगर अमीर को अमीर होना है और गरीब को गरीब होना है तो फिर उसमें अपनी पॉलिसीज को देखिए । आपने बारह लाख रुपये का इनकम टैक्स रिलीफ दिया । मैं

उसकी कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत इंट्रेस्टिंग है । यह कहा गया कि हमने मिडल क्लास को बड़ा बोनानजा दे दिया, आपकी अपनी वेबसाइट पर 2023-24 पर इसकी जानकारी है, 7.54 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा, 5.89 करोड़ ने जीरो टैक्स दिया क्योंकि उनकी इनकम 7 लाख से कम थी । बारह लाख एग्जेम्पशन के लिए अब जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनकी संख्या 6.77 करोड़ है, 88 लाख लोगों को फायदा दिया, 35-40 करोड़ मिडल क्लास हैं, आपने अखबारों में छपवा दिया कि सारे फायदे मिडल क्लास को दे दिया, एक करोड़ से कम लोगों को आपने फायदा दिया ।

आप लोगों को ऐसे गुमराह क्यों करते हैं? जहां तक स्टेटों की हालत है, आपने स्टेट्स को जीएसटी में ले लिया, उन्होंने 48 परसेंट टैक्स छोड़े, आपने 22 परसेंट छोड़ा । आपने सेस और सरचार्ज लगाकर बीस परसेंट पूरा कर लिया, उनको इनकम टैक्स रिबेट दे दिया, कॉरपोरेट टैक्स रीबेट दे दिया, डिविजिबल पूल कम हो गया, उनका शेयर कम हो गया । जितनी आपने रियायतें दी हैं, आप रियायतें दीजिए, मिडल क्लास को दीजिए, कॉरपोरेट को दीजिए, लेकिन अपने पैसे से दीजिए, स्टेटों का पैसा न काटें, सारे स्टेट्स इस वक्त फाइनेन्शियल स्ट्रेस में हैं, उनको बहुत तकलीफ है ।

सारे सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट्स का बजट कम कर दिया, पिछले दो-तीन सालों से तुलना कीजिए । आप वेजेज नहीं बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर सेस कम नहीं कर रहे हैं, लोग कहां जाएंगे? एमपीलैड का पैसा क्यों नहीं बढ़ाते? वह हम सभी का है, एमपीलैड का पैसा बहुत साल पहले पांच करोड़ रुपये हुआ था, इसे दस-पन्द्रह करोड़ रुपये कीजिए । प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाइए । पच्चीस करोड़ रुपये कर दीजिए । अमेरिका हमें धमका रहा है, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए कि टैरिफ पर हमारी पॉलिसी क्या है? वित्त मंत्री जब जवाब दें तो इसके बारे में बता दें ।

सारा हिन्दुस्तान जानता है कि वर्ष 1960 और 1970 के दशक में बेगिंग बाऊल कहते थे, कटोरा लेकर दूसरे मुल्कों में गेहूं और चावल लेने के लिए जाते हैं । वहां के किसानों को कहा गया गेहूं और चावल पैदा करें । उन्होंने मेहनत करके हिन्दुस्तान को सक्षम बनाइए, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं । अब उनकी हालत क्या है, केन्द्र सरकार किसानों को एमएसपी देने को तैयार नहीं है । हरियाणा सरकार सड़कें रोक कर बैठी है, इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा दिया और केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी है । मेरी सरकार से विनती है कि हरियाणा सरकार से कहा जाए कि ब्लॉकेड हटाए, उसकी वजह से इंडस्ट्री वहां से छोड़ कर जा रही है ।

वे कह रहे हैं कि न कच्चा माल आता है और न हम सामान भेज सकते हैं तो पंजाब में रहकर क्या करना है ।

हमारा अंडर ग्राउंड वाटर बहुत डैमेज हुआ है । मेरी मांग है कि कृपा करके डायवर्सिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार हमें एक स्पेशल पैकेज दे दे । मैं बहुमत मिनिमम अमाउंट मांगता हूं । केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं । सरकार उनको दे, कोई बात नहीं है, लेकिन पंजाब को भी दे दीजिए । अगर हमें 15,000 करोड़ रुपये तीन-चार साल के लिए कैश क्रॉप्स और डायवर्सिफिकेशन के लिए दे देंगे तो पंजाब बच जाएगा । आप वहां मनरेगा का वेजेज भी बढ़ाइए ।

महोदया, मेरी कांस्टिट्यूएंसी में, एक तो हरियाणा में जो रोड ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से बहत कुछ डैमेज हो रहा है । मैं उसके लिए भी आपसे मांग करता हूं ।

दूसरा, जीएसटी की वजह से मंडी गोविन्दगढ़, खन्ना, दोराहा, साहनेवाल, मेरी कांस्टिट्यूएंसी की सारी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में है । यहां माननीय मंत्री चौधरी साहब बैठे हुए हैं । मंत्री जी वहां आप कोई अपनी टीम भेज दीजिए । मुझे कोई तकलीफ नहीं है । आप उनकी आवाज सुनिए कि उनको जीएसटी से क्या तकलीफ है । आप उसको शॉर्टआउट कर दीजिए । केंद्र सरकार ने उनको फोर्स किया है । वहां जितने भी स्टील मिल्स हैं, उनसे कहा गया कि आप जो कोयले से मिल और रोलिंग चलाते हैं, उसको बंद कीजिए । आप गैस पर आ जाइए । वे गैस पर चले गए । अब गैस के प्राइस इतने हाई हो गए हैं कि उनकी इंडस्ट्री नॉन वॉयबल हो गई है । वे उसको बंद कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी आप कृपा करके उन इंडस्ट्रीज को देखिए, नहीं तो सारी स्टील इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी ।

मेरी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएंसी में वर्ष 2018 में ?उड़ान स्कीम? के तहत हलबारा में एक एयरपोर्ट सैंक्शन किया गया था । अब सातवां साल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक वह एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ है । आप कृपा करके उसको शुरू करवा दीजिए ।

मैंने दोराहा में एक रेलवे ओवर ब्रिज के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वह भी शुरू नहीं हुआ है । मैं शुरू से कहता आया हूं कि मेरी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूएंसी श्री फतेहगढ़ साहिब एक पवित्र जगह है । वहां हमारे दसवें गुरु के छोटे साहबजादे की कुर्बानी हुई थी । आप कृपा करके वहां के लिए एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए । हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं । आप फतेहगढ़ साहब सरहिंद को 200-300 करोड़ रुपये दे दीजिए । आज छ: साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं दिया गया । आप कृपा करके इस पर विचार कीजिए ।

जो नेशनल हाइवे नम्बर वन है, माननीय सभापति जी, आप तो वहीं से आती हैं, अमृतसर से दिल्ली तक वह सबसे पहला नेशनल हाइवे बना था । इस वक्त सबसे खराब नेशनल हाइवे वही है । जगह-जगह ट्रेफिक जैम है, सड़क टूटी हुइ है, साइड रोड नहीं है और अंडर ब्रिज नहीं है । टाउन बड़े हो गए हैं । मंडी गोविंदगढ़, खन्ना के नीचे से निकलने की जगह नहीं है । कृपा करके उस पर भी कार्रवाई कीजिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SUSHRI SAYANI GHOSH (JADAVPUR): Namaskar, Madam. I thank you and my leader, Shrimati Mamata Banerjee for giving me an opportunity to speak today. After 22 months of demanding, protesting, criticising and shouting, this Government is finally compelled to discuss Manipur. But under what circumstance? It is when the democracy is officially dead in this State of this largest democratic country. They are forced to debate on Manipur today because the President?s Rule has been imposed in the State of Manipur.

महोदया, मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं । चर्चा न होने पर कभी हमने वॉकआउट किया तो कभी मकर द्वार पर धरना दिया । हमें सबसे ज्यादा उम्मीद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से थी, लेकिन उनके मन में न मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा न उनकी बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा । 600 दिनों से ऊपर वहां एथनिक वायलेंस चल रही है, जिसमें 240 से ऊपर मणिपुर के भाई-बहनों की मौत हो गई और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं । More than 5600 arms and 6.5 lakhs rounds of ammunition have been looted from police armouries. करीब 68,000 इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट्स और 13,000 ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज हुए हैं । कई लापता लोगों की डायरी और लगातार दहशत की खबरों के बावजूद सरकार ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी ।

Madam, in the past 22 months, every individual has been taken to the streets of Manipur, protesting and demanding peace. The apex student body of the North East staged a protest against the Prime Minister and the Home Minister for their failure to handle the crisis. The Indigenous Tribal Leader?s Forum and the Kuki Front organised a mass rally, alleging that the Central agencies were cherry-picking in order to appease the majority community at the expense of the minorities.

महोदया, कल तक मैतेई कम्युनिटी की महिलाओं ने प्रोस्टेट किया है और गृह मंत्री जी से अर्ज किया है कि आप वहां जाएं और मणिपुर में शांति लाएं ।

सभापति महोदया, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं । मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूं कि चाहे आप इस फैक्ट को पसंद करें या न करें, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है । More than 550 civil society organizations, retired bureaucrats, police officers, activists, lawyers, filmmakers, journalists, academics, writers, had to unitedly issue a public statement urging the hon. Prime Minister to speak out about the ongoing ethnic violence in Manipur. But, there was pin drop silence from the Prime Minister's end. जब वे पहली बार बोले, तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस पार्टी की तब की सरकार को कोसा था, जबकि मणिपुर में उन्हीं की पार्टी की डबल इंजन सरकार चल रही थी ।

Madam, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the Central Government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of the shameful incident of public humiliation of two tribal women that led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the State Government. Unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur citing reports of extrajudicial killing and sexual violence.? (*Interruptions*)

What is the point of discussing Manipur, Madam?? (*Interruptions*) What is the point of discussing the budget of Manipur? Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the State. Around 70 per cent of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 per cent to 12 per cent, the highest inflation among all States in the country. Youth employment in Manipur is at 23 per cent. ? (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदया, मणिपुर पर इसी सदन में बार-बार बातें रखी गई हैं ।?(व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : बातें नहीं रखी गई हैं ।

श्री नित्यानन्द राय : महोदया, बातें रखी गई हैं ।

सुश्री सयानी घोष : यह गलत बात है ।

श्री नित्यानन्द राय : महोदया, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में वहां की स्थिति को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा है । इस तरह का बयान देकर, गुमराह करके और अराजक स्थिति क्यों पैदा कर रही हैं, जबकि मणिपुर बिल्कुल शांति की ओर बढ़ चुका है । इस सदन में इस तरह से क्यों बोला जा रहा है?? (व्यवधान)

SUSHRI SAYANI GHOSH: Madam, the budget for healthcare was slashed by 23 per cent and 11.5 per cent, and the budget for education was slashed by 17 per cent and 5.6 per cent in the past two years. Also, the budget for nutrition has been cut by 25 per cent. Social security spending for tribal communities has seen a massive cut of 47 per cent. The price rise is bleeding every family dry, no matter what their ethnicity be. What has the Manipur Budget Demands for Grant proposed for reducing inflation and ease supply chain for the network of the State? Approximately 6,164 children between six months to six years, 2,638 adolescent girls, 232 pregnant women, 753 lactating mothers are currently living across 325 camps in Manipur. By April 2024, 554 babies were born in relief camps since the violence erupted, including two maternal deaths as per official data.

महोदया, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुराचांदपुर के एक रिलीफ कैंप में कभी ट्रॉमा, तो कभी कुपोषण और कभी बीमारी से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है । एक 36 साल के नौजवान ने एक रिलीफ कैंप में खुद की जान ले ली थी । Around 665 days of continuous conflict assaulted the well-being of 30 lakh people of Manipur. Youth have no future. Women and children are cramped in the relief camps. Elderly says that they have no hope for the future. आज पश्चिम बंगाल में एक मच्छर भी मरता है, तो बीजेपी वाले वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ऐसे चिल्लाते हैं । जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपकी ही सरकार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि ?जिंदगी धूप, तुम घना साया? ।

Madam, my question is, if the President?s Rule was the solution, why was it not being imposed months ago in Manipur? People were continuously dying, and after allowing Manipur to burn for months, today you are here offering bouquet of rosy promises.? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : आप किस नियम के तहत बोलना चाहते हैं?

डॉ. निशिकान्त दुबे: महोदया, नियम 66, 67 और 68 है । ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रही हैं, वह आईडेंटिकल बिल है, जो कि इस हाउस के पास है । राष्ट्रपति शासन पर डिस्कशन होने वाला है । इसीलिए इनको वित्त विधेयक पर केवल वित्त की ही बात करनी चाहिए ।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं ।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदया, राष्ट्रपति शासन पर बात होनी है । यहां वह बिल है ।?(व्यवधान) ऐसा नहीं होता है ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you please carry on.

? (*Interruptions*)

SUSHRI SAYANI GHOSH: Thank you, Madam.

After allowing Manipur to burn for months, today, you are here offering a bouquet of rosy promises. Please remember:

?फिर नहीं बसते वे दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब,
कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता ।?

Please remember this.

Madam, this was imposed not to restore peace in Manipur but to salvage the BJP?s political reputation after months of inaction. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने जनवरी, 2022 के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे हैं, लेकिन इस बीच चालीस बार इंटरनेशनल और 244 बार डॉमेस्टिक ट्रिप्स लगाई हैं । ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी सिर्फ दो बार गए, माननीय रक्षा मंत्री सिर्फ एक बार गए, माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसीडेंट तो गए ही नहीं । There is a saying called ?Nero fiddled while Rome burned?, अर्थात् आग लगी बस्ती में साहब अपनी मस्ती में । ? (व्यवधान)

मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, but why was not a second given to comfort the people of Manipur? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, are you yielding?

? (*Interruptions*)

SUSHRI SAYANI GHOSH: Please do not take it personally, Sir. ? (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: महोदया, यह सदन बिल्कुल असत्य की बुनियाद पर खड़े होकर बोलने का नहीं है । उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहां पर गए थे, तो प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करने के लिए गए थे । ? (व्यवधान) वह ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में गए थे, जहां इन लोगों ने जाने की कभी हिम्मत नहीं की थी । वही धरती गवाह है कि जब इन लोगों के राज में वहां हिंसा हुई थी, तो दस हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे । सदन को क्यों गुमराह किया जा रहा है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, भाषण नहीं ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you please carry on.

? (*Interruptions*)

SUSHRI SAYANI GHOSH: Madam, as per a release by the Home Ministry, it was said that the Ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest. उस ब्रिज का टेण्डर अभी तक पास नहीं हुआ है । The bridge has not yet been constructed.

Mr. Shah visited Manipur on 29th May, 2023 and constituted a Peace Committee under the Chairpersonship of Governor of Manipur but there has been no development since then. वहां बाद में यह देखा गया कि गवर्नर को जबरदस्ती हटा दिया गया, because she echoed the voice of the people of Manipur saying that मणिपुर के लोग दुखी हैं, मणिपुर के लोग अपसेट हैं । उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि प्रधानमंत्री एक बार आएं और उनसे मिलें । इसमें गलत बात कुछ नहीं है ।? (व्यवधान) Is this the reason why the Government always shies away from any discussion and debate? ?(*Interruptions*) The truth is that double engine ran over the people of Manipur. ?(*Interruptions*) Your double engine ran over the people of Manipur. ? (*Interruptions*) On the other hand, we have our Leader. जब कहीं कोई दुर्घटना घटती है, कहीं बस्ती में आग लगती है, जब कहीं आंधी आती है तो हमारी लीडर वहां खुद जाकर खड़ी हो जाती हैं । ? (व्यवधान) जहां पर वह खुद नहीं जा पाई, वहां पर उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वह हाथरस हो या लखीमपुर खीरी, चाहे वह सिंघु बॉर्डर हो या वायनाड या मणिपुर हो । वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं ।? (व्यवधान) हम गर्व के साथ बोलते हैं कि यह बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है, बीजेपी कटी पतंग है, ममता दीदी पूरा आसमान है । हम यह बोलते हैं ।? (व्यवधान)

मैडम, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि आप मणिपुर का बजट बनाएं, सप्लीमेंट्री बजट बनाएं और इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाएं ।? (व्यवधान) भारत में गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नेंस नहीं, बजट है, लेकिन बचत नहीं, खर्च है, लेकिन रोजगार नहीं, बाग है, लेकिन बहार नहीं । ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसी सरकार को हम पहचानते नहीं । ? (व्यवधान) आज माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए हैं । उनको हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं । एक तरफ मॉरिशस है, दूसरी तरफ मणिपुर है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैडम, हम आपसे रूलिंग चाहते हैं । ? (व्यवधान)

Madam, this is a gross abuse of the Chair?s indulgence. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No, Minister, you cannot point fingers at the Chair.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am sorry.

....(Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: She is exceeding the remit of her debate on the Appropriation Bill. *....(Interruptions)* She is abusing the indulgence that the Chair is showing to her. *....(Interruptions)* This is absolutely unacceptable. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Raju Bista ji.

....(Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: When an Appropriation Bill is discussed in this House, the rules have to be followed. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Raju Bista ji.

....(Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: Please give your ruling under Rule 218. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member is referring to Rule 218, which is related to the Appropriation Bill.

....(Interruptions)

DR. NISHIKANT DUBEY: Madam, this is the Manipur Appropriation Bill. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Raju Bista ji.

....(Interruptions)

माननीय सभापति : आपकी बात हो गयी है । आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गयी है ।

? (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । ? (व्यवधान) आपका मैं इसलिए भी आभारी रहूंगा कि टीएमसी की सांसद के बोलने के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।? (व्यवधान)

मैडम, वर्ष 2024-25 की जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रांट्स हैं और साथ ही वर्ष 2021-22 का जो एक्सेस ग्रांट है और मणिपुर का जो बजट है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं । मैं केन्द्र सरकार खासकर प्रधान मंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का बहुत आभारी हूं कि ये पश्चिम बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत स्नेह रखते हैं । इस बात को बजट के आंकड़े भी दर्शाते हैं । वर्ष 2010-11 में टैक्स के डेवल्यूशन का अमाउंट 15954 करोड़ रुपये मात्र होता था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 85000 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2024-25 में 96000 करोड़ रुपये हुआ और वर्ष 2025-26 के बजट में 1,60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यानी करीब-करीब 291 परसेंट का इंक्रीज है । इसी तरह ग्रांट इन एड पश्चिम बंगाल को वर्ष 2010-11 में 7800 करोड़ रुपये मात्र होता था जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 40 हजार करोड़ रुपये हो गया है । इसमें 303 परसेंट से ज्यादा का इंक्रीज है । मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, लेकिन मुझे यह बताते हुए तकलीफ भी है कि केंद्र सरकार जो पैसा पश्चिम बंगाल की दस करोड़ जनता को भेजती है, वह पैसा जनता तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमें जो मुख्यमंत्री मिली है, वह एक जादूगर है । जादूगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिली है, इसकी वजह से लाखों-करोड़ों रुपये जनता तक नहीं पहुंच पाता है । यह बात मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं । हमारी जो जादूगर मुख्यमंत्री हैं, हमारे पैसे कहां खाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा । मैडम, ये लोग गरीब टी गार्डन श्रमिकों की जमीन खा गए । टी गार्डन में काम करने वाले पांच लाख से ज्यादा काम करने वाले आदिवासियों के बोनस का पैसा भी ये खा गए । सिंकोना बागान को अंग्रेजों ने प्लांटेशन के लिए लगाया था, जहां मेडिसिन बनती थीं, उसको टीएमसी सरकार पूरी तरह से खा गयी ।

ये लोग चिट फंड घोटाले का पैसा भी खाते हैं । टीचर्स अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का पैसा भी खाते हैं । नदी, बालू और हमारे जंगल भी ये लोग खा गए । इतना ही नहीं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जल जीवन मिशन का पानी ये लोग पी गए । बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा ये लोग खा गए । इतना ही नहीं मनरेगा का पैसा जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भेजा गया था, इन्होंने बांग्लादेशियों को दे दिया । इन्होंने राशन का घोटाला किया । डिजास्टर का 1200 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार के बजट का पैसा भी ये लोग खा गए । इतना ही नहीं कोयले में भी ये लोग चोरी करते हैं और कोयले का पैसा भी खा जाते हैं । यह इतनी जादूगर वाली सरकार पश्चिम बंगाल का है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं । अभी पश्चिम बंगाल विधान सभा में बजट पास हुआ और 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा गया । उसी बजट में टी गार्डन को लेकर, टी गार्डन के वर्कर्स की 30 परसेंट जमीन नॉन-टी पर्पज के लिए और टी टूरिज्म के लिए डायवर्ट करने का प्रावधान ममता दीदी की सरकार ने किया । मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं और दार्जिलिंग तराई डुअर्स की जनता इसका विरोध करती है । इस कारण हमारे मूल आदिवासी जैसे गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, टोटो, मेच, राभा, बंग्लाभाषी, हिंदीभाषी जो मूल निवासी हैं, उन पर सीधा आघात है । इतना ही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 का भी यह उल्लंघन करती है । अनुच्छेद-39 के बी और सी सैक्शन का भी यह उल्लंघन करती है । इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल का खुद का लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 का यह सरकार उल्लंघन करती है । इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल स्टेट एक्युजिशन एक्ट 1953 का भी यह वायलेशन करती है । टी एक्ट 1953 के अंतर्गत टी बोर्ड और मंत्रालय से परमिशन न लेकर कभी भी आप लेन को डायवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये उसका भी उल्लंघन करते हैं ।

महोदया, इस जमीन के असली मालिक हमारे श्रमिक माता-पिता और भाई-बहन हैं । मैं आपको इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं । दार्जिलिंग तराई डुअर्स का क्षेत्र वर्ष 1861 से लेकर 1870 तक रेग्युलेटेड एरिया होता था । वर्ष 1870 से लेकर वर्ष 1874 तक यह नॉन रेग्युलेटेड क्षेत्र होता था । वर्ष 1874 से वर्ष 1919 तक यह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट होता था । वर्ष 1919 से लेकर वर्ष 1935 तक डेको ट्रैक होता था । वर्ष 1935 से वर्ष 1947 तक पार्शियली एस्कुलिरेट एरिया होता था । नॉर्थ-ईस्ट के जितने भी प्रदेशों में यह प्रावधान था, आगे चलकर सारे क्षेत्र अलग-अलग राज्य या यूटी बने, लेकिन वर्ष 1954 एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत हमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया । यह इतिहास मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ताकि आप इसकी जानकारी रखें ।

महोदया, पश्चिम बंगाल हमारी जमीन की मालिक नहीं, मात्र केयर टेकर है । मालिक हमारे श्रमिक हैं । मैं इस सदन से टीएमसी को बताना चाहूंगा कि एक और आंदोलन का आमंत्रण आप कृपया न दें । हमारे साथ अन्याय हुआ है । हमने बार-बार भारत सरकार से यह मांग की है कि हमारे साथ न्याय हो । भारतीय संविधान के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई और डुअर्स की जनता को न्याय मिलना चाहिए । ?जल जीवन मिशन? नाम से बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार ने लाँच किया है । मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में सात सौ चौदह प्रोजेक्ट्स के लिए 2,450 करोड़ रुपये, यानी पश्चिम बंगाल के केवल एक जिले को भारत सरकार ने ?जल जीवन मिशन? के तहत दिया है । इस मिशन का नाम था हर घर जल, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर यह हर घर नल हो गया, क्योंकि नल तो लग गए हैं, लेकिन पानी उनमें है ही नहीं । आंकड़ों में 54 प्रतिशत हाउस होल्ड्स को इन्होंने टैप वाटर से जोड़ा । ऐसा कागजों में है, लेकिन 20 परसेंट काम भी नहीं हुआ है । जल जीवन मिशन का सारा पानी भी टीएमसी सरकार पी गई । हाल ही में केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के थ्रू ऑडिट किया था । मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे हिस्से के पानी का जो पैसा है,

वह हमारी जनता को मिले तथा जिस कांट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार किया है, उसे जेल में डाला जाए । अमृत-1 के बाद अमृत-2 स्कीम के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र या म्यूनिसिपैलिटी एरियाज हैं, जैसे दार्जिलिंग, कालिंपोंग, मिरिक और सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन को भारत सरकार की तरफ से दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिला । अभी इसमें टेंडर नहीं हुआ । यह प्रक्रिया में है, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि टेंडर होने से पहले ही 10 परसेंट कमीशन में टीएमसी सरकार टेंडर बेच चुकी है ।

माननीय सभापति : आप कृपया मणिपुर पर आइए ।

श्री राजू बिष्ट : जी मैडम, मेरी तो जन्मभूमि है, मैं उस पर आता हूं । डिजास्टर का पैसा हर साल बारह सौ करोड़ रुपये केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को देती है । हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर, 2023 में सिक्किम में जो बाढ़ आई थी, उसके कारण कालिंपोंग, दार्जिलिंग के करीब पांच सौ लोगों के घर बह गए हैं । हमारे भी घर बह गए ।

इतने साल होने के बावजूद भी डिजास्टर बजट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की सरकार को सालाना 1200 करोड़ रुपये मिलते हैं, लेकिन आज तक हमारी जनता को कुछ नहीं मिला है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक जिले में, स्पेसिफिक सिर्फ दार्जिलिंग का 1200 करोड़ रुपये में से जो हिस्सा है, वह हमें नहीं मिल रहा है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप मणिपुर के विषय पर आइए ।

श्री राजू बिष्ट : सभापति महोदया, इसी तरह से मैं रेल मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूँ । रेलवे के अलग-अलग 45 प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को 4,660 किलोमीटर्स के लिए 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट का आवंटन किया गया है और 101 से ज्यादा अमृत स्टेशन्स बन रहे हैं । वर्ष 2014 से लेकर अभी तक साढ़े चार सौ से ज्यादा फ्लाई ओवर्स और आरओबीज़ पश्चिम बंगाल में बने हैं । बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए मोदी जी की सरकार ने हमें 1600 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसका काम भी ऑलरेडी चालू हो चुका है । इसी तरह से हाइवेज़ और रोड्स का काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था । वर्ष 2014 के बाद वह हम सबको देखने को मिला है । ? (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (**अम्बेडकर नगर**): सभापति महोदया, अभी माननीय निशिकान्त दुबे जी नियम 216 का उदाहरण दे रहे थे कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा, जिनसे वे बने हों । जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी । यानी मूल बजट की इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, केवल अनुदान की मांगों पर ही चर्चा होगी ।

सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अनुदानों की मांग या अनुपूरक मांग पर एक शब्द भी नहीं बोला है । उन्होंने जो कुछ बोला है, वह मूल बजट पर बोला है या पश्चिम बंगाल के बजट पर बोला है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): Madam, thank you for permitting me to take part in this very important discussion.

I am here to express certain deep concerns with regard to our national economy. When we think of economy and when we discuss about problems facing the economy, we have to identify the place of the disabled identities throughout the world in the process of development, especially in our country. The goal of social justice will not be achieved without inclusion of the persons with disability. This Government is failing utterly in all the spheres of development.

The words ?pichada?, ?dalit? and ?alpasankhyak?, that is the backward, dalits and minorities are very important when we think of the sidelined and the marginalised sections of our society. But the Government is presenting a good picture away from reality.

?आप ही की तरह खूबसूरत बहुत,
आप ही की तरह बेवफा जिंदगी ।?

This is the picture now-a-days with regard to the weaker sections and the backward sections of the community. There are no steps taken to solve their problems. As a poet said ?कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती ।?

After discussing all these things, the Government is not coming forward with any concrete policy for the upliftment of minorities and backward sections of the society. Growth will be possible only in an atmosphere of social peace and peaceful co-existence.

No growth will be possible in the social scenario of discord, disharmony, friction, and strife. That is the lesson of Manipur, and we are again and again reminded of this lesson. Whether it is in Manipur or any other State in the country, we need programmes for alleviating distress.

Madam, where are we now approaching in the age of Artificial Intelligence? Artificial Intelligence has to be taken very seriously into consideration, along with the problems created by it when we discuss our present condition of the economy. Economic discrimination has to be fought with tools of social justice embedded in economic justice. In the age of Artificial Intelligence, we have to take into consideration the technological risks confronting us. Excessive dependence on digital networks will be highly dangerous.

?रेश्मी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी कि गावा और हवा ने हमको नंगा कर दिया ।?

This is the condition when the wave of Artificial Intelligence is coming. The truth itself becomes the casualty. The real risk is the deep fake syndrome that is facing modern society. Everything has become mechanical. Life itself is going on becoming mechanical. The signature of the present society, the present humanity, is that humans behave like machines and machines work like human beings. But whatever may be this condition, we cannot hide the picture.

?हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से

खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से ।?

That is what I have to remind the Government also. Most of our people will not be able to reach the arena of progress. Most of our people will be marooned in the slow lines, not able to seize the opportunities offered by Artificial Intelligence, data science, robotics, and FinTech.

?जिंदगी उसकी है, जो उसे झेल ले

सबको देती नहीं आसरा जिंदगी ।?

So, I would like to emphasize the point that these tools, these new measures will not be accessible for a large section of our society. The sectors and the tools are not native for crores of people. I have to bring to the notice of the House the situation of ASHA workers. It has already been brought to the notice when we discussed the economic condition of the country. Ten lakhs of ASHA workers across India are playing a crucial role in health care, community health awareness, immunization, and so on. Despite their indispensable contribution, ASHA workers remain among the most underpaid and overworked sections of India's public health workforce, with no fixed salary. Their social security is limited and recognition is inadequate. ASHA workers are not classified as Government employees, but as volunteers. Even this word 'volunteer' is a kind of injustice in the case of ASHA workers that allows the State to deny their minimum wages, gratuity, and other employment and retirement benefits. There is gross injustice that continues to be done against ASHA workers, which has to be undone urgently. So, I seek a clarification from the Government on whether it will be willing to remunerate ASHA workers with a full-time salary, which is routine in the case of Government services throughout the country. The political ideologies and programme strategies have to be reformed and remoulded, aiming at the welfare of the weaker sections. Bridging the digital divide is important, but more than that, Madam, the divide between ?haves? and ?have-nots? has to be solved. It should not be like that. The poet said:

?एक समुन्द्र ने आवाज दी, मुझे पानी पिला दीजिए ।?

It should not be like that. Thank you.

माननीय सभापति : आप भी शायरी कहना चाहते हैं ।

श्री पीयूष गोयल : मैडम, मैं अब्दुस्समद जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी में अपनी बात को यहां रखा है, शालीनता से अपनी बात को यहां रखा है और एक प्रकार से दिखाया है कि भारत एकता

और एकजुटता का प्रतीक है ।

केरल के मुस्लिम लीग के माननीय सांसद ने इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग किया । ऐसे ही शशि थरूर जी, शफी भाई, सब लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप भी तमिल में बोल सकते हैं ।

? (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं । भाषा के नाम पर लोग राजनीति करते हैं ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister can also speak in Tamil.

? (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल : मैडम, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों की बात है । अब तमिलनाडु में भी तामरै वेल्लुम, कमल का फूल खिलने वाला है । हम तमिल में भी बात करेंगे, बड़े आदर से बात करेंगे ।

माननीय सभापति : श्री एस. वेंकटेशन ।

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Madam Chairperson, Vanakkam. Hon. Minister who intervened and spoke before me said that opposing Hindi is equivalent to opposing India. I wish to emphasize to the hon. Minister that opposing the imposition of Hindi is equivalent to strengthening of India. India is not Hindia. India is in treating all languages of our country with equality. We insist to you to show importance in providing funds to education similar to the importance you show to Kasi Tamil Sangamam. If you do not understand this, you cannot understand the importance of mother tongue or the significance of education. It is a part of modern fascism when you attack on the federalism of our country. We wish to quote from your reports. NITI Aayog?s report says that Tamil Nadu remains on top among the States of this country in eradication of poverty. Your Economic Survey says that Tamil Nadu remains on top among all other States as regards human resource development. Your report further says that Tamil Nadu is in first place in the textile exports of the country. From Higher Education to Public Health, Tamil Nadu remains in the forefront. Against a tax revenue of Rs. 1 paid by Tamil Nadu, the Union Government pays back only 29 paise to Tamil Nadu. What an injustice is this? You pay back Rs. 7 to Bihar as against Rs. 1 paid by them as tax revenue. You are paying Rs. 1 and 75 paise to Uttar Pradesh as against a tax revenue of Rs. 1 paid from that State. When we ask our rightful share, you make false allegations against us. You are making an open attack on federalism on all fronts including education, finance and governance. You make States to bow before you by depriving them of finances. If they refuse to bow before you, then you address them as uncivilized. You take back the words which you uttered in this House. If that is so, it shows the way how you used such uncivilized words. We want to ask you whether you have understood now the gravity of the matter. We

wish to ask you that even after you took back the words you uttered here, a Union Minister while speaking in Tamil Nadu supports such usage. Is that the civilized way of life that you wish to portray? Director of an IIT in our country, which comes under the Ministry of Education, asks us to drink Cow urine. You do not dare to ask him how civilized is this? If we ask funds for our educational projects, you are asking whether we are civilized. America had sent back hand-cuffed Indians who migrated to their country illegally. You did not show angry towards America. But you have shown your strength against the Anantha Vikatan Magazine which published a cartoon condemning America. Manipur is on the boil for the last three years. Prime Minister did not visit Manipur at least once. You are placing this Manipur?s Budget in this august House where you have the Prime Minister as a Member. Is this the civilized way you are preaching to us? We have 543 members of Parliament in this Lok Sabha. Whereas we have 848 seats in this newly built House. This is a conspiracy of the Union Government against the interests of the southern States of our country. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu and all the political parties of the State are all one side against you on this issue. We are determined to uphold the federalism of our country against the denial of rightful dues to the southern States of our country. The Budget presented by you is taxing more on the MSMEs and providing tax relief to the corporates. This one liner can explain how faulty your tax system is. Similarly, MGNREGA. Union Government has not released the instalment dues of MGNREGA for the last 3 months. Payments to the tune of Rs. 121 crore is delayed by the Union Government which is due to the labourers of Madurai. We want to place before this august House this accusation against Prime Minister and Finance Minister of this country. Today our Education Minister of the Union says that only when Tamil Nadu follows the New Educational Policy, Rs. 2500 crore that is due for educational projects in Tamil Nadu would be released. Those in power at the centre think that they can make us bow before them due to denial of funds. I wish to say they will fail in making us to bow before them as Tamil society is filled with self-dignity and rationale nature which will teach them a lesson for sure. You are not superior as you are is the place of giving. And we are not inferior as we are in the place of receiving. Tamil Nadu will time and again prove the fact that there is no one superior to the Constitution of India.

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Hon Madam Chairperson, Vanakkam. For the first time in this august House, I stand to speak in my mother tongue Tamil. A sister among the seven sisters of the North East is on the boil. This sister State is on the boil for more than last one and half years. This has not fallen on the deaf ears of those in power in Delhi. Since 3 May, 2023, the State of Manipur is on fire. The violent clashes between Meitei and Kuki Groups have spread throughout the State as it ended in riots. More than 250 people were burnt alive besides 60 thousand people have become refugees in their own State of our country. Schools have been damaged and churches were demolished. Many of their belongings have been badly

damaged. More than 15 lakh students have lost their education. Is it not necessary for the Prime Minister to remain in this august House at the time such an important discussion is taking place? Thousands of weapons have been looted from the weapon depot which is under the control of the Ministry of Home Affairs in the presence of our armed forces. Hon Prime Minister was witnessing this as a mute spectator. But PM proclaims himself as a Chowkidar wherever he goes. Is it not a funny thing? When you cannot protect your arms depot, how will you protect the common people of this country? In what way the people of this country hope that they are protected? Prime Minister is so inclined to find a solution to Ukraine issue by holding talks with the Ukrainian leaders. Are you not having inclination to find solution to the problem faced by a small State of our country? Is he feeling insecure? I urge that the Union Government should clarify on this. Where are those BJP leaders who time and again insisted on Double Engine Government for the focussed development of a particular State? Whether their voices have list significance? Is this the way of functioning of Double Engine Government in our country? Or else whether the double engine has become faulty? When we analyse as to why Manipur is on fire, we get only one answer for this issue. This is the political calculation of BJP. Prime Minister goes swiftly and attends functions organised by corporate giants without fail. But PM has no inclination to go to Manipur. I want you to clarify as to why does he prefer not to go to Manipur? Why is he not instilling confidence in the minds of the people of Manipur? BJP, for its political gains, has spearheaded this attack on the Kuki people of Manipur. That is why it has not taken any measure to bring down violence in the State of Manipur. We cannot forget that it has become a question mark on the administrative efficiency of the Union Government. Women and children were the most affected persons in these violent incidents of Manipur.

Hon. Chairperson, women are excelling in every field. They are acquiring Degrees and legislating laws of the country. At this juncture, Kuki women were paraded naked and were subjected to gang rape. This video created shocks in the world. To which civilized society does it belong to?

Hon. Chairperson, yesterday hon. Minister of Education called the MPs of Tamil Nadu as ... * Whether this is your civilized behaviour? I think that you need not teach us about civilization. Tamils have taught the entire world of what civilization is. Tamils engaged in trade by crossing the geographical barriers. Every place in the world is ours and every human being our kith and kin. I wish to say with happiness that this is the saying in Tamil which is adding pride to the life of Tamils. Researches prove that Tamils were the ones to first use iron as a metal 5000 years ago. Moreover, there were groups of people who shout louder about women?s protection. Where have they gone? Because there is no protection for women. There is increase in number of sexual harassment incidents against women.

Women are unable to roam freely outside. They shout like this. But they will shout only when any untoward things happen in the Non-BJP ruled States. I want to ask them whether Manipur is not in India. Or otherwise you have not considered the women of Manipur as your sisters. Or otherwise they are not women in your thought. I want that the Union Government should answer to these questions. Intrusion, drug-trafficking are some of the reasons cited to justify the attack of Kuki Groups in Manipur. If the Union Government is really concerned about the intrusion, it would have sealed the Indo-Myanmar border. It should have acted against the intruders. I wish to point that the Union Government has failed in that front as well.

Madam Chairperson, there goes a saying in Tamil. ?You can test the whole pot of rice by just testing one piece of it?. Similarly, Manipur riots can be explained to us how inefficient this Union Government is in administration. The Chief Minister of that State resigns from that post owing to his inability to control riots in Manipur. The State is now under President?s Rule. You are unable to contain violence in one particular State. How can you protect the entire country? I now come to Demands for Grants pertaining to Manipur. Only 2.2 per cent is the increased allocation for education in that State. This is a meagre amount. Only 0.2 per cent is the increase in allocation for health sector of Manipur. Manipur is State which is backward in terms of health facilities. They have reduced the funds meant for tourism by 79.4 per cent. This will impact the economy of that State. There is a 17.7 per cent reduction of funds meant for relief and disaster management department. Labour and Employment department has seen a reduced allocation of 23.8 per cent. This will be detrimental in providing employment opportunities. Reduction of funds stands at 29.8 percent as regards Department of Food and Consumer Affairs. For agriculture, the fund allocation is reduced by 5.1 percent.

This will further deteriorate the condition of farmers. BJP Government has allocated very less amount of funds to Education, Health and Agriculture sectors. It shows the negligence of the Union Government in protecting the interests of the people of Manipur. Let us now see about the schemes of the Union Government. They have reduced the allocation to Samagra Shiksha Scheme by 1.5 per cent. Scholarships for OBC students have seen a reduction of 22.9 per cent. National Food Security Scheme has witnessed a reduction of 23.7 per cent. For Jal Jeevan Mission, the fund allocation is reduced by 48.3 per cent. For the city monitoring scheme of crimes against women under the Nirbhaya Fund, the allocation has seen a drastic reduction of 45.5 percent. At a time when we need more funds for providing protection for women and at a time when Nirbhaya funds were not utilized fully, the reduction made is unforgivable. It is a matter of concern as well.

Hon. Chairperson, I can say with pride that hon. Chief Minister of Tamil Nadu as a pioneer in India has celebrated women?s day as part of Government celebrations. As regards upliftment of women and for ensuring their protection, Tamil Nadu remains a role model for the entire country. This is our Dravidian Model of Government. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu is the head of our Dravidian Model of our Government. Dr. Kalaignar Women?s Entitlement Scheme giving monthly assistance, Puthumaippen Scheme, Women?s Hostels for their safety, Breakfast scheme for students, free Bus pass Scheme for women are some of the Schemes continuously implemented by hon. Chief Minister of Tamil Nadu in the footsteps of *Muthamizh Arignar* Dr. Kalaignar. But it is painful to say that the Union Government has reduced the allocation of PM- AJAY Scheme, meant for the socio-economic development of the people belonging to Scheduled Castes, by 36.2 percent. What is plan of Union Government for the future of Manipur? What are the measures proposed to be undertaken by the Union Government for restoration of peace and ensuring harmony in Manipur? I want the Union Government to explain the measures taken by the Union Government as regards providing livelihood, education and protection to the people of the State of Manipur. The people of Manipur are waiting for getting justice. One sister State among the seven sisters is waiting with hope that the Union Government will put off the fire in that burning State. I urge upon the Union Government, through Hon Chairperson, to expedite restoring peace and normalcy in the State of Manipur. Thank you. Victory to Tamil.

17.00 hrs

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Thank you, Madam Chairperson.

First of all, this Budget should have been discussed on the Floor of the State Assembly. The fact that it has been brought to the Parliament House, tells you about the anomaly. This is not a regular thing that the State Budget is discussed on the Floor of the House here.

But there is a story about why this Budget is here and what does this Budget speak of. First of all, it speaks of the exclusions and the contemptuous nature in which the present Government has dealt with the State of Manipur. The number will speak the measures that are reflected in the Budget.

We have talked a lot about Prime Minister not visiting the State. Initially, at the beginning of the crisis in 2023, I was heard that the Prime Minister did not visit the State. Today, I am almost indifferent. Whether he visits the State or not, it does not matter anymore. But the rest of the country should know that there is no visa issue for the Prime Minister to visit the country. He may go to Ukraine and talk about peace when his own citizens have been slaughtered and more than 60,000 people have been rendered homeless. This kind of a behaviour can never be justified by anybody who swears by nationalism. It can only be done

by those who swear by pseudo-nationalism and who has a peculiar idea of a nation that thrives on excluding the people.

Let me talk about this Budget in two ways. What do these numbers speak of? The first one is a clear sense of the state of economy of this State called Manipur. Look at the fiscal liabilities. It is 37.07 per cent of the GSDP. What does it speak of? It speaks of a terrible State of an economy, the debt burden that the State witnesses.

Look at the revenue expenditure. Out of 61 per cent, roughly around 45 per cent goes to salaries and pensions. Look at the capital expenditure. It is 39 per cent. What kind of a development project or development of the State that you can sense from these numbers?

Or, for that matter, you look at this non-tax revenue component ? one per cent. I thought that this Budget would have schemes to deal with these basic economic anomalies of the State. For instance, I was trying to look for additional or diversification of the additional sources for the non-tax revenue of the State. No, we do not have that image here. I thought that there would be measures to deal with this debt burden. There is nothing of that kind. This is a normal aspect of any Budget that you expect this budget to reflect but we do not have. But over and above this, you have this crisis for 21 months. Does that Budget reflect anything on that? No. Nothing of that kind. How do you expect that kind of economy of a State to deal with this crisis without the help of the Centre? We are not asking for UN interventions. We are not asking for international financial institution to help Manipur. We are asking for additional source of money from the federal Government as a constituent State of India. We do not get anything. How do we deal with this 60,000 people who are rendered homeless? Villages are wiped out. Women and children are suffering. Children are not able to go to school. Had this crisis been there in Bihar or UP, you would have felt the nation in you for you to reflect on your Budget. This is the kind of exclusions that I have been trying to bring in this House.

Remember that Gandhi was thrown out of the train. How did he feel? He thought that he was a Barrister. He thought he is entitled to that compartment in the train. He was thrown out of that.

Bankim Chandra Chattopadhyay, when he was told that India does not have history, that sense of invisibility is what this Government has been doing. Nothing of this has been mentioned in your Presidential Speech. You have been trying to make us invisible. Our tragedy is insignificant and you expect the people of this State to feel like any other Indians and be proud of being an Indian. People have begun to start asking questions about the relationship between our State and the Union of India. People are remembering instrument of accession. People are remembering that controversial agreement. Why? It is because you

have allowed the feeling to be groomed like that. And this Budget is an addition to that series of actions that you have conducted.

I will give one more example which I felt as I sat in this House and listened. I have seen floods in my home State. Even the Raj Bhavan was inundated. Every year, it has become a ritual. Did the Budget reflect anything on that in the national Budget? Does it reflect in this Budget as well? Nothing of that kind. आपने 11,500 करोड़ रुपये बिहार को क्यों दिए थे? It is because Bihar is more Indian than Manipur. You said that you will try to help the State of Assam and Himachal Pradesh for the floods. Nothing has been said about Manipur. Ask your Governor. How that Raj Bhavan was inundated? Was it a foreign country? Or even if it was an Ambassador?s house, you would have invested. This is the State Governor under the Union of India. You do not bother and you expect us to feel normal, being included.

Madam Chairperson, I am representing a voice. I have taught generations in this country from Kanyakumari to Kashmir and from Gujarat to Nagaland. For 30 plus years, I have seen this. And do you think this is normal that we, as people?s representatives, in this House will continuously go through this kind of insults? This Budget is the same story that I have been witnessing.

What do we do now? What can I expect from this Government? What they will end up by doing is -- though this is a Budget Estimate that they are projecting for 2025-2026 -- at the end of the day, they will say and I am aware of it that this is a Vote on Account and 50 per cent of it has been approved. It is like a ritual and you will finish it off. Manipur is not even addressed and the ritual will be completed in a couple of days.

Is this how the largest temple of democracy indulging itself? I am ashamed of myself to bring up these issues. It is not a joke. When thousands of people suffer, I expect this Government to have some sensitivity and pump in a little more money and talk openly. If we have made a mistake, let us accept it. This is not about BJP or Congress. Let us move forward. Let us try to have this feeling that we are one, that you care for us, and this Budget must reflect that. It should not be a simple ritual to continue this insult and then blame the people for anti-India feeling been emerging in that space. Remember that anti-India feeling emerged in Manipur unlike anywhere in this country because of the continuous follies of the State Government and the Government of this country.

None other than the retired Home Secretary of the Union Government has said that Manipuris have been insulted and the only way to move forward is ... * That insult continues even today. This Budget is not taking care of the IDPs, not taking care of the basic needs of that economy, not taking care of the floods, and it has become a ritual. Do you think that it is going to be another ritual to pass on this floor of the House?

It is very saddening, Madam Chairperson. I hope sooner we learn this and make corrective measures. I am only wishing that one day we will be able to say that we are all Indians and we feel the same feeling as everybody else. Thank you.

डॉ. भोला सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदया, आपने मुझे मणिपुर राज्य के लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभांवित करने का काम किया है । इसके साथ-साथ उनकी जीवन-यापन की जो आवश्यकताएं थीं, उनको पूरा करने के लिए निरंतर पिछले दस सालों में आपने देखा कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है । इसी का परिणाम है कि पिछले दस सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं । यह बहुत बड़ा कार्य गरीब कल्याण के लिए किया गया है । जिस व्यक्ति को आवास की आवश्यकता है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के गरीबों को 4 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री आवास देने का काम किया है । इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2.99 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1.19 करोड़ आवास हैं । कुल 4 करोड़ से अधिक आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है । आगामी पांच साल में 3 करोड़ नए प्रधान मंत्री आवास बनेंगे, यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । जिस गरीब को आवास की आवश्यकता है, उसे आवास दिया है, जिसे इलाज की आवश्यकता है, उसके लिए प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से देश का गरीब बीमारी में अच्छे से इलाज करा सकता है, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है और पिछले दस सालों में 12 करोड़ 37 लाख से अधिक परिवारों को प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला है ।

सभापति महोदया, जहां वर्ष 2014 से पहले, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से आता हूं और मैं देखता था कि जब गैस के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती थी, तो गैस सिलेंडर के लिए लोग रात को ही लाइन में लग जाते थे । इसके बाद भी उनको यह गारंटी नहीं होती थी कि उन्हें गैस सिलेंडर मिले । आज सबको गैस तो मिल ही रही है, इसके साथ-साथ साढ़े दस करोड़ से अधिक परिवारों को सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिया है । मैं बुलंदशहर से आता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के जो लोग लाइन में लगते थे, उनकी रसोई में आज पाइप लाइन के द्वारा गैस पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

सभापति महोदया, ग्रामीण इलाकों में हमारी जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, उनको हमारी सरकार ने शौचालय दे कर एक बहुत बड़ी सुविधा देने का काम किया है । हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है । हर व्यक्ति को पानी देने का काम किया है । इसके साथ-साथ जो इस देश का युवा वर्ग है, उसके कल्याण के लिए सरकार ने काम किया है । जहां वर्ष 2014 में 1219 करोड़ का बजट सरकारें ले कर आती थीं, आज वर्ष 2024 में 3794 करोड़ रुपये का बजट हमारी सरकार युवाओं के कल्याण के लिए ले कर आई है । जो महत्वपूर्ण कार्य युवाओं की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने किए हैं, उनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इस देश के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा हुए, जहां पर वर्ष 2014 में मात्र 16 आईआईटी होते थे, आज वर्ष 2024 में उनकी संख्या 23 हुई है । वर्ष 2014 में मात्र 13 आईआईएम होते थे, आज उनकी संख्या 21 हुई है । वर्ष 2014 में सात एम्स होते थे, आज उनकी संख्या 23 हो गई है । वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 731 पहुंचाई है । अभी जो बजट हमारी सरकार का आया है, इसमें युवाओं के लिए 50 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब

बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । वहीं सभी सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए भारतनेट योजना के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है ।

दूसरा, किसानों के कल्याण के लिए निरंतर माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि देश के अन्नदाता की आय दोगुनी होनी चाहिए । आय दोगुनी तब होगी जब उसको फसल में लगने वाले आय की मात्रा में कमी आएगी, पैदावार बढ़ेगी और उसका अच्छा रेट किसानों को मिलेगा । किसान कल्याण के लिए, हमारी सरकार ने देश के सभी अन्नदाओं के लिए किसान सम्मान निधि देने का प्रावधान रखा है, जिसमें आज नौ करोड़ 80 लाख किसानों को 22 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है । इसके साथ-साथ खाद, बीज और जो यूरिया की उपलब्धता की किल्लत पहले किसानों के सामने रहती थी, उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है । प्रत्येक किसान को अच्छी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है । किसान अपनी फैसल की पैदावार को अच्छे स्थानों पर बेच सकें, इसके लिए ई-नाम मंडी प्रत्येक जनपद में बना कर किसानों को एक अच्छा प्लेटफार्म हमारी सरकार ने दिया है । सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अभी जो हमारा बजट आया है, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को तीन लाख रुपये से बढ़ा कर पांच लाख रुपये तक करने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

महोदया, मैं आपके माध्मय से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ । जैसे पूरे देश में चार करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री आवास बने । अभी जो प्रधान मंत्री आवास की गाइडलाइन है, उसमें प्रावधान है कि जिसका कच्चा घर है, उसको मकान देने की योजना है । लेकिन मेरे क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी होगा कि कुछ ऐसे मकान बने हैं, जहां पर ईंटे लगी हुई हैं, लेकिन छतें कच्ची हैं, या वे टीन शेड से पटी हुई हैं । मेरा आपके माध्यम से हमारी सरकार से निवेदन है कि उन मकानों को भी प्रधान मंत्री आवास की योजना की गाइडलाइन में जोड़ा जाए । दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद बुलंदशहर के लिए दो-तीन मांगें हैं कि मेरे यहां पर एक रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है । रिंग रोड के लिए पहले से एक प्रस्ताव है और डीपीआर भी सरकार ने तैयार कर लिया है । वह अति शीघ्रता से बन जाए, यह मेरा निवेदन है । दूसरा, चूंकि बुलंदशहर यहां से बहुत नज़दीक है, वहां पर रेलवे की डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी दिल्ली और लखनऊ के लिए नहीं है । लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसके साथ-साथ हमारा हाई कोर्ट प्रयागराज में पड़ता है, वहां के लिए रेल की व्यवस्था की जानी चाहिए । हमारे जो धार्मिक स्थल हमारे अयोध्या और काशी विश्वनाथ वाराणसी में हैं, इसके लिए मैंने रेल मंत्री जी से भी आग्रह किया था, एक बार पुन: आग्रह करता हूँ कि बुलंदशहर से अलीगढ़ होते हुए लखनऊ की जो लाइन है, उस पर मेरे जिले का एक चोला स्टेशन है, उस स्टेशन पर एक नया स्टॉपेज बना कर ट्रेनें रोकने की व्यवस्था की जाए ।

सभापति महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय है । अभी हमारी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए बहुत काम किया है । हम निरंतर देख रहे हैं कि कैंसर के मरीजों में वृद्धि हो रही है । उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद में डे-केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ मंत्री जी को बधाई देता हूँ ।

एक आग्रह करता हूँ कि मेरा क्षेत्र दिल्ली के बहुत नज़दीक है और मेरे क्षेत्र से बहुत से मरीज़ इलाज के लिए एम्स में आते हैं । इसलिए एक तो डे-केयर सेंटर बुलंदशहर में 200 बेड्स का सेंटर बनाने का निर्णय इस सत्र में लिया है तो इसको इसी में बना दें । ऐसा मैं निवेदन करता हूँ ।

धन्यवाद

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, आपने मुझे मणिपुर के अनुपूरक अनुदान की मांग पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदया, आज मैं इस सदन में भारी मन और उलझे हुए विचारों के साथ कहना चाहता हूं । मणिपुर की त्रासदी पर सरकार की चौंकाने वाली चुप्पी और उदासीनता के कारण ही मणिपुर की यह स्थिति हुई है । मणिपुर के लिए 35,104 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया । निश्चित तौर पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है । अभी मणिपुर के हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि मणिपुर की त्रासदी में हजारों लोग घर से बेघर हो गए । आज भी तकरीबन 351 राहत शिविरों में 58,357 लोग रह रहे हैं । इसमें तकरीबन 22 हजार बच्चे हैं ।

महोदया, मणिपुर में 70 परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है । वहां धान की खेत जला दिए गए । बाजार नष्ट हो चुके हैं । इसको आप किस प्रकार से पुनर्स्थापित करेंगे? इसके लिए कोई ठोस नीति इस बजट में नहीं दिख रही है । बेघर हुए लोगों और जो बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

महोदया, मैं सदन में जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मणिपुर त्रासदी के तकरीबन 20-21 महीने हो गए । इंटरनेशनल स्तर की एक-दो मीडिया ने कहा कि भारत के मणिपुर में एक काला अध्याय लिखा गया और वहां एक तरह से नरसंहार हुआ है । वहां पर दोषी कौन है? जब आपको वहां सरकार बनाना होता है तो आपके पास जाने के लिए टाइम रहता है और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । वहां पर जब इस तरह की त्रासदी हो रही थी तो वहां जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं था । आप सभी इवेंट्स में जा रहे थे । माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां जाने के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला । यह चौंकाने वाली बात है । मणिपुर हमारे देश में है ।

महोदया, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । ? (व्यवधान) अभी तो एक-दो मिनट ही हुए हैं ।

माननीय सभापति : हम हर माननीय सदस्य को सिर्फ पांच मिनट दे पाएंगे । अगर आप विषय पर ही बोलें तो बेहतर होगा ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदया, पांच मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा । अभी हमारे बिहार में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है । जिस तरह से जुमले की बात इस सदन में रखी जाती है, उसी तरह का जुमला बिहार के विधान सभा में भी चालू हो गया है । अभी बिहार का तीन लाख सोलह हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया । हमें तो लगता है कि ये लोग सपने की फैक्ट्री दिखा रहे हैं । उन्होंने 358 नए डिग्री कॉलेज खोलने का एलान किया । आप डिग्री कॉलेज खोल लेंगे, लेकिन पहले से ही जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें शिक्षक ही नहीं हैं । अब आप 358 डिग्री कॉलेज खोल कर क्या करेंगे? मैं औरंगाबाद जिले से आता हूं । मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं ।

तकरीबन 100 से 150 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो दूसरी जगह स्थानांतरित हैं । दूसरी जगह पर उनका समायोजन करके आप उन्हें चलाने का काम कर रहे हैं । यह किस तरह की बात है? छात्र हमारे यहां आज भी बाहर पढ़ने को मजबूर हैं । आप अगर रियल में बिहार के हित की बात करते हैं और बिहार के लिए सोचते हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 17 महीने के शासन काल में एक इतिहास रचने का काम किया और पटना के गांधी मैदान में 2 लाख 43 हजार नियुक्ति-पत्र बांटे । मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य में इतने नियुक्ति-पत्र एक

बार में बांटने का काम नहीं किया गया । मुख्य मंत्री जी हमेशा विशेष राज्य की बात करते रहते हैं । अब किस बात की देरी है? आप सत्ता में हैं । आप विशेष राज्य की दर्जा लीजिए । आप अगर इस बार विशेष राज्य का दर्जा लेने में कामयाब नहीं होंगे तो मैं इस सदन के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2025 में बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और एक बढ़िया सबक सिखाने का काम करेगी ।

आज हमारे बिहार के लोग, चाहे युवा हों, किसान हों, छात्र हों, नौजवान हों, हमारी मां-बहनें हैं, सभी आशा भरी नजरों से भाई तेजस्वी जी की ओर देख रही हैं । निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आने वाले समय में अब जुमले का बोलबाला खत्म होगा और जो काम करेगा, जो मुद्दे की बात करेगा, वही बिहार पर और देश पर राज करेगा ।

इसी सदन में एक प्रश्न पर मैंने माननीय एनएच मंत्री जी से एनएच 139 को फोर लेन करने के बारे में प्रश्न पूछा । उन्होंने जवाब दिया कि उसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन किसी प्रकार के डीपीआर का निर्माण एनएच 139 के निर्माण के लिए नहीं किया जा रहा है । इस तरह का ?* सदन में वह भी माननीय मंत्री जी के द्वारा बोला जाना, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत है ।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, ?* शब्द अनपार्लियामेंट्री है । इसको डिलीट कर दिया जाए ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, Chairperson, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Budget.

The Polavaram Project is the lifeline for the State of Andhra Pradesh. It plays a crucial role in irrigation, water security and regional development. It deeply concerns the State of Andhra Pradesh that the height of the dam is getting reduced from 45.72 metres to 41.15 metres. That would have a severe impact on the storage, reducing it to 115 TMC from 194 TMC. This will have a huge impact on the irrigation of about 7.5 lakh acres of land, drinking water supply and hydroelectric power generation also. Therefore, the YSR Congress Party demands that the Central Government must honour the commitments made during the time of State's bifurcation and uphold the original height of the dam and storage capacity to secure the project's long-term benefits.

Then, there is a big uncertainty in the project funding and the execution cost. The current cost has been escalated to Rs.30,436.95 crore. Yet we see a huge gap between the allocation of funds under the Union Budget and the execution cost. The sanctioned budget of Rs.5,936 crore, which is only 20 per cent of the cost, is insufficient to meet the project completion deadline.

Having said that, if the project?s budget has such a difference, the people of Andhra Pradesh are having the following doubts. If the project cost further shoots up, will the Central Government still be in agreement to pay the shot up cost? Who is going to bear the amount? Is the Central Government going to bear the difference amount?

Chairperson Madam, the Central Government must prioritize Polavaram and provide appropriate funding to prevent cost overruns and delays. I have one more demand. The Central Government must immediately shift the Polavaram Project Authority CEO?s office to Andhra Pradesh. It will enhance efficiency, accountability, and execution speed.

The YSR Congress Government under the leadership of YS Jagan Mohan Reddy *garu* had undertaken a revolutionary initiative by securing approval for 17 new Government medical colleges, five of which were successfully established, adding over 2,550 MBBS seats. This was done with a well-structured financial plan, ensuring accessibility for poor and middle-class students. Even though sufficient infrastructure is there, the National Medical Commission withdrew permission for Dr. YSR Government Medical College at Pulivendula, citing lack of infrastructure after receiving a letter from the Director of Medical Education. It has happened for the first time in the country. On behalf of the YSR Congress Party, we demand not to privatise these 17 medical colleges.

Thirdly, Vizag Steel plant is also put into jeopardy, impacting 14,000 contract workers, out of whom 3,600 have cancelled passes. The people of Andhra Pradesh have a straight question in their mind whether the steel plant will be privatized or not? Will we be getting captive mines or not? Can we please expect a straight answer to this question?

Fourthly, as outlined in Part XII, 13th Schedule, Section 93, Infrastructure and Special Economic Measures of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the Government of India committed to the development of a new major port at Dugarajapatnam in the Tirupati parliamentary segment and establishing an integrated steel plant in YSR Kadapa district. Despite this provision, the project?s initiation has not yet commenced. As mentioned in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, the Special Category Status for Andhra Pradesh was promised. However, in the 2025-26 Union Budget also, there is neither an allocation nor even a mention of Special Category Status for Andhra Pradesh. This is not just a broken promise; it is a betrayal of Andhra Pradesh?s rightful demand. As the Central Government is set to provide Rs. 15,000 crore as a loan through multilateral agencies, who will be responsible for repaying the loan amount ? the Central Government or the State Government?

Thank you, Madam.

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदया, मैं मणिपुर के बजट और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मणिपुर के ऊपर मुझे दो बातें कहनी है । यहां वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जो को बोलने नहीं दिया । उस दिन के नारों को आप याद कीजिए । मणिपुर पर दो मिनट के लिये प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए तैयार नहीं थे ।

हम नारा लगा रहे थे । यहां विप्लव दास जी बोल रहे थे कि मणिपुर की आबादी ही कितनी है, वह कितना छोटा प्रदेश है, लेकिन हमारे लिए यह सवाल नहीं है, हमारे लिए सवाल यह है कि इस देश का छोटे से छोटे प्रदेश भी अगर उपेक्षा महसूस करेगा तो इंडिया गठबंधन को वह तकलीफ देगा । हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यहां पर खड़े हैं । इसलिए, हमने उस पर विरोध किया था । यहां दो घंटे की मेहनत से हमें अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य सभा में पंद्रह सेकेंड बोले । एक बात तो हमें यह बोलना है ।

दूसरी बात यह है कि मणिपुर में आपने जो बजट दिया है, उसका इस्तेमाल शांति, भाईचारा और एकता के लिए होना चाहिए । आप एथनिक वॉयलेंस को बढ़ाकर नार्थ-ईस्ट की मिलिटेंसी को रोकने की रणनीति पर न चलें । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सदन में एक बात की चर्चा नहीं हुई है । एक बार असम पुलिस और मिजोरम की पुलिस के बीच में गोली चली । उसमें असम पुलिस के पाँच जवान मारे गए थे । ऐसा लग रहा था कि दो देशों के बीच में गोली चल रही है, जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी । कहीं क्षेत्र के आधार पर, यहां पर अभी हिन्दी बनाम तमिल करके भाषा के आधार पर मतभेद करने की रणनीति ठीक नहीं है । यह क्षणिक तौर पर देश में अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए और संविधान सम्मत राज्य के लिए उचित नहीं है । इस पर सत्ताधारी दल को और उसकी सरकार को विचार करना चाहिए ।

मैं आगे अनुपूरक मांगों पर अपनी बात रखना चाहता हूं । सबसे बड़ा सवाल है कि आप कृषि को लाभकारी बनाइए । खेती घाटे में है और किसान कर्ज में डूबकर आज भी आत्महत्या कर रहे हैं । बटाईदारों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, जबकि 70 परसेंट खेती उन्होंने ही संभाल रखी है । आप उन पर ध्यान दीजिए । आप चालाकी मत कीजिए । सी-2 प्लस 50 परसेंट फार्मूला के आधार पर स्वामिनाथन कमीशन ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए कहा है कि कुल लागत का ड्योढ़ा दाम देने की गारंटी दीजिए । देश की आबादी बढ़ रही है । हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गए हैं । खेती की जमीन घट रही है । आप कृषि योग्य भूमि को बचाइए । लगातार इसका अधिग्रहण हो रहा है । आज के मार्केट रेट पर जिन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, उसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है । इस अन्यायपूर्ण कदम को रोकने के लिए बजट में अनुपूरक मांग रखते हैं तो उसमें प्रावधान कीजिए । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यहां बार-बार कहा है कि बिहार को बहुत मिला है । क्या आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है? क्या आपने वहां की गरीबी मिटाने के लिए कोई उपाय किए? क्या वहां बाढ़-सुखाड़ के स्थायी निदान की जो बात है, उसके लिए कोई घोषणा की है? क्या आपने बिहार में ऐसी परियोजनाओं को ताकत देने की बात की जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? आज से नहीं, सैंकड़ों वर्षों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से मगध का क्षेत्र, जिसका 600 साल का भारत का इतिहास है, उसमें आपने कोई योगदान दिया है? आपने इंद्रपुरी जलाशय बनाया? सोन नहर प्रणाली एक जिंदा नहर प्रणाली है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि को ताकत मिलती है, उसके लिए आपने कुछ भी पैसा दिया? उसके लिए कोई कार्रवाई की? इन सब प्रश्नों का जवाब ना है ।

महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना बारूण-बिहटा रेलवे लाइन है, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है । मनमोहन सिंह जी के जमाने में उसकी स्वीकृति मिली थी और उस पर सर्वे भी हुआ था ।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । आज यह डेवलपमेंट वर्क हमारे पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, धरती के तापमान को बढ़ा रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस को खत्म कर रहा है । हजारीबाग में ?बढ़ता गाँव? एक प्रखंड है, जहां बहुत अच्छी खेती होती है । उसके बगल में पहाड़ है, पहाड़ पर जंगल है, जंगलों में जंगली जानवर हैं, चिड़ियां आदि सब कुछ हैं । नदियों में बहता हुआ साफ पानी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि उसकी धरती के नीचे कोयला है और अदानी ने एग्रीमेंट कर लिया है । किसान वर्षों से वहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है । खदानें खुलेंगी और वह साफ हवा, साफ पानी, चिड़ियाँ, जंगल, खेती, सारी खूबसूरत चीजें खत्म हो जाएंगी ।

मेरा यह भी कहना है कि इसी गर्मी में बिहार में 62 लोग लू लगने से मर गए ।

यदि आप विकास की कोई रणनीति बना रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखना होगा । नहीं तो, यह सवाल उठ रहा है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं ।

अंत में, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि क्या आपको इस धरती पर ही रहना है, या किसी दूसरी जगह कोई योजना बनाई है? अगर कोई योजना नहीं बनाई है, तो इस धरती को अनुकूल बनाकर रखिए, ताकि मजदूर-किसान यहां रह सकें ।?(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति जी, मेरी तबियत ठीक नहीं है, फिर भी मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा । एक तरफ ड्रग्स का आतंक है और दूसरी तरफ हमारा देश संवैधानिक आतंक से जूझ रहा है । मैं आपको दलाल स्ट्रीट की ओर ले जाना चाहूंगा । फरवरी माह में शेयर बाजार में 40.80 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । जनवरी माह में 17.93 लाख करोड़ रुपये, दिसंबर माह में 4.73 लाख करोड़ रुपये, नवंबर माह में 1.97 लाख करोड़ रुपये और अक्टूबर माह में 29.73 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । यह दलाल स्ट्रीट का मामला है ।

दूसरा, पीएसयूज़ हैं । 25 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं, जिसमें एलआईसी के तीन लाख करोड़ रुपये हैं, एसबीआई के 1.6 लाख करोड़ रुपये और 1.5 लाख करोड़ रुपये हैं । एचएएल के एक लाख करोड रुपये हैं और एनटीपीसी का एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । यदि आप अनुदानों की अनुपूरक मांगें 2024-25 को देखेंगे, तो वर्ष 2025 भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति 4.31 प्रतिशत गिर गई है । यदि हम मुख्य रूप से खाद्य कीमतों की गिरावट की बात करें, तो वर्ष 2024 में 6.2 प्रतिशत बनाम 8.4 प्रतिशत हुआ है । भारतीय उपभोक्ता मूल टोकरी का लगभग आधा हिस्सा बनाती है, जैसे सब्जियां हैं । नरम मुद्रास्फीति 11.35 प्रतिशत बनाम 26.56 प्रतिशत है । ईंधन और प्रकाश के लिए अपस्फीति माइनस 138 प्रतिशत बनाम 1.39 प्रतिशत बनी रही और मुद्रास्फीति 2.76 प्रतिशत बनाम 2.71 प्रतिशत तक स्थिर रही है ।

अब आप मुझे एक बात बताइए । हमारे नेता कह रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यूक्रेन जाते हैं । मैं पूरे नॉर्थ-ईस्ट की बात कर रहा हूं । मैं मणिपुर गया था । मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा है कि दो सालों से लगातार दो समुदायों के बीच गोली चल रही है । वहां गोली जरूर चल रही है, लेकिन गोली चलाने वाला भारत के उस पार कोई माफिया है, जो ड्रग्स की सप्लाई करता है । उस ड्रग्स में जितने लोग शामिल हैं, यदि मैं उनके नाम की गिनती करा दूं, तो पूरे के पूरे मणिपुर का झगड़ा ड्रग्स को लेकर है । भारत के कई पदाधिकारी और कई सामाजिक व्यवस्थाओं के लोग इसमें शामिल हैं । यह कोई छोटी घटना नहीं है ।

पहली घटना यह है कि अपनी ही सरकार को अपदस्थ करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और वहां पुलिस फोर्सेज़ के द्वारा गोली चलवाई गई । अभी तक वहां गोली चल रही है । 10,000 लोगों के बीच जिस तरीके से महिलाओं को नंगा करके सामूहिक बलात्कार किया गया है, देश सिर्फ इसलिए चुप रहा, क्योंकि वह हिन्दी पट्टी में नहीं है । कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है । हम इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांट रहे है । हम इस देश को जात-पात, सिख, दलित, मराठा इत्यादि में बांट रहे हैं । इस देश को एक नहीं देख सकते हैं । इसमें बजट की जो स्थिति है, मैंने आपको पहले ही बताया है ।

महोदया, मैं एक और बात कहना चाहूंगा ।?(व्यवधान) मैं सिर्फ बिहार की तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा । मैं बेरोजगारी भत्ते की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । आज लगभग 30 करोड़ बच्चियां और बेटे बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं । इस हिन्दुस्तान कि सियासत के बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है ।

मैडम, दूसरी तरफ किसानों की बात आती है तो किसान कितने हैं । एक बीघा से पांच बीघा जमीन वाले मात्र 10.1 प्रतिशत लोग हैं और मात्र 3.2 प्रतिशत लोग 5 से 10 बीघा वाले हैं । उसके बाद टोटल बट्टेदार हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं । ये किसे फसल बीमा योजना दे रहे हैं? आप किसान और बट्टेदार को क्यों नहीं लाते हैं, आप बंधुआ मजदूर को क्यों नहीं लाते हैं? ? (व्यवधान) रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है । सबसे बड़ा बोझ हिन्दुस्तान में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर है । आयुष्मान में आप पांच लाख रुपये दे दीजिए, लेकिन आयुष्मान के लिए कितने प्रावधान हैं, वह देख लीजिए । मेरा मानना है कि जो जांच है, वह सभी लोगों के लिए है । उसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड सैम्पल को कोई फ्री नहीं करते हैं । ये जांचें हिन्दुस्तान के मिडिल क्लास और गरीब पर सबसे बड़ा बोझ हैं । आप इनको बजट में नहीं लाए हैं ।

मैडम, एजुकेशन में कोचिंग आती है । मिडिल क्लास के बच्चों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है । आप कोचिंग पर प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? आप बच्चों को उसी कॉलेज में, जहां पर टेक्निकल शिक्षा देते हैं, वहां पर नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं अंत में आपसे दो बातें कहना चाहूंगा । बिहार में किसान की बात करते हैं, लेकिन खाद कहीं पर भी नहीं मिलती है । वहां 200-250 रुपये वाली खाद 450 रुपये में और 800 रुपये की खाद 1200 से 1800 रुपये में मिलती है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि खाद के संबंध में किसी भी कीमत पर एक प्रावधान लाया जाए और उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत एक व्यवस्था की जाए । किसान के लिए आप उन्नत बीज के बारे में कहते हैं, लेकिन खाद और बीज नहीं मिलता है । वह पूंजीपतियों के हाथ से किसान को दिया जाता है । बिहार, कोसी, सीमांचल के बारे में मैं दो-तीन बात कहना चाहूंगा । ?(व्यवधान)

कई बार हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है । ये बार-बार कहते हैं कि हम बिहटा में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं । हमारे प्रधानमंत्री भागलपुर नहीं गए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अगली बार बोलिएगा, तब तक आपकी तबियत ठीक हो जाएगी।

श्री राजेश रंजन: मैं अंत में कह रहा हूं कि सहरसा में एम्स खुलने की व्यवस्था हो गई थी । भारत सरकार को जमीन दे दी गई थी, लेकिन सहरसा के एम्स को हटाकर आपने कोई प्रावधान नहीं किया । कोसी, सीमांचल में सबसे ज्यादा कैंसर, टीबी, दमा के मरीज हैं । हमारे यहां कोसी में एम्स होना चाहिए । पुर्णिया में एक कैंसर का हास्पिटल होना चाहिए, लेकिन आपने कोई प्रावधान नहीं किया है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप

कम से कम एक चीज कीजिए कि एक योजना के तहत बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों का बजट में प्रावधान कीजिए और विशेष राज्य तथा विशेष पैकेज की घोषणा कीजिए ।

श्री राहुल सिंह लोधी (दमोह) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । आज मैं भारत सरकार और केन्द्र सरकार की नदी जोड़ो परियोजना के विषय में चर्चा करना चाहता हूं । मैं केन-बेतवा लिंक परियोजना के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं । जब हम बुंदेलखंड का नाम लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें वहां दिखती है और हमारे सामने जो दृश्य बनता है, वह सूखे का बनता है । आज से दस वर्ष पहले, वर्ष 2014 से पहले जब लंबे समय से विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने कभी बुंदेलखंड की तरफ ध्यान नहीं दिया । उन्होंने न रोड की तरफ, न शिक्षा की तरफ, न बिजली की तरफ और न ही पानी की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया । हमेशा बातें करके, वादे करके संपूर्ण बुंदेलखंड को वोट के माध्यम से बरगलाने का काम किया ।

लेकिन वर्ष 2014 के बाद जब केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का रोडमैप तैयार हुआ । सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ सरकार ने जब काम करना तय किया तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम भी हुआ । मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदी से नदी को जोड़ने का जो सपना था, उस योजना को साकार किया । इसी वर्ष तीन महीने पहले पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर खजुराहो में उन्होंने लगभग 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन किया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बुंदेलखंड की बात करता हूं तो बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है । जब केन-बेतवा लिंक परियोजना तैयार होगी तो मध्य प्रदेश की लगभग 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर भूमि और उत्तर प्रदेश की 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी । इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी । मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आठ-दस वर्षों में यह योजना बनकर तैयार हो जाएगी और सम्पूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में जब इसका पानी पहुंचेगा तो आप इस बात को विश्वास के साथ मानिए कि बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदल जाएगी । क्योंकि आज अगर हम हरियाणा और पंजाब की तुलना बुंदेलखंड से करते हैं तो हमारा बुंदेलखंड इसलिए विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वहां पानी नहीं था । जब वहां पानी पहुंचेगा तो विकसित बुंदेलखंड होगा और हमारा राज्य विकसित बनेगा । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं ।

माननीय सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. थोल तिरूमावलवन ।

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion. At the outset, I wish to pinpoint that the southern States including Tamil Nadu are being ignored as regards the devolution of funds collected through tax revenues. The net proceeds of taxes under the 14^{th} and 15^{th} Finance Commissions stood at 41 per cent and it is shocking to note that the Union

Government has been trying to reduce this to 40 per cent. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Katchi, we met Hon Finance Minister yesterday and put forth our demands in this regard. A little while ago, on behalf of Viduthalai Chiruthaigal Katchi, we met the Chairman of 16^{th} Finance Commission Shri Arvind Panagariya and submitted our memorandum in this regard as well. This 41 per cent devolution on the net proceeds from taxes should not be reduced at any cost. Rather this percentage of net proceeds from taxes should be increased to 50 per cent. I want to place the same demand here in this august House. The funds provided to Tamil Nadu are being reduced in the name of mentioning it as a developed State.

Not only Tamil Nadu, all the southern States of our country are being ignored in this way. In order to encourage the developed States, as an incentive, the devolution of funds meant for them should be increased rather it should never be decreased. There is no second thought that one should encourage the developing States. But the Union Government of India is ignoring the southern States including Tamil Nadu by terming them as developed States of the country. I want to question you whether is it justifiable to punish the developed States for no fault of them. Under the 9^{th} Finance Commission, the total share in devolution stood at 7.9 per cent for Tamil Nadu. Whereas this has further been reduced to 4 per cent during the 15^{th} Finance Commission. You should ponder over this matter as to why such a punishment given to Tamil Nadu. The Union Government is increasing the financial burden of the States. The Union Government has been introducing several Schemes for implementation.

17.59 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

The Union Government has been implementing Centrally-sponsored schemes in the country with fund sharing from the Union. Earlier it was implemented with 75 per cent borne by the Union Government and 25 per cent borne by the respective State Governments. But this ratio has now been changed to 60:40 between the Centre and the States. This has caused huge financial burden on the States. I urge that this financial burden on the States should be reduced.

HON CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: Just I started my speech. Please give me two minutes to conclude. I urge that this financial burden on the States should be reduced. Collection of Cess and Surcharge has become a burden for the States. Major part of such collection of taxes is taken away by the Union Government. I urge that the Union Government should also share the funds collected through Cess and Surcharges with the State Governments. The criteria relating to this fund sharing with the States should be redesigned and put to

review. I further urge that it should be redesigned in such a way that the developed States are not affected by that. MGNREGA funds should not be withheld by the Union Government but should be immediately released to the States concerned, including Tamil Nadu. Thank you.

18.00 hrs

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, यदि सहमत हों, तो इन विषयों की समाप्ति तक सदन की कार्यवाही बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

माननीय सभापति : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी ।

? (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam for giving me an opportunity. I will be speaking on Items 15, 16, 17, 18 and 19 in today?s List of Business. A pattern of deception repeats every year with the Ministry of Minority Affairs. In 2023-24, the Government allocated Rs.3,097 crore in BE. The Ministry of Minority Affairs surrendered Rs.2,060 crore, barely utilising the funds. The same rule or pattern is being followed in 2024-25 where the allocation of Rs.3,183 crore has been slashed to Rs.1,681 crore with no effort to demand admitted funds through the Supplementary Demands. Scholarships for minority students have been gutted. In pre-matric scholarship, only Rs.90 crore out of Rs.326 crore have been utilised. In post-matric scholarship, Rs.343 crore out of Rs.1,145 crore have been utilised leaving thousands of students without promised support. The Government is not willing to make the minority scholarships demand-driven. The unit cost of scholarship for three schemes has not been revised since 2007-08. Scholarships are not being sanctioned because of lack of approval by the Cabinet Committee on Economic Affairs since 2022-23. It is a known fact and empirical studies have proven that the literacy rate of Muslims for persons aged seven years and above is lower than the all-India literacy rate of the same age. According to one study, the Muslim enrolment for higher education is 8.91 per cent compared to all India enrolment which is 26.7 per cent.

The PM VIKAS scheme, a scheme meant for skilling and entrepreneurship of minorities has met the same fate. There was an allocation of Rs.540 crore in 2023-24. Only Rs.240 crore has been utilised. This scheme was aimed to benefit nine lakh candidates by 2025-26. The Budget has been slashed from Rs.500 crore in BE to just Rs.220 crore in RE 2024-25. In the supplementary grants, for the Ministry of Agriculture, there is a Scheduled Castes Sub Plan. Since 2021, the utilisation has never crossed 70 per cent. I demand from the

Government that they should ensure that from the Scheduled Castes Sub Plan, the Scheduled Caste farmers should benefit. Let them not sit on paper year after year. For the Ministry of Chemicals and Fertilizers, in this Supplementary Demands, Rs.14,000 crore is being asked.

Madam, this is not budgeting. This is firefighting. This talk on Atmanirbhar Bharat is only an empty talk. How did the Government allow such a critical sector to be held hostage by China? About 30 per cent of India?s urea imports, in 2023-24, came from China. Key raw materials like phosphoric acid and ammonia come from China, which make Indian prices vulnerable to China?s trade policies.

Madam, I am thankful that the hon. Minister, Shri Piyush Goyal is here. I have a specific point to make on US tariff. Goldman Sachs estimates that if the US imposes tariffs, this could decrease India?s GDP growth by 0.6 per cent. The US is a major buyer of Indian agricultural produce. We export nearly six billion dollars of agricultural produce to US. The imposition of higher tariffs will make Indian produce less competitive, affecting incomes in agriculture sector. We export generic pharmaceuticals worth 18.5 billion dollars to US. It is just to US. The US tariffs could significantly impact these exports.

Jewellery and precious metals are at a risk because of US tariffs. This industry faces 13.32 tariff differentials affecting SMEs engaged in jewellery manufacturing.

Madam, we export diamond and gold products worth 12 billion dollars to US. This tariff hike could reduce demand and could impact jobs in Surat and Mumbai. I want a categorical assurance from the Minister and the Government that the US tariff will not be imposed on India from April 2.

The Bilateral Trade Agreement is going on but Phase-I is due by September. Can the Government tell us about it? The EU market also has become restrictive. Will this Government give a categorical assurance that the CBAM and EUDR will not be imposed on India by EU, which will affect three billion dollars of Indian exports, particularly iron and steel? According to the *Economic Survey*, the EUDR is expected to affect 9.5 billion dollars of India?s exports. Madam, in the Supplementary Demands, the MEA is asking for Rs. 300 crore. Will India get a sanction waiver for Chabahar Port as we got in 2018?

Madam, now, I come to Manipur Budget. About 14,763 school-going children are displaced due to violence. Ninety-six schools have been used for relief measures. There was an internet shutdown for 54 days. And this Government has increased only two per cent for education in respect of Manipur.

Madam, 258 people were killed, 60,000 people were displaced including 22,000 children, and 1000 people were injured.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड कीजिए ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, I am concluding.

In Manipur, in displaced camps, 65.8 per cent of the people are suffering from PTSD and 24.8 per cent are suffering from moderate anxiety. What did you do? The help is, there is only an increase of Rs. 4 crore. There has been a 19 per cent reduction in water supply and sanitation. There has been a significant cut in capital outlay in Manipur Budget from Rs. 1,612 crore to Rs. 1,307 crore.

A Central assistance for providing temporary shelters to displaced families has seen a reduction of 75 per cent from Rs. 60 crore to Rs. 15 crore. Rural Manipur has experienced the highest inflation in July, which is 10 per cent.

Madam, 5000 hectares of agricultural land and 15,437 metric tonnes of paddy crops worth Rs. 38.6 crore have been lost due to ethnic violence. Madam, you will be surprised to know that agricultural allocation has been reduced by eight per cent. The total budget for police has been cut by two per cent compared to the last year. Manipur is the poorest State which has a per capita income of Rs. 7,630 per month, which ranks fourth from the bottom.

Madam, I am now concluding. We have heard hon. Piyush Goyal. He stood up and appreciated the speech made by Dr. M. P. Abdussamad Samadani from Kerala. I am very thankful to him. मैडम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उर्दू के अशार पढ़ने पर इसको कठमुल्ला की जुबान नहीं कहा, जो इनके वज़ीर-ए-आला ने कहा । इस भारत की खूबसूरती को आप नहीं समझ रहे हैं । आपको समझना चाहिए । उर्दू इस मुल्क की आजादी की जुबान है । आप अपने मुख्य मंत्री जी को समझाइए ।

मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants as well as on the Manipur Budget. I am standing here to express my views on the same.

मैं शुरू में बजट से ही बात करता हूँ । पहली बात यह है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए बजट बढ़ाया है । उसका स्वागत है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों के बारे में सोचते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का हमारी जमीन पर क्या असर हो रहा है? पानी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे क्षार बढ़ता जा रहा है । उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसानों का उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेरी एक मांग रहेगी ।

मेरी उसमें एक मांग रहेगी । आपने उसके लिए पैसा बढ़ाया है, यह ठीक है । मेरी मांग यह है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । सरकार को उसके लिए कदम उठाना चाहिए ।

आप सिविल एविएशन के लिए उड़ान योजना चला रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज कहां हैं, यह पता नहीं है । कोंकण में चिपी नाम का एक एयरपोर्ट बना । अभी उस एयरपोर्ट पर एक भी फ्लाइट नहीं जाती है । इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है । आपने बजट में पैसा कम भी किया है ।

I appreciate the hon. Finance Minister. At least finally, she has agreed to it. कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो घाटा हो रहा था, उसका कारण था कि पूर्व सरकार लाइसेंस फी के लिए उनसे पैसे भरवाने लगी और उन्हें बैंकों से कर्जा उठाने में लगाया, जब कि उनकी क्षमता नहीं थी, तो कर्ज की वजह से बीएसएनएल और एमटीएनएल डूब गए । आपको यह वर्ष 2014 में मालूम था । आज उन्होंने बताया है तो देर आए, दुरुस्त आए । मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं । अब मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे आप कॉर्पोरेट के कर्ज माफ कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार की यह जिम्मेदारी थी, वह ज्यादा नहीं बल्कि केवल दस हजार करोड़ रुपए थे, अगर आप वह करेंगे तो बीएसएनएल और एमटीएनएल फिर उभर कर आगे आएंगे, क्योंकि वे ब्याज भरते-भरते मर रहे हैं, उनका दम वहीं घुट रहा है ।

सरकार ने DIPAM को अनुमति दे दी है । इनके पास बहुत लैंड बैंक है । आप उस लैंड बैंक का इस्तेमाल करें और अपनी निधि तैयार कीजिए । वह काम नहीं हो रहा है । You are raising the funds by using the land bank. DIPAM has miserably failed. आपको उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर अलग चर्चा करनी पड़ेगी । आज मुझे नायडू साहब की याद आती है, जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे । वे हर वक्त कहते थे कि मातृभाषा में शिक्षा हो । आज हमने शिक्षा का जो बाजार बनाया है, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, क्या-क्या बोर्ड्स बनाए गए हैं और हम स्टेट बोर्ड्स का डिवैल्युएशन कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि स्टेट बोर्ड का वैल्युएशन बढ़ाइए । आप उसको अपग्रेड करिए, ताकि हमारे बोर्ड की शिक्षा सीबीएसई से भी अच्छी हो । लोग मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं । जब लोग मातृभाषा से दूर होंगे, तो वे देश की मिट्टी से भी दूर होंगे । इसलिए नए बच्चों को पुराना इतिहास बता-बता कर थकने से फायदा नहीं है । वे सब ऐकेडमिक बन गए हैं । अगर उस ऐकेडमिक स्थिति में मातृभाष नहीं आती है, उनको अपने देश के बारे में कोई इतिहास नहीं मालूम है, तो वे देश से कैसे जुड़ेंगे? उनको अच्छी उच्च शिक्षा नहीं मिलती है, तो वे विदेश चले जाते हैं । बच्चे यूक्रेन में पढ़ाए जा रहे हैं । क्या हिन्दुस्तान उससे पीछे है । सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ।

मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, I am really serious. हम पूरे विश्व में जहां कल्चरल इंट्रैक्शंस होती हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं । हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश को मदद करते हैं । हमने क्या किया है कि वर्ष 2023-24 में 37,196 करोड़ रुपए थे, फिर रिवाइज करके 29,660 करोड़ रुपए किए गए, अभी वह 20,516 करोड़ रुपए किए गए हैं, यानी 10 हजार करोड़ रुपए कम किए गए हैं । एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग बन गया है कि अगर विदेश में किसी हिन्दुस्तानी की मृत्यु होती है, तो उनके शव को लाने के लिए पैसे चाहिए, तो the Ministry of External Affairs is in problem. I really request the Finance Minister to pay very serious attention to the Ministry of External Affairs. मैं फिशरीज डिपार्टमेंट और हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में बाद में बोलूंगा । सभी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है ।

मैडम जी, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि इलेक्शन कमीशन, बोगस वोटिंग, EPIC के बारे में बंगाल के लोगों ने बताया है और सेम नम्बर्स, वे ही वोटर्स हरियाणा में हैं । मैंने मणिपुर के ऊपर नहीं बोला है ।? (व्यवधान) मुझे मणिपुर के ऊपर बोलने दीजिए । मुझे बहुत दु:ख है, मेरे मन में मणिपुर के लिए बहुत दर्द है ।? (व्यवधान) हम सभी वहां गए हैं । यह नहीं है कि हम अखबारों को पढ़ कर या हम किसी को देख कर कह रहे हैं ।

हम वहां गए । वहां कुकी और मैतेई की लड़ाई चल रही है । इससे दीवार खड़ी हुई है । इस देश का दुर्भाग्य है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज तक खबर नहीं ली ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अप्पलनायडू कलिसेट्टी जी ।

श्री अरविंद गणपत सावंत: मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । क्या आपको मणिपुर के बारे में बुरा नहीं लगा? वहां महिला की आबरू गई । क्या आपको बुरा नहीं लगा? चेयर पर महिला बैठी हैं । ? (व्यवधान) **SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM):** I thank you for giving me this opportunity to speak on supplementary demands for grants for the year 2024-25. I represent the aspirations of people of Andhra Pradesh under the able leadership of our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu. At the outset, I would like to thank our honourable Prime Minister Sri Narendra Modi for good governance and for placing India on the world arena as a leader. With additional outlay of 6 lakh crores and 51,000 crores of net expenditure, this budget proves to be an important tool for our country's development.

I would also like to thank our finance minister Smt Nirmala Sitaraman for balancing the development of infrastructure, social security and economic stability of our country. As a result, we could see good economic progress in our country. In this period of Amrit Kaal, though we are progressing ahead, Andhra Pradesh is going through a critical phase. Due to the previous government's negligence in the last 5 years, Andhra Pradesh suffered economic crisis. People of Andhra Pradesh reposed their faith in the able leadership of our leader Shri Nara Chandrababu Naidu garu.

I request the Union Government to bail out Andhra Pradesh out of the economic crisis it suffered in the last 5 years. I welcome additional funds of Rs 2,185 crores for PM Kisan Nidhi. Though this will benefit 9 crore farmers throughout the country, it will be of less benefit for our state farmers. 3 Questions need to be answered. Firstly, 50% of agriculture land is under cultivation of tenant farmers, who are not getting benefits from any farmers' welfare scheme as they are not eligible for these benefits. There is a need to make tenant farmers eligible for such welfare schemes. Secondly, the eligibility year is fixed in 2019, which needs to be revised as land holding changes every year. Thirdly, Rs 6,000 is not enough for financial assistance to farmers, as input cost of agriculture has increased substantially. Therefore, there is a need to revise this amount.

Madam, in Andhra Pradesh, fisheries and animal husbandry are important pillars of the rural economy. But due to the previous government's negligence, these sectors underwent a crisis. For the National Livestock Mission, the budget has decreased by 80%. For the financial year 2022-23 the budget allocated was 60 crores, which has been reduced to 12 crores for the year 2023-24. Till August 2024, not even a single rupee was released for this scheme.

I request the Union Government to allocate at least Rs100 crores for this mission. Water security is another important issue in our state of Andhra Pradesh. Especially in regions like Rayalaseema and North Andhra Pradesh, drought is severe. I thank the Union government for allocating ₹5,900 crores out of ₹12,000 crores for the Polavaram project. Due to the previous government's mismanagement, the Polavaram project got delayed by five years. Funds misuse, stalling of project works and improper planning for displaced, affected thousands of families. Had we completed the Polavaram project by now, we could have provided irrigation facilities to 7 lakh acres of agricultural land, drinking water facility to 540 villages. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, Chairperson, I rise to oppose the Second Batch of Supplementary Demands for Grants of 2024-25, Demands for Excess Grants of 2021-22, Demands for Grants of 2025-26 for the State of Manipur and the Supplementary Demands for Grants for the State of Manipur.

First of all, may I submit that the discussion on the Budget along with the Demands for Grants on Account for the State of Manipur is totally unfair and improper?

It is because the Union Government?s Supplementary Demands for Grants is generally distinct from that of the State of Manipur. These two issues are entirely different. That has to be corrected. That is my first submission which I would like to make.

Madam, the Supplementary Demands for Grants, the Second Batch for the financial year 2024-25, include 52 grants and three appropriations. It is sought to authorise for an additional expenditure of Rs. 6,78,508 crore. Out of this, the net cash flow is just Rs. 51,462 crore. Other expenditure comes by savings of the ministries and departments or by enhanced receipts or recoveries, that means a technical Supplementary would come to around Rs. 6.27 lakh crore. Further, the token provision of Rs. 67 lakh is also sought. What does it indicate? An amount of Rs. 6.78 lakh crore as an additional expenditure than the budget estimate of expenditure means there is a lack of foresight and planning in the budgetary process. It is absolutely the budgetary process failure of the Finance Ministry. In 2024-25, the first batch of Supplementary Demands for Grants were Rs. 87,000 crore. It would come to around Rs. 7.5 lakh crore. That means, it is one-sixth of the total budget

estimate. The total budget estimate for the last financial year was around Rs.46 lakh crore. Out of that, Rs. 7.5 lakh crore is coming as the Supplementary Demands for Grants. In that case, what is the Ministry doing? What is the efficiency of the Ministry? What is the sanctity of the budget proposals, the budget estimate and budget expenditure? This has to be explained by the Finance Minister.

Madam, whatever the Government has demanded from this House, it has granted without any cut. Then, what is the reason behind asking this much of amount?

Now, I would like to come to savings. Around Rs. 6 lakh crore is the savings. That is to be re-appropriated under various ministries and departments. The Comptroller and Auditor General of India has specifically stated that if there is a savings of more than Rs. 100 crore, that has to be seriously dealt with. I would like to know whether the Government is aware of this or not.

Now, I would like to talk about a technical objection. Last time also, I have raised the same objection. Madam, it is a Point of Order also. Last time, when I raised it as a Point of Order, the hon. Speaker had directed the Government that if permission was not sought from the Parliament regarding advance from the Contingency Fund of India, then the statement has to be laid on the Table of the House. It is quite unfortunate to say, in this Supplementary Demand for Grants also, besides Rs. 67 lakh of token provision being sought, Rs. 1 lakh for each item of expenditure for enabling re-appropriation of savings in cases of involving new services and new instruments of service, as per the Parliamentary procedure, this has to be laid on the Table of the House in case of advance, which has not been done. I would like to cite two examples. In the case of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Rs. 347.5 crore has been taken as advance from the Consolidated Fund of India by virtue of Demand Number 1, and by virtue of Demand Number 26, Department of Higher Education, Rs. 908 crore has been taken from the Consolidated Fund of India without the prior approval of the Parliament. Even after getting advance, no statement has been laid on the Table of the House as per the Parliamentary procedure. I would like to seek the clarification from the hon. Finance Minister, as well as a ruling from the Chair.

Now, I am coming to the Supplementary Demands for Grants, Demand Number 97, with respect to the Ministry of Steel. There is an investment of Rs. 6,783 crore to recoup the advance from the Consolidated Fund of India for equity infusion in Vizag Steel Plant. I fully welcome the step taken by the Government for capital infusion in the Vizag Steel Plant. Due to that effort, the privatization will be over. I would like to ask a question to the hon. Finance Minister. Why is it allowed to the Vizag Steel Plant alone? When the capital infusion in the form of foreign direct investment is being granted for life insurance sector, why is it not available for other public sector undertakings? Is it because TDP is supporting this

Government? Is it the reason that Rs. 6,786 crore has been provided under the Supplementary Demands for Grants?

The last point is Demand Number 84 which relates to excess grants for the financial year 2021-22. Madam, with that point I will conclude. That is regarding the railways. That is a very, very serious matter. Around Rs. 35 lakh is misclassified as per the Demand which is being shown. How does this misclassification happen? Who is responsible for this misappropriation? I would like to know whether it is done purposefully or mistakenly.

With these points, I strongly oppose the SDGs for the financial year 2025-26.

Thank you very much, Madam.

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं, उसका हर एक रुपया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नागरिकों को सशक्त करने के लिए और सशक्त भारत के निर्माण में ही खर्च होता है, उसका योगदान होता है । आज जो अतिरिक्त धनराशि मांगी गई है, वह सिर्फ कागजों पर कुछ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है । वह भविष्य के भारत के निर्माण का मानचित्र है । पीएम गति शक्ति हो, पीएम किसान योजना हो, राष्ट्र की सुरक्षा को सशक्त बनाना हो, ये सभी व्यय भारत की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं ।

अभी कुछ विपक्षी दलों ने विषय उठाया, फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में, मैं माननीय प्रेमचन्द्रन जी को सुन रहा था । उन्होंने वित्तीय अनुशासन को लेकर प्रश्न उठाया । I would like to remind them that there was a period during the UPA regime when recklessly, they had burdened the economy with unplanned spending and policy paralysis. In contrast, in our term, under the leadership of Modi ji, every rupee that flies out of the coffer of the exchequer is under the guidance, under the radar of the ?ATC?. This does not mean ?Air Traffic Control?. The meaning of ?ATC? is ?A ? Accountability; T ? Transparency; C ? Clear vision of development?.

माननीय सभापति महोदया, during the UPA regime, वर्ष 2004 से 2014 के दौरान, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 94,060 करोड़ रुपए की बजट राशि जो कि लगभग 14 विभागों- सामाजिक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से संबंधित थी, वह 10 वर्षों में खर्च नहीं हो पाई थी । यूपीए की सरकार उस समय बजट का लगभग 6.4 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं कर पाई थी । मैं कृषि क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं । वर्ष 2013-14 में कृषि का बजट यूपीए के समय में 27,663 करोड़ रुपए था, अब वह पाँच गुना बढ़कर 1,37,756 करोड़ रुपए हुआ है । फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है, वह भी पाँच गुना बढ़ी है । अभी हाल-फिलहाल में बिहार के भागलपुर से 19वें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किए । मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक उस समय की कहानी थी, जिस समय कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी करती थी । ट्रेजरी बेंच के उनके एक मंत्री थे, वे उस समय ट्रेजरी बेंच में बैठते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वे बहुत बड़े मंत्री थे, उन्होंने आईटी एग्जेम्पशन के लिए यानी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के

लिए कहा था कि मैं कृषक हूं और मैं कृषि से भी अर्न करता हूं । उन्होंने गमले में सात करोड़ रुपए की गोभी उगायी थी । गमले में सात करोड़ रुपए की गोभी उगी थी । सोचिए कैसे सात करोड़ रुपए की गोभी गमले में उग सकती है, यह मुझे नहीं पता है ।

अब मेरे दो छोटे-छोटे विषय हैं, मगर मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इंप्रिंट छोड़ेगा, मैं एक उदाहरण देता हूं । यहाँ पर गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की । मैं दो हेडलाइंस लेकर आया हूं । पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई से जो छपा था । यह 8 जुलाई, 1991 का हेडलाइन है । इसे लिखा है शंकर अयर ने ।

?Secret sale of gold by the Reserve Bank of India again. 21,000 kg of metal air-lifted to coded destination.? एक समय था, जब वर्ष 1991 में श्री राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था । उस समय लिक्विडिटी का अभाव था और देश की अर्थ-नीति में त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी । उस समय पहली बार हिन्दुस्तान के ऊपर वह त्रासदी आई थी, जब देश के 67 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा था । ? (व्यवधान) शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर देख रहा था, चुपके-चुपके आरबीआई की गाड़ियां आ रही थीं और हिन्दुस्तान के सोने को एयर इंडिया की एयर बस में लोड किया जा रहा था । ? (व्यवधान) हिन्दुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था, आप सोचकर देखिए । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं 31 मई, 2024 की एक दूसरी हैडलाइन पढ़ना चाहूंगा । ? (व्यवधान)

?RBI Brings Back Home 102 Tons of Gold from United Kingdom.? श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक लाख के.जी. सोना बाहर से मई, 2024 में हिन्दुस्तान में वापस आता है । ? (व्यवधान) यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा और दूसरे लल्ला ने, हमारे श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी भारत मां को अलंकृत किया, यह होता है फर्क । ? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा । ? (व्यवधान) मैं एक और उदाहरण देता हूं । ? (व्यवधान) इस पूरी सप्लिमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के लिए अधिक व्यय की मांग की गई है । ? (व्यवधान) यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है । ? (व्यवधान) मैं 31 जुलाई, 2012 की एक हैडलाइन पढ़ता हूं । अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आएंगी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उस समय पार्टी की प्रवक्ता थीं । वे एक चैनल के डिबेट में बैठी हुई थीं, तब अचानक अंधकार हो गया और डिबेट बीच में बंद हो गई । ? (व्यवधान) 22 राज्यों में अंधकार हो गया था, क्योंकि 30 और 31 जुलाई, 2012 को नॉर्दन ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ-ईस्टर्न ग्रिड, तीनों ग्रिड फेल हो गए । ? (व्यवधान) About 700 million people were plunged into darkness. Nine per cent of the world?s population were plunged into darkness. टीएमसी के लोग अभी यहां नहीं बैठे हैं । 200 मजदूर एक माइन के अंदर बंद हो गए । न जाने कितने लोगों ने, जो वेंटिलेटर पर थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी । ? (व्यवधान) I would read another headline of the Times of India dated June 3rd, 2024. It quotes, ?India?s come a long way since 2012 outage, world?s largest; even 250 GW isn?t a problem.? 30 मई, 2024 को अचानक भारत की जो पावर की रिक्वायर्मेंट थी, वह सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है । भारत की पावर की आवश्यकता 250 गीगावॉट हो जाती है, मगर हमारा ग्रिड टूटता नहीं है, फेल नहीं होता है । World's largest unified power grid is what

our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji has given to the nation. इसलिए, मैं इसका समर्थन करता हूं ।? (व्यवधान)

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि आज मणिपुर के विषय में बहुत कुछ बोला गया है । मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां कहीं न कहीं, जहां एकता दिखनी चाहिए, उस एकता की कमी है । मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और अपोजीशन के हमारे माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वे आंकड़ों को मांगें और जानें भी, क्योंकि यह देश हम सबका है । ?इन्टर्नली डिस्प्लेस्ड पीपल?, जिसको आईडीपी कहा जाता है, उनके लिए यहां प्रश्न उठे और उठने भी चाहिए । ये प्रश्न उठे कि उनके लिए क्या किया गया?

In response, the Government has implemented a series of measures aimed at providing immediate relief, long-term rehabilitation and economic stability for the Internally Displaced Persons. These initiatives are Housing Assistance First wherein pre-fabricated housing would provide immediate shelter to 3,000 families. Of this, 2,660 houses have been completed and 2,520 houses have been occupied. About 340 houses will be completed by the end of the month. Then, financial aid of Rs.1,000 has been provided on five separate occasions, amounting to a total of Rs.30 crore.

An additional amount of Rs. 27 crore has been released to support the housing reconstruction efforts in Manipur for those who are internally displaced. Relief camp operations have been sustained with an allocation of Rs. 280 crore, ensuring essential services, such as food and healthcare for affected families. A compensatory package of Rs. 32 crore has been provided to farmers who have suffered agricultural losses due to the conflict.

माननीय सभापति महोदया, यहाँ एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की है । A total of 11,763 displaced students have been enrolled in various educational institutions. The Government schools and colleges have provided free admission. A college students rehabilitation scheme had been introduced in 2023. उसको वर्ष 2023 में इंट्रोड्यूज किया गया, जिसने हजार डिसप्लेस्ड बच्चों की मदद की ताकि वे वहाँ जाकर फ्रीली एडमिशन ले सकें और उन्हें 10 हजार रुपये की राशि भी ऊपर से दी गई । For employment and skill development of displaced people, 426 IDP-led startups have received Government support. स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दी गई । अभी हाल-फिलहाल में 500 इंडिविजुअल्स इसमें एनरोल्ड हुए हैं । केबिन क्रू ट्रेनिंग इन दिल्ली, इसमें मैं एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइन्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को धन्यवाद दूँगा कि इनके माध्यम से मणिपुर के 500 बच्चे, जो डिसप्लेस्ड हुए थे, उनको यहाँ प्लेस किया गया है ।

Free medical treatment has been provided to the IDPs at JNIMS. ठीक उसी प्रकार हमारी जो गर्भवती माताएँ हैं, इन रिलीफ कैंपों में उनके लिए भी हर संवेदना के साथ पूरी तरह का प्रोविजन किया गया है ।

महोदया, अपने भाषण के अंत में, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे राहुल जी ने कल ही कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है । अभी अरविन्द सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है । वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है ।? (व्यवधान) आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी ।? (व्यवधान) आपके डेवलपमेंट लिस्ट

में गड़बड़ी थी । वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है । अभी हमने आपको जो बताया, अगर ऐसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहाँ नहीं बैठे होते ।

दूसरी बात, यह कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट हैं । रोहित शर्मा अनफिट नहीं हैं,* ? (व्यवधान) मैं बता दूँ, आप देखिएगा कि नरेन्द्र मोदी जी की कप्तानी में ही भारत विश्व की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगा ।? (व्यवधान) भारत माता की जय । जय जगन्नाथ ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री अमर काले जी ।

? (व्यवधान)

श्री अमर शरदराव काले (वर्धा) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार मानता हूँ ।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदया, इन्होंने असंसदीय शब्द कहा है ।

माननीय सभापति : कुछ आपत्तिजनक होगा, तो उसे हटा दिया जायेगा । कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसे हटा दिया जायेगा । आप बैठिए । माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री अमर काले जी ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: इन्हें माफी माँगनी चाहिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकॉर्ड से हटा दिया गया है । माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अमर शरदराव काले जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अमर शरदराव काले जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री अमर शरदराव काले : सभापति जी, मैं बोलना चाहता हूं ।?(व्यवधान) आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों तथा मणिपुर के बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

*Hon. Chairperson, thank you very much for allowing me to speak on the General discussion on the budget for the state of Manipur for 2025-26. We all are well aware of the

situation in Manipur. On 3rd May, 2023, violence erupted in the state of Manipur and it continued for the next two years without pause. The union Government did not take any cognizance of this violence which led to complete chaos and lawlessness. It started in May 2023, but the Chief Minister of Manipur recently resigned from his post.

We have heard about ?when the Rome was burning, Nero was fiddling?. Unfortunately, same situation persists in our country too. They always talk about, ?Modi hai, toh Mumkin hai,? but it is of no use. Please let me complete.

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री अमर शरदराव काले: सभापति जी, मैं अपनी पार्टी का अकेला वक्ता हूं । मेरी पार्टी का टाइम 10 मिनट का है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री आनंद भदौरिया जी ।

? (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति जी, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा अनुदानों की अनुपूरक मांगों और मणिपुर के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।? (व्यवधान) मैं इस विषय पर अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले अपने लोक सभा क्षेत्र धौरहरा की महान विभूतियों, सीतापुर के निर्माता महाराजा सीतापासी जी, मितौली के महाराजा मितानपासी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने नेता श्रद्धेय नेता जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करता हूं ।? (व्यवधान)

<u>18.44 hrs</u>

At this stage Shri Gurjeet Singh Aujla, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members stood on the floor near the table.

माननीय सभापति जी, मणिपुर का बजट आखिर संसद में किन हालातों में प्रस्तुत करना पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है ।? (व्यवधान) जब आधी आबादी राहत कैम्पों में रह रही हो, तो इस बजट का लाभ किसे मिलने वाला है? मैं मणिपुर के बजट पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं ।? (व्यवधान) आज 11 मार्च है । हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । अभी होली आने वाली है । ईद की भी छुट्टी होनी है । शनिवार, रविवार भी आना है । अब 31 मार्च में कितने दिन बचे हैं? इस नए बजट को कैसे खर्च कर पाएंगे ।? (व्यवधान) पहला अनुपूरक बजट आप दिसम्बर में लाए, दूसरा फिर ले आए हैं । इसका मतलब आप इस मद को लूटना चाहते हैं ।? (व्यवधान) इसका मतलब यह बजट आपका चुनावी चंदा बन जाएगा ।? (व्यवधान)

सभापति जी, 51 हज़ार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जो सरकार ने मांगा है, इसकी प्राप्ति कहां से होगी, इसका कोई ज़िक्र आपने नहीं किया है । किसी नए मद का न होना यह बताता है कि आपका नियोजन सही नहीं है, आपका वित्तीय अनुशासन सही नहीं है, इसलिए आपको बार-बार अनुपूरक मांगे लानी पड़ती हैं ।

? (व्यवधान) खाली भाषण आपके पास हैं । प्लानिंग कमीशन की जगह आपने नीति आयोग बनाया है, वह बनाना भी ?* साबित हो रहा है । ? (व्यवधान) सभापति जी, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि

?वादा किया गया था, उजालों का क्या हुआ?
जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ?
शाहों की सेर के लिए रस्ते तो बन गए,
लेकिन आवाम के पैर के छालों का क्या हुआ??

? (व्यवधान) आदरणीय सभापति जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, जो मैं ले कर के आया हूँ कि यूएस एड बंद हो गयी है । वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि यूएस एड का पैसा भारत की आर्थिक परियोजनाओं में लगा है । ? (व्यवधान) जब यूएस एड बंद हो गयी, तो क्या वे परियोजनाएं बंद हो जाएंगी? मसलन क्या उन सारी परियोजनओं को रोक दिया जाएगा? ? (व्यवधान) वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगी तो इसको बताने का काम करेंगी । ? (व्यवधान) माननीय सभापित जी, तमाम विभागों पर बजट आया है । ? (व्यवधान) कृषि कल्याण पर आपने अतिरिक्त बजट मांगा है । ? (व्यवधान) आज देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई बेहाल है, तो किसान बेहाल हैं । ? (व्यवधान) कोई बाज़ार नहीं है । ? (व्यवधान) उत्पादन का उसको कोई ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं जिस माहौल में भाषण कर रहा हूँ और हमारी पार्टी का समय 15 मिनट है । ? (व्यवधान) मुझे आपका संरक्षण चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया : माननीय सभापति महोदया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि से इस देश के किसान का कल्याण नहीं होने वाला है । ? (व्यवधान) इसलिए किसानों का कर्ज़ा माफ कीजिए । ? (व्यवधान) माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सिंघु बॉर्डर पर भेजा था । ? (व्यवधान) डल्लेवाल जी आज भी अनशन पर हैं । ? (व्यवधान) किसानों की मांगें माननी चाहिए । ? (व्यवधान) प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंदर ऐसे मानक बना दिए गए हैं कि अगर खड़ंजा लगा हो तो अब सड़क नहीं बन सकती है । ? (व्यवधान) वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से लेंगे तो सड़क नहीं बन सकती है । ? (व्यवधान) हमारी आपसे मांग है । ? (व्यवधान) हम सांसदों के पास है क्या? ? (व्यवधान) प्रधान मंत्री सड़क योजना ही तो हम लोग बनवा सकते हैं । ? (व्यवधान) उसके मानक को सरलीकरण किया जाए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, हम लोग दिल्ली की चमक-धमक देखने नहीं आए हैं । ? (व्यवधान) हम अपने क्षेत्र की लाखों जनता की उम्मीदें ले कर के दिल्ली आए हैं । ? (व्यवधान) इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि वर्ष 2014 के बाद तमाम परिवर्तन हो गया है, लेकिन वर्ष 2014 के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सांसद निधि में नहीं हुआ है । ? (व्यवधान) वह जितनी वर्ष 2014 में थी, वही आज भी है । इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि 90 लाख जीएसटी, दस करोड़ कंटीजेंसी । ? (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि आइए मिल कर के विकसित भारत बनाएं । ? (व्यवधान) क्या चार करोड़ में खाक विकसित भारत बनाएंगे? ? (व्यवधान) इसलिए सांसद निधि को बढ़ाया जाए । ? (व्यवधान) हमारे उत्तर प्रदेश में एक करोड़ विधायक निधि है । ? (व्यवधान) इसलिए पांच करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपये सांसद निधि की जाए । ? (व्यवधान)

सभापति जी, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि

?तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं,
कमाल यह है कि फिर भी तुम्हे यकीन नहीं ।
मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,,
मैं इन अंधेरों का अंध तमाशबीन नहीं ।?

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, मणिपुर के बजट और अनुदान से जुड़ी मांगो पर सदन में चर्चा हो रही है । ? (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा । ? (व्यवधान)

सभापति जी, आज सरकार अतिरिक्त बजट की मांग कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप राज्यों को जो बजट आंवटित करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं होती है । केंद्र की विभिन्न योजनाओं हेतु भेजी गई राशि में से 1.40 लाख करोड़ रुपये अब भी बैंक खातों में पड़े हैं, इसका जिक्र आपने इस बजट में भी किया है । प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, शहरी कायाकल्प, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं में पैसे राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई ।

सभापति महोदया, मैं खनन नीति और राजस्थान के बारे में एक विषय रखना चाहता हूं । आज आवश्यकता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान के कई जिलों में निकलने वाले लाइमस्टोन, बजरी व अन्य खनिजों के लिए एक या दो हेक्टेयर के छोटे पट्टे किसानों को दिए जाएं ।? (व्यवधान) हाल ही में आपने केवल गुजरात के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेराईट्स, क्वार्ट्ज, फैल्सफार तथा अभ्रक आदि को माइनर से मेजर मिनरल में सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी कर दी है । इससे राजस्थान के लाखों छोटे उद्यमियों को नुकसान होगा । इससे उनका कामकाज प्रभावित हो   जाएगा । ऐसे निर्णयों की सरकार को फिर से समीक्षा करनी चाहिए ।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से खान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन का खनन पुन: शुरू करने की मांग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहूंगा ।? (व्यवधान) मैंने एक सवाल भी उठाया था । उसके बाद जीएसआई ने वहां सर्वे शुरू किया । आप इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य करें । साथ ही मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी से मांग करता हूं ।? (व्यवधान) मैं अपने संसदीय क्षेत्र नागौर में उगाई जाने वाली विश्वविख्यात पान मैथी को जीआई टैग देने की मांग करता हूं ।? (व्यवधान) जीआई टैग के आवेदन पर जो कमियाँ आपके मंत्रालय में निकाली गई, उन कमियों की पूर्ति करके जिला प्रशासन नागौर द्वारा भेज दी गई है ।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं नदियों और गंगा जल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । आज अतिरिक्त बजट की मांग सरकार कर रही है, लेकिन एनजीटी के निर्देर्शों के बाद भी मेरे राजस्थान के पाली जिले में स्थित बांडी, जोधपुर स्थित जोजरी व बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के बालोतरा जिले में स्थित लूणी नदी में कपड़ा फैक्ट्रियों सहित अन्य फैक्ट्रियों द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले दूषित जल से वहां बंजर हुई कृषि भूमि व फैल रही बीमारियों की तरफ भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।? (व्यवधान) आप केंद्र की एक टीम वहां भेजिए । प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी फैक्ट्रियों को सीज कीजिए । नदियों में दूषित जल रोकने का तत्काल स्थाई समाधान किया जाए ।? (व्यवधान)

महोदया, अमृत योजना के बावजूद भी शहरों में दुर्गति की स्थिति है । आज सरकार अमृत योजना के माध्यम से शहरों में सुधार की बात करती है ।? (व्यवधान) लेकिन, आज ही मेरे नागौर के अखबारों के अंदर मेन पृष्ठ पर लिखा हुआ था कि पार्कों की खराब हालत से अमृत योजना की उम्मीदों पर पानी फिरा है । हमारे सीकर शहर के सिवरेज और गंदे पानी की निकासी से वहां के गांव नानी, ढाका की ढाणी, सबलपुरा, पूरा की ढाणी सहित गई गांव गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ।? (व्यवधान) मेरी मांग है कि अमृत योजना या अन्य किसी योजना में सीकर सहित राजस्थान के सभी नगरीय इकाइयों में गंदे पानी के ट्रीटमेंट और उनके समुचित निकास का प्रबंध करवाया जाए ।? (व्यवधान)

महोदया, अब मैं राजस्थान और अतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में विषय रखना चाहता हूं । आज पंजाब समझौते के बावजूद भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा है ।? (व्यवधान) वहीं नहरों में पानी कम आने के कारण बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले से लेकर जैसलमेर जिले में परेशानी हो रही है ।? (व्यवधान)

महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा । जैसलमेर में मोहनगंज के किसान सिंचाई के पानी के लिए परेशान हैं । नहरों में पंजाब से आ रहे गंदे पानी से राजस्थान के लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं ।? (व्यवधान) मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और राजस्थान के लंबित जल विवादों का निस्तारण करे । पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले दूषित पानी के प्रवाह को रोका जाए ।? (व्यवधान)

महोदया, मैं एक और निवेदन करूंगा । एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो । ? (व्यवधान) केंद्र सरकार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे । बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है ।? (व्यवधान) पेट्रोल-डीजल की कीमत कम की जाए । इस विषय पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।? (व्यवधान)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Madam, I rise today to discuss Manipur?s Budget at a critical juncture. ? (*Interruptions*) With many lives lost and 50,000 displaced and the State under President?s Rule, this Budget transcends routine governance. It is a moral imperative. ? (*Interruptions*) Parliament now bears the responsibility of Manipur?s legislature demanding our collective resolve to heal divisions and restore civility.

Regarding financial governance under President?s Rule, Article 356 has placed Manipur?s governance in our hands. History reminds us that Central rule must prioritize financial continuity and accountability. ? (*Interruptions*) In Bihar, President?s Rule lasted nearly a week to pass a budget, underscoring the urgency of fiscal responsibility during a crisis. For Manipur, this means rigorous Parliamentary oversight to ensure that funds translate into action. What are the key priorities in the 2026 Budget? ? (*Interruptions*) Rs.35104 crore Budget professes on powerfulness, infrastructure, security, social welfare, relief and rehabilitation. We must rebuild trust and religious harmony. ? (*Interruptions*) The destruction of 386 religious sites including churches, temples and mosques has deepened wounds. Rebuilding these is not near-reconstruction; it is an act of healing. While the Budget lacks a specific item for this, I urge earmarking relief funds for restoring places of worship.

Let us send a clear message: Manipur's diversity is its strength. ? (*Interruptions*) Christian communities, in particular, need assurance through tangible support; rebuilding churches and ensuring welfare reaches those in camps. ? (*Interruptions*) There has to be accountability and transparency. Without an elected Assembly, Parliament must ensure public reporting, zero tolerance for corruption and balanced priorities. ? (*Interruptions*) We must give a roadmap for hope. ? (*Interruptions*) This budget must be more than numbers. It is a covenant with Manipur's people. ? (*Interruptions*) We need clear timelines, accountability mechanisms and a path to elections. ? (*Interruptions*) Manipur's anguish calls for unity, not partisanship. ? (*Interruptions*) Let this Budget be a beacon of justice, inclusion, and renewal. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shri Durai Vaiko.

? (*Interruptions*)

ADV. FRANCIS GEORGE: Every rupee must speak to the farmer returning to his field, the child reclaiming her education, and the priest reopening a rebuilt church. Together, let us pledge: No citizen of Manipur will be left behind. ? (*Interruptions*)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वहां महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए । ? (व्यवधान) यह मुद्दा केवल एक राज्य का ही नहीं है, बल्कि यह देश की अस्मिता और गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ।? (व्यवधान) अत: वहां शांति व्यवस्था बहाल कर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए ।? (व्यवधान) मणिपुर की घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है ।? (व्यवधान) मुझे ऐसा लगता है कि यह तभी होता है, जब सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हितों से कम प्यार होता है ।?(व्यवधान)

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, बिजली के बिल माफ हों, किसानों के कर्ज माफ हों । ?(व्यवधान) सरकार को समझना होगा कि जब किसान मजबूत होगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ।? (व्यवधान) खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जाए । किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है ।?(व्यवधान) खाद के वितरण में पारदर्शिता लाई जाए ।? (व्यवधान) यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं, जब देश में खाद्य संकट आ जाएगा ।? व्यवधान)

महोदया, गया में महाबोधि विहार प्रखंड में बुद्धिस्ट समाज में चिंता और आक्रोश है ।?(व्यवधान) सरकार उनकी समस्या को हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करे, ईसाइयों पर हमले बंद हों और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ।? (व्यवधान) आज एससी, एसटी पर एट्रोसिटी बढ़ रही है ।? (व्यवधान) जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं । ? (व्यवधान) अभी हाल में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां जातिगत अपमान हुआ है । ? (व्यवधान) नगीना लोक सभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है । ? (व्यवधान) वहां न गन्ने के मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पर भुगतान किया जा रहा है । ? (व्यवधान) गन्ना किसान मजबूत होगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ।? (व्यवधान)

एससी, एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरियां खत्म की जा रही हैं, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है ।? (व्यवधान) यह सब मैं बार-बार इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे समझें कि सरकार उनकी कितनी हितैषी है? ? (व्यवधान)

प्रधान मंत्री आवास योजना के मानक में बदलाव किया जाए । उसकी वजह से बहुत से पीड़ित वंचित रहते हैं ।? (व्यवधान) कई बार ऐसा होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दीं, तो उसको मानक से बाहर कर दिया जाता है । इस वजह से ऐसे परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ।? (व्यवधान) इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे हैं । ? (व्यवधान) आजादी के 75 साल बाद भी लोगों के पास घर नहीं हैं । यह शर्म की बात है ।? (व्यवधान) नगीना लोक सभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं । जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो ।? (व्यवधान)

अंत में, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी ईद का त्यौहार आ रहा है । ?(व्यवधान) हम भी यह देखेंगे और देश भी यह देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद कराके उस त्यौहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे वह अन्य धर्मों की लगातार मदद कर रही है ।?(व्यवधान) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिनकी सरकार है, उन्हीं की बात होगी, न कि मुसलमानों की, जैनियों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की । ? (व्यवधान) वे आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है । ? (व्यवधान) मैं समय रहते सूचित कर रहा हूं कि सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्ध बर्दाश्त नहीं करेंगे । महाबोधि विहार हमारा हक है और वह देना पड़ेगा ।? (व्यवधान)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय भीम, जय भारत ।? (व्यवधान)

<u>19.00 hrs</u>

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Madam, thank you for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants ? Second Batch for 2024-25, Demands for Excess Grants for 2021-22, and the Manipur Budget.

मोदी जी के दस वर्षों के शासन में इतिहास रचा जा रहा है । चार करोड़ लोगों को आवास योजना का बेनिफिट इस सरकार ने दिया है । महराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है । महाराष्ट्र में आवास योजना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी ने दीनदयाल उपाध्याय योजना चलायी, जिसमें लोगों को एक लाख रुपये सरकार के द्वारा घर खरीदने के लिए अतिरक्ति पैसे दिए जाते हैं ।

हमारे नेता माननीय देवेन्द्र फडणवीस जी ने आवास योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अतिरिक्त पचास हजार रुपये जारी किए हैं । यह डबल इंजन की सरकार है । जब मणिपुर की बात आती है, अंडमान और निकोबार में हमारी सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का 2300 किलोमीटर का जाल बिछाया है । लक्षद्वीप और कोच्चि में 1800 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर का काम किया है । सरकार ने कश्मीर में धारा 370 खत्म करके विकास को एक नई दिशा दी है । पहले कश्मीर में हमेशा दंगे होते थे, वहां पर सरकार ने विकास की गंगा लायी है । वहां दो एम्स, एक श्रीनगर और एक जम्मू को दिया है ।

जब मणिपुर की बात आती है तो पूरे देश को यह समझने की जरूरत है कि विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है । सरकार ने डिमांड फॉर ग्रांट्स में किसानों के लिए यूरिया की सब्सिडी दो हजार रुपये अतिरिक्त दी है । इसके साथ ही पोटाश और फॉस्फेट के लिए बारह सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिमांड की है । माननीय मोदी जी द्वारा उज्ज्वला योजना लाई गई थी, इस योजना के माध्यम से हर घर में चूल्हा आया है, इसके लिए भी छह सौ करोड़ रुपये की डिमांड की गई है । मैं अपनी कंस्टीट्यूएंसी के लिए कुछ डिमांड रखना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में अकोला, भुसावल और जलगांव स्टेशनों के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये की निधि दी है । मैं चाहूंगा कि एक एक हजार करोड़ की राशि से इन स्टेशनों का जल्द से जल्द डेवलपमेंट किया जाए । अकोला में चौदह सौ मीटर की लाइन है ।

* There is a 1400 metre rail line in my constituency Akola, which needs to be revised to 1800 metre urgently. I would like to thank Hon. Modiji for it. A new Port with 20 metre depth is being developed at Vadhavan in Palghar district by spending Rs. 78000 crore.

Our country and my State Maharashtra are heading towards overall development at a very fast pace under leadership of our PM Narendra Modi. I would like to thank Hon. Railway Minister Ashwini Vaishnav for sanctioning Gati Shakti Terminal in my constituency Akola. Jai Hind. Jai Maharashtra.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, the Budget regarding Manipur should have been discussed about 20 months ago. We went to Manipur one year six months back and we came back to the House. ? (*Interruptions*) We had said at that point of time that the condition of Manipur was such that Article 356 should have been imposed. ? (*Interruptions*) But at that time, Article 356 was not imposed. Now, Article 356 has been imposed. ? (*Interruptions*) As a result thereof, how many persons have died in Manipur? It is also reported that over 5,000 persons are injured and 32 persons are missing. Madam, 4,786 houses have been burnt and 386 religious structures have been vandalised, including temples and churches. ? (*Interruptions*) The violence in Manipur has divided the communities into two, with Meiteis inhabiting the Imphal valley and the Kukis living in the surrounding hill areas.

Out of 243 violent incidents reported in the North-East States in 2023, 187 violent incidents were reported in Manipur. Manipur has suffered more than any State due to the recent inflation and economic woes in the country, and there was no action from the Centre for the restoration of peace and for a dialogue to help the displaced return to their homes. They are talking about the development of the North-East. But has the hon. Prime Minister gone to Manipur? This Manipur situation should not have been arisen. We have repeatedly said that the hon. Prime Minister should go to Manipur and visualise the position, but

unfortunately, five minutes? time has not been allocated by the hon. Prime Minister to go to Manipur itself.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री कल्याण बनर्जी: मैडम, मुझे बोलने का थोड़ा टाइम दीजिए । आप ऐसा क्यों कर रही हैं ।

Now, in such a situation, how much money has been allocated to Manipur? About Rs. 15 crore have been provided for temporary shelter; Rs. 35 crore have been provided towards housing and displaced people; Rs. 100 crore have been provided for relief operations; and Rs. 7 crore have been provided for compensation. It is such a little amount. How can it help the people of Manipur to develop? How will Manipur be developed with this little amount itself? ? (*Interruptions*)

Madam, as regards the population of Manipur, who are mostly affected in Manipur? The percentage of Scheduled Tribe population in Manipur is 40.9. The percentage of Scheduled Caste population in Manipur is 3.41. The Meitei population constitutes 41.39 per cent of the total population in Manipur. The Muslims constitute 41.29 per cent of the population in Manipur. Kuki-Chin-Mizo population in Manipur is 8.40 per cent. And other religions constitute 8.19 per cent. Why violence happened there? Who has suffered? The Scheduled Tribe people have suffered. The Scheduled Caste people have suffered. Poor people have suffered. ? (*Interruptions*)

Thousands and thousands of women have been raped in Manipur. Manipur has not got any justice from the hon. Prime Minister. Manipur needs justice. Justice has to be given to Manipur. Article 356 should not have been imposed in Manipur. And elections should be held immediately in Manipur. ? (*Interruptions*)

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । पिछले साल पूरा बजट नहीं हुआ था । केवल वोट ऑन अकाउंट हुआ था । वोट ऑन अकाउंट होने के बाद और चुनाव के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया । ? (व्यवधान) वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने के बाद 48.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया । सप्लीमेंटरी डिमांड्स का ड्राफ्ट पिछले सेशन में लाया गया था । अब फिर से सप्लीमेंटरी डिमांड्स लेकर आए हैं । ? (व्यवधान) चार-चार बार बजट पेश करने के बाद भी इनका जो नियोजन है, जो पूरे साल के लिए बनना है, वह आज भी इनसे सरलता से नहीं हो पा रहा है । अभी 48 लाख करोड़ के बजट में पौने सात लाख करोड़ रुपये का री-ऑर्गेनाइजेशन किया है । सवा छ: लाख करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया था, उसको खर्च नहीं कर पाए । अब उस पैसे को किसी और जगह खर्च करने के लिए इन्होंने यहां पर नया बजट हमारे सामने पेश किया है । ? (व्यवधान) ये पिछले बजट से 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने की मांग कर रहे थे । अब इन्होंने डिफिसिट के बारे में बताया है । स्किल डिफिसिट को कम कर दिया है । ये पिछले दरवाजे से 51,000 करोड़ रुपये वापस ला रहे हैं । यहां भी फिटनेस और अनिफिटनेस की बात हो रही है । अगर अनफिटनेस की बात हो रही तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि चार-चार बार बजट पेश करने का मौका मिलने के बावजूद भी अगर

माननीय वित्त मंत्री जी ठीक से आंकड़े पूरा नहीं कर पाती हैं तो शायद आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री और पूरे डिपार्टमेंट को अनफिट बना दिया है ।

यहां पर मैं जान-बूझकर कहना चाहता हूं कि पेंशन के लिए थोड़ा अधिक प्रावधान करने की कोशिश की गई है । लेकिन, लोगों की जो ईपीएस-95 की मांग है, उसके बारे में यहां कुछ नहीं बोला गया है । अगर आप अधिक पैसा चाहते हैं और लोगों को ज्यादा पैसा देना चाहते हैं तो ईपीएस-95 को इस बजट में लेकर क्यों नहीं आए?

महोदया, मैं मणिपुर के बारे में दो शब्द बोलूंगा । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । आप यहां पर मणिपुर का बजट क्यों पेश कर रहे हैं? वहां पर जो दंगे हो रहे हैं, वहां पर यह दिक्कत आ रही है कि दो समाजों के बीच झगड़ा लगाया गया है, जिसके कारण आज आपको वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है ।?(व्यवधान) यह हाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है । यह हाल पूरे देश का है, हर राज्य का है, हर जिले का है । हर जिले के हर कोने में झगड़ा लगाया जा रहा है । कहीं ओबीसी विरुद्ध एसटी, कहीं एसटी विरुद्ध ओबीसी, सब जगहों पर झगड़ा लगाया गया है । यह राजनैतिक फायदे के लिए जान-बूझकर किया जा रहा है । अगर इसको न रोका गया, तो वह दिन दूर नहीं, जब हमें यहां पर भारत के सभी राज्यों का बजट पारित करना पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करना पड़ेगा ।?(व्यवधान)

महोदया, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध है, आपने जो बजट पेश किया है, इसमें इतना पैसा बचा है, हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए कुछ पैसा देना अनिवार्य था, लेकिन वह पैसा नहीं दिया गया है । इसलिए मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूं कि कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें ।

? (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदया, आज मैं इस सदन में वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के लिए लेखानुदानों की मांगों तथा अनुदानों कि अनुपूरक मांगें 2024-25 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।?(व्यवधान)

आज बहुत से लोगों को यह पता चला होगा कि मणिपुर कहां है और पूर्वोत्तर राज्य कहां हैं । मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि आज मणिपुर के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है । मैं आज यहां बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों को ?अष्टलक्ष्मी? के नाम से जाना जाता है । मोदी साहब ने कहा है कि अगर पूर्वोत्तर राज्य डेवलेप नहीं होंगे, तो नॉर्थ-ईस्ट डेवलेप नहीं होगा ।?(व्यवधान)

इसलिए मोदी साहब ?अष्टलक्ष्मी? के नाम से पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलेप कर रहे हैं । आज दिल्ली से दीमापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है । दिल्ली से ईटानगर डायरेक्ट फ्लाइट है, इंफाल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, अगरतला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है और मिजोरम के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है । आज मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य एयरवेज़ से कनेक्टेड हैं, रेलवे से कनेक्टेड हैं, वाटर वे से कनेक्टेड हैं और हाइवेज़ से कनेक्टेड हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैंने अपने जीवन में पहले कभी पूर्वोत्तर राज्यों में टू लेन रोड्स नहीं देखी थी । आज हर राज्य की राजधानी फोर लेन सड़कों से जोड़ी जा रही हैं । यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है । कांग्रेस पार्टी के समय में पहले अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्री इश्यूज़ थे । मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ बाउंड्री इश्यूज़ होते थे ।?(व्यवधान)

आज मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की चेयरमैनशिप में सभी बाउंड्री इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं । आज पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो रहा है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल हो रही है, तो मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल हो रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना चाहिए ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में दीमापुर से इंफाल हाइवे, जिरीबाम से इंफाल हाइवे, इंफाल से मोरेह हाइवे, इंफाल से चुराचांदपुर हाइवे और इंफाल से उखरुल हाइवेज़ बन रहे हैं ।?(व्यवधान) वहां ट्राइबल का भी विकास हो रहा है, ओबीसी का भी विकास हो रहा है और माइनोरिटी का भी विकास हो रहा है । इसलिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों में सारी सुविधाएं दी गई हैं । इसलिए मैं आज इस बजट का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई जी ने कहा है कि वह नॉर्थ-ईस्ट में शांति लाना चाहते हैं । नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बोडोलैंड अंडरग्राउंड के साथ समझौता हुआ है, त्रिपुरा अंडरग्राउंड के साथ समझौता हुआ है, कार्बी आंगलोंग और वहां कई अन्य समझौते हुए हैं तथा कांग्रेस पार्टी ही नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में आर्म्ड फोर्सेज़ (स्पेशल पावर) एक्ट लाई थी । ?(व्यवधान)

19.15 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : पहले भाषण देते हो, फिर वैल में आते हो ।

? (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : मैं यह कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस शांति नहीं लाई, मोदी जी ही अष्टलक्ष्मी के कारण शांति लाए हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट्स पर जाइए । संबित पात्रा जी बोल रहे हैं ।

? (व्यवधान)

मान**नीय अध्यक्ष :** मैं संबित पात्रा जी को बुला रहा हूं ।

? (व्यवधान)

मान**नीय अध्यक्ष :** मैं संबित पात्रा जी को बुला रहा हूं ।

? (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : मैं आप सबके सामने यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में जब असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय पूरे नॉर्थ ईस्ट में अण्डरग्राउण्ड डेवलप

होता था, कांग्रेस राज में अण्डरग्राउण्ड गन पॉइंट से सरकार चलती थी, लेकिन आज असम में बीजेपी है और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों में शांति ही शांति है । ? (व्यवधान) आज मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर शांति लाई है तो बीजेपी ही लाई है, शांति लाए हैं तो नरेन्द्र मोदी जी ही लाए हैं । गौरव गोगोई गन पॉइंट, गन पॉइंट बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कांग्रेस के जमाने में होता था । आज बीजेपी के समय में पूरी शांति हो गई है । ? (व्यवधान) आज मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां कांग्रेस जितना भी चिल्लाए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों और मणिपुर को बर्बाद किया है तो कांग्रेस ने ही बर्बाद किया है । ? (व्यवधान)

*m134 **माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही ।

? (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : ऑनरेबल स्पीकर सर, एक मिनट । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर ऐसे टेबल बजाओगे तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी ।

? (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : मैं यह कहना चाहता हूं और आज मैं कांग्रेस को इतिहास को बताना चाहता हूं । ऑनरेबल सर, एक मिनट सुनिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

19.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty-Eight Minutes

past Nineteen of the Clock.

19.28 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twenty- Eight Minutes

past Nineteen of the Clock.

-

***m96 माननीय अध्यक्ष :** संबित पात्रा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, what is this ?बोलना चाहते हैं??

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर से ऐसे बात मत किया करो!

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको सुधारने का तरीका जानता हूं । आप चेयर से इस तरीके से बात मत किया करो ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको समझा दिया है कि आप चेयर से बात करने का तरीका सीखिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको सदन चलाना है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : अध्यक्ष जी, मैं सुबह से यहां सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रांट्स और मणिपुर के बजट पर भाषण सुन रहा हूं । हमारा धर्म और कर्तव्य है कि सुनना चाहिए । माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज ही नहीं कई बार इससे पहले हो चुका है, यह बात सदन में किसी से छुपी नहीं है । प्रधान मंत्री जी को बोलने भी नहीं दिया जाता है । यह बातें हमें आहत पहुंचाती हैं । अगर मैंने कोई शब्द ऐसा कहा है, जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो तो मुझे लगता है कि उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमेशा सिखाया है ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास । धन्यवाद । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदस्य, चाहे प्रतिपक्ष के हों, चाहे सत्तापक्ष के हों, हम संसद की मर्यादाओं को ध्यान में रखें । चाहे माननीय प्रधान मंत्री जी हों, चाहे एलओपी के नेता हों या मंत्रीगण हों अथवा कोई भी माननीय सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य, सदन के सदस्य होते हैं । हम प्रयास करें कि सहमति-असहमति, पक्ष-विपक्ष, तथ्यात्मक रूप से आरोप-प्रत्यारोप हमारे संसद की परंपरा रही है और संसद में समय-समय पर अपना पक्ष रखा भी है लेकिन, यह कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी और विशेष रूप से, मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि बैठे-बैठे कोई टिप्पणी न करे । बैठे-बैठे की गई टिप्पणी रिकॉर्ड में तो नहीं जाती है, लेकिन उससे सदन का वातावरण अच्छा नहीं रहता । आप बैठे-बैठे टिप्पणी करें, सदन के नेता जब बोलें, तब भी बैठे-बैठे टिप्पणी करें, यह भी उचित नहीं है । आपको जो बोलना है, आपका समय आने पर बोलें । पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं बोल रहा हूं ।

वेणुगोपाल जी, एक अच्छी परंपरा का पालन कर लें, तो ठीक रहेगा, सदन ठीक से चलेगा । जो भी समस्या हुई, सदन में उन्होंने जो-कुछ भी बोला, उन्होंने वह विषय वापस लिया । कल धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ विषय ध्यान में आया, तो उन्होंने उस विषय को वापस लिया । यही परंपरा रही है ।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Hon. Speaker Sir, I agree with whatever you are saying. However, making personal allegations and attacking anyone personally, whether it is the Prime Minister or the Leader of the Opposition, is not appropriate. But you see in this House, some Members continuously getting the chance to speak during ?Zero Hour? and attacking the Leader of the Opposition. We have been raising that issue every time. When you are in the Chair, sometimes you control the situation. But if you are not in Chair, I think,? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन से यही अपेक्षा करता हूं और इसी भावना से सदन चले कि हम कभी भी आरोप-प्रत्यारोप लगाते समय तथ्यात्मक रूप से चीजों को बोलें, अन्यथा प्रयास करें कि सदन की जो भाषा रही है, जो पुरानी परम्परा रही है, परिपाटी रही है, अच्छी मर्यादा रही है, इस सदन के अंदर हम उस मर्यादा-परिपाटियों को बनाए रखें, यह मेरी आप सभी से अपेक्षा है ।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष जी, आपने रूलिंग दी और सबको एडवाइज़ भी किया । वेणुगोपाल जी ने भी प्रतिक्रिया दी । मैंने कल भी इस बात को बोला था कि लोकतंत्र में कभी-कभी गर्मा-गर्म बहस हो जाती है, लेकिन मर्यादा आपने तय की है । सदन में सभी मिलकर रूल को मानते भी हैं, लेकिन बीच-बीच में चेयर की ओर सीधे अंगुली उठाकर आप कहें कि आप बायस्ड हैं, इस तरह का अटैक जब आप करते हैं, तो सदन की मर्यादा पर बहुत बड़ी चोट लगती है । अत: एक-दूसरे के प्रति भी हम लोग इंडीवीजुअल अटैक न करें, विशेष रूप से चेयर पर अटैक न करें, यह मेरी विनती है ।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, when the House is not in order, we used to see the Parliamentary Affairs Minister reaching out to all the Parties to have a consensus. But I am sorry to say that this House is lacking that. They are attacking personally. You can see the words they have been using against Shri Rahul Gandhi ? (*Interruptions*) You are talking about the Prime Minister also. We are not attacking anybody personally, including the Prime Minister. But whenever the Treasury Benches speak, there is no limit at all. ? (*Interruptions*) Sambit ji is quoting about an issue which is not an issue now. We stated that the Congress Party's stance is very much in support of the Indian cricket team, regardless of who the captain is. When you moved the resolution also, we were very happy with that. But it is a political issue, and taking the name of the Leader of Opposition is not appropriate. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, जब बात चली तो कई सदस्यों ने बहुत गंभीर टिप्पणियां कीं । यहां तक टिप्पणियां कीं, जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए । मैंने उनको एक्सपंज कर दिया, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी पर, माननीय राष्ट्रपति जी पर टिप्पणी, इस हेतु सदन को कुछ न कुछ मर्यादा बनाए रखनी चाहिए ।

हमें सदस्यों को समझाना चाहिए कि वे सदन के नेता है या सदन का कोई भी माननीय सदस्य हो, सभी माननीय सदस्यों के द्वारा बोलते समय व्यक्तिश: रूप से टिप्पणी करना और व्यक्तिश: रूप से कुछ चीजों के बारे में कहना, इस पर हमें ही गरिमा बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए ।

19.35 hrs

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir. Today, after six hours of discussion, we are dealing with four Bills which were presented by me with your permission. This is the Second and the Final Batch of Supplementary Demand for Grants. Normally, Governments are allowed to bring in up to three but we have made it a self-imposed rule that we do not go beyond two. So, this is the Second and the Final Batch of Supplementary Demand for Grants for 2024-2025.

One of them is the Excess Demands for Grants for 2021-22 of the Union Government. The third is the Budget of Manipur 2025-26, and the fourth is the Supplementary Demands for Grants for 2024-25 of Manipur. The Budget for Manipur, which is for 2025-26, is more of a Vote on Account. We are seeking time for about six months. These are the four which we are taking up for discussion.

A lot of Members have participated in the discussion. I will highlight the top features of each one of them. The Second Supplementary Demand for Grants has 52 Demands and three Appropriations.

माननीय अध्यक्ष : अगर सदन की इजाज़त हो तो मैं गोली ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ, सर ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The three Appropriations pertain to the Supreme Court of India, Repayment of Debt and also the Department of Space. I am not getting into the details, although I felt it might be useful for me to talk what the technical supplementary is, what the token supplementary is and also what the cash supplementary is. I am not getting into the details because many Members are fairly seized of these details.

The authorization for the Second and the Final Batch of Supplementary Demand for Grants is being sought for gross additional expenditure of about Rs.6.79 lakh crore. I know, the hon. Member, Shri N.K. Premachandran ji has raised a question on it. I will answer it duly in time.

The net cash outgo on the Cash Supplementary is about Rs.51,463 crore. The Technical Supplementary is the one on which there was a specific question from the hon. Member, Shri N.K. Premachandran ji. It is about Rs.6,27,045 crore. These are not new ones. They are matched by savings in various different sections within the same grants and also recoveries. Therefore, they are not new. But they are only moving from one to another as a token supplementary of Rs.67 lakh.

There is also a recoupment of Contingency Fund advance which is of Rs.19,765 crore. So far as Cash Supplementary is concerned, I will just highlight one or two of them. I do not want to go into each one of them. The most important thing is the one which is given for fertilisers which is Rs.14,100 crore. That is for urea, P&K fertiliser, subsidy and so on, and also pensions of the civil nature.

We have arranged for a pre-funding of the Unified Pension Scheme Fund of Rs. 7,000 crore because it is going to be effective from 1st April, 2025. However, even in this year, we have made a provision to start with some money in hand. Pensions take up a major chunk, along with other expenditures.

One other point I would like to highlight is that we have fiscally restored the public finance of J&K. I am very happy to say during the last three to four years, we have spent a lot of time cleaning up the J&K finances. Several committed expenditures that were laying a heavy burden on the States have been taken over, and we have also paid and cleared them. This is a point I would humbly like to place before this House because the fiscal deficit to GSDP of J&K was over 12 per cent. That has now been brought down to three per cent in the last four years. We have made sure that wherever there are huge arrears, we would fund them to clear the arrears so that the State is not in a difficult position when the elected Government comes into place. Much before the elected Government came into place, we ensured that the fiscal deficit was brought down to three per cent, adequately taking care of many other payments and so on. Even now, I would definitely say that we will continuously support J&K to make sure the UT Government focuses on development-related activities and prioritizes them because we are here to support them if the State needs a lot of development activities.

Without going into many other details, there is one point I did not think I should emphasize, but I will place it before you, Sir. The Department of Agriculture and Farmers? Welfare receives Rs. 2,186 crore. This is an enhancement of an outlay for the PM Kisan, and also the BE of forthcoming year 2025-26 is kept in mind with this enhancement taken on board. This is not an enhancement that we have given and forgotten, only to revert the BE to last year?s level. This enhancement is inclusive of what our calculation for BE for the next year is.

Without taking much time detailing the technical supplementary, Sir, there is only one point on the technical supplementary that I would like to highlight ? repayment of debt. This is a point on which I have heard quite a few hon. Members speak about the debt to GDP of the Government. Is there any measure being taken to take care of the debt burden? It is necessary for us to understand that this Supplementary Demands for Grants in the technical supplementary gives a big role for Rs. 5,54,349 crore which somewhat answers N. K. Premachandran ji, but I will discuss it in detail a bit later. That Rs. 5,54,349 crore goes for repayment of debt, repayments of 14-day treasury bills because we cannot estimate how much the States would keep in the treasury bills, so approximately it is Rs. 4 lakh crore. The 91-day treasury bills amount to Rs. 70,745 crore, but what is more important is the advanced redemption of high-cost loans and the buyback of the G-secs, which amount to Rs. 85,159 crore. Essentially, we are removing the high-cost debt from our shoulders through advanced redemption of those debts. The payment for high-cost loans has already occurred. I am glad to say to this House ? I am sure many Members would have noticed ? due to this redemption, the borrowing rates for the Government have all come down. It can be noticed that if market borrowings were to be taken care of, the Government of India borrowings have

come down, and I am sure as a result, when States go to the market to raise their bonds, their rates will also be significantly lower. It is a constant endeavour to ensure that we do not have excess demand, which is the next topic coming for discussion ? the Excess Demands for Grants, which is for fertilizers and pensions, two appropriations namely for the Defence Ministry (Civil), which is a charge section, and also for the Ministry of Railways.

So, the Excess Demand for Grants for 2021-2022 is Rs. 1,291 crore, but I repeat that there is a constant endeavour that we do not go on with Excess Demands. We will ensure that we do not have too many Excess Demands happening because frequently we are looking and reviewing at cutting down.

The third one is the Manipur Budget. The total receipts for the Manipur Budget are Rs. 35,368 crore and revenue receipts are Rs. 27,231 crore. The State?s own tax is about Rs. 2,634 crore and non-tax revenue is about Rs. 400 crore. They are the receipts. The total expenditure has been estimated at Rs. 35,104 crore, the revenue expenditure is Rs. 21,512 crore and capital expenditure is Rs. 7,773 crore. A receipt of Rs. 1,300 crore is projected under the special assistance for States, which is the 50-year interest free amount that we give as a loan, but essentially eventually it is going to be a grant and that is for the year 2025-2026.

So, as I said before, it is a Vote on Account for six months at this stage for an amount of Rs. 17,947 crore. Here too, similar to the way in which we have helped J&K, we are providing all the financial assistance to support a faster recovery of the economy for Manipur. This is something that I would like to put for consideration of all Members. We will continuously support so that the recovery is faster.

The Supplementary Demand for Grants for 2024-2025 of Manipur is also on the Table here and the Supplementary Demand for Grants for 2024-2025 is an amount of Rs. 1,861 crore. It covers 20 Demands and one Appropriation. Rs. 948 crore are being sought for revenue expenditure and Rs. 913 crore are for the capital expenditure.

One good thing that has already been done for the Manipur finance management is that they never had a Contingency Fund till now. Now, when we are coming up with this Vote on Account and a Supplementary Demand for 2024-2025, a Rs. 500 crore corpus is being given so that they will have a Contingency Fund from now kept every year. If necessary, more can be added to it, but we have now brought in that system which did not exist earlier.

Other than this, there were very many discussion points, which were on the general discussion of the Union Budget and not specific to these four that are on the Table today. So, beyond the Supplementary Demand or the Vote on Account for Manipur, on the content of

the Budget itself there is not much more I need to add. But I will go to the specific issues, which some hon. Members have raised here.

I was here when I heard Member Gogoi speak about GST. I am going into the details of some of the Budget related issues and not so directly related issues to the Budget. On the GST on temple matters, this has also been answered in several Questions in the Parliament. GST is exempted completely for supply of ?prasad? in the temple, and if there are religious ceremonies which are being conducted, even they are totally exempt. Renting out precincts of a religious place meant for general public owned and managed by entities registered as charitable or religious trust under Income Tax Act are also completely exempt.

Services by any entity registered under the Sections 12AA and 12AB of the Income Tax Act by way of charitable activities, be it with the temple or related to temple or otherwise are also completely exempt.

I want the hon. Member, Gogoi Ji, to recognize that GST or Income Tax has been completely exempted for temple-related activities, and here the credit goes to all the Finance Ministers who are seated in the GST Council, in which Finance Ministers belong to different parties. It is not just the Union Government which is seated in the GST Council. So, when we talk about GST, it is equally a contribution which every Finance Minister coming from every State of this country is contributing to. And in GST Council, I would like to say that 99.9 times, every decision taken there is unanimous. Therefore, it is not the case that a decision for the temple is supported by only BJP and opposed by all others. No, that is not the case. It is clearly looking at the category, revenue position, and revenue foregone, and that which is for public cause, the Council takes support. So, I would say, when it comes to GST, please remember, it is not just the Finance Minister of the country, not just the BJP Finance Ministers; everybody is in the GST Council, as much a concern that you have on GST when you talk to me.

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ देर पहले मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would like to inform through you, Sir, that I have no objections to people raising questions about GST.

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा करता हूं कि वे बैठे-बैठे किसी भी सदस्य का जवाब नहीं दें ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सर, आप बार-बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं ।

माननीय अध्यक्ष : सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the second issue is not related to the four budgets and supplementary demand for grants, but since the matter was raised and it is my duty to answer, I will answer that.

Regarding the concern which hon. MP, Gogoi ji, raised on defence-related matters, he said, ?do not look at defence from accounting and audit only?. This point is very well taken, but I find it difficult to accept that a senior Member of Parliament from the Congress Party has said this to me, and I will take it in its spirit. It might be relevant now for me to recall under three different headings. One is, policy inertia and procurement paralysis. So, policy inertia and procurement paralysis made a former Defence Minister say in February 2014 ? I am not taking any names ? ?there is no money left; all major projects have to wait till 1st April?. Several Aprils had passed before 2014, nothing was procured. At that time, it was said, ?There is no fund; because of shortage of funds, I cannot procure anything?. That was the state of affairs then.

The second point is about delays in procurement. It is the second category I want to highlight. The Army had requested 1.86 lakh bulletproof jackets in 2009. The UPA Government never delivered, leaving soldiers vulnerable. The second time in 2012, the Army Chief at that time warned of alarming ammunition shortages and obsolete air defence systems. The UPA Government failed to give anything. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Procurement delays exist today also.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am answering that. I will tell you what we have procured, so that you can compare and contrast. The third incidence was that the Scorpene Submarine Project of 2005 was delayed extensively with zero deliveries by 2014 for 10 years.

Navy?s operational submarine fleet had shrunk from 16 to 13 by 2015. It is 2014 again. Ammunition reserves were critically low and the statement by the armed forces was that it is insufficient for even a 10-day intensive war scenario. ? (*Interruptions*) I am giving the data so that it can be compared. ? (*Interruptions*) Compare and say the same thing. ? (*Interruptions*) Hon. Speaker, Sir, I am speaking because you called my name.? (*Interruptions*) I sought the permission to stand and speak. In 2014, the ammunition thing is over. It was because of indecision and also the way in which the procurement could not be done because of finances. Then there were scams during UPA era. Now I want to contrast. I will give the data so that it can be compared. What was the number of scams? AgustaWestland, Tatra trucks, Ordnance Factory Board scam 2008-09, Rolls Royce engine scam ? all this was happening and there was a freeze. Nothing could be bought or procured by the Government. But even with the freeze, scams were happening. You were not procuring, but the scams were

happening. Money was going to whom? From that level of indecisiveness for them to compare, I am giving the details.

SHRI GAURAV GOGOI: Where is Lalit Modi? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: When did he run? Under their regime, there was so much indecisiveness and import dependence. And, under Prime Minister Modi?s leadership, we have now got defence products being exported to over 85 countries with over 100 companies actively contributing to this growth. India?s defence exports have achieved milestones, increased 30 times over what was it in 2013-14 that is, Rs.686 crore. Today, in 2023-24, it has touched Rs.21,083 crore of exports. So, when we are talking about Defence, we are not looking at it as just audit and accounting, but actual progress is happening under Prime Minister?s leadership.

Hon. Member Shri Alfred Kanngam S. Arthur felt that Manipur?s Budget which is normally bifurcated between hill and valley allocations as per a particular order which was issued in 1972, is not kept this time. I would like to inform the hon. Member that the bifurcation is intact. What was issued in 1972 is being followed even now. The documents prepared in this Budget also have this bifurcation. If I can draw his attention, the e-budget portal of the State Government where the Budget documents were uploaded on 10th March 2025, has detailed Demands for Grants with this bifurcation intact. So, I would just want to give a clarification on that.

The other question is about the steps which have been taken for Manipur to restore normalcy. With the collective effort of both the Central and State Governments, there has been an improvement in the law and order situation in the State to a large extent, except for some sporadic incidents in the fringe areas and the incident of the 8th of March 2025 in Kangkokpi.

<u>20.00 hrs</u>

There has been a decreasing trend in the deaths, injuries, arsons, firing and so on. Currently, 286 companies of CAPF, 137 columns of Army and Assam Rifles are together deployed with the Manipur State Police to maintain law and order.

Also, recovery of arms and ammunition looted are underway. Recovery is underway. So, following a public notice, which was issued by the Governor on 20th February 2025, the recovery has seen an increase.

There is a free movement along the national highways. Convoy movement of essential commodities that are being carried out are continuing, and that will ensure availability of essential commodities in the State. Helicopter service has also resumed so that most district headquarters are connected for ease of travel for the public.

Sir, because of violence of the displaced persons who are now living in relief camp, about 60,000 persons are currently residing in relief camps, about 7,000 persons have returned to their homes.

An amount of Rs. 400 crore have been provided under the MHA's special package for relief camp operations and to support those who are affected, and more support will be continuously provided. I did hear one of the Members saying, `have you given anything for it?? So, this is the amount which I want to mention.

Under the PM Awas Yojana (Gramin), 7,000 houses have been approved very recently to provide housing to those who are displaced. So, various other supports have also been given to the relief camps, such as healthcare, including mental health support, skill and livelihood training and also for education. The administration is involved in talking with people and helping them to get their priorities served.

Priority is also given for release of funds from the Centre for Centrally- sponsored schemes. So, the major and critical projects that are being monitored and reviewed regularly for timely completion include tying up of required funds, such as for the national highway projects, railway projects, civil Secretariat, Churachandpur Medical College, Manipur water supply project, IIIT at Mayangkhang, Government Residential Accommodation. For all these things, on a priority, the monies are being released.

I now come to the specific question of Shri N.K. Premchandran, who said technical Supplementary over Rs. 6 lakh crore is very huge. I answered it earlier, but I want to go into the details. Rs. 5.5 lakh crore pertains to a single appropriation, that is, repayment of debts. Within the repayment of debt, Rs. 4 lakh crore of technical supplementary has been sought for the States to facilitate the deposit into and withdrawal of 14 days' T-bills. The Central Government is helping the States and providing a platform for short-term investment, which can be withdrawn by the States on a need basis. Second, for prudent fiscal management, about 85,000 crore of Government securities were bought back, and about 99,000 crore redemption of 91 days' T-bills, that is, the advance payment of costly, expensive loans. When the Government engages in active debt management, which is a dynamic process by very nature and is aiming at reducing the cost of borrowing for both the Union and the States, the Government needs to have requisite flexibility to attain that objective.

Then, hon. Member Arun Nehru ji ? I can see him here also ? has raised questions about several accomplishments of Tamil Nadu. He has mentioned about debt to GSDP of the State being lower than that of the Union Government, and women?s participation in labour force higher than the national average. He also says about the higher enrolment ratio. Let me upfront say that we are very proud of the achievements which Tamil Nadu has made. My birth has happened in that State. My younger days, my student days, my family ? everything belongs to Tamil Nadu. We are from there. I am very proud of all the achievements. There is no hesitation in admitting that. But in the context of the debt, to compare a State?s debt

with the Centre?s debt may not be appropriate. I would like to draw the attention of the hon. Member because the debt to GSDP of Tamil Nadu is for the State and only for the State, while the debt to GDP of the Union Government is for the country as a whole including exclusive subjects which have no bearing on the States such as Defence, Railways, communication and foreign affairs. They are exclusive to the Centre, and they have also got to be managed. So, the Union Government works together with all the States. ? (*Interruptions*)

I want to highlight the projects that have been taken up for Tamil Nadu. On 19th June, 2024, the Union Cabinet approved Viability Gap Funding for the schemes for implementation of offshore wind energy projects. They are only in two States, namely, Gujarat and Tamil Nadu. The total amount put together for both the States is Rs.7,453 crore.

Second is the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor which has six nodes, namely, Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore, Salem, and Hosur. It was inaugurated in 2019. I am not talking about private separately, but private also put together. If you were to get some figure, Rs.3,123 crore, even during the inauguration of the Corridor was invested. On 2nd July, 2024, the Ministry of Defence signed MoUs under the Defence Testing Infrastructure Scheme to set up testing facilities in unmanned aerial systems, electronic warfare and electro-optics domains in the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor. That is from the Central Government.

Thirdly, PM MITRA Mega Textile Park in Virudhunagar is one of the seven under the PM Mega Integrated Textile Region and Apparel scheme. So, if all over the country there are seven, one is in Tamil Nadu.

Fourthly, in 2022, the PM virtually inaugurated 11 new Government medical colleges in Tamil Nadu. The new colleges are in Ariyalur, Dindigul, Kallakurichi, Krishnagiri, Nagapattinam, Namakkal, Ramanathapuram, the Nilgiris, Tiruppur, Tiruvallur and Virudhunagar. All of them put together will have an intake of 1,450 M.B.B.S. students annually. ? (*Interruptions*)

Sir, now, I come to the fifth point. Tamil Nadu was one of the four States selected under the Promotion of Medical Device Parks Scheme, with a final approval for financial assistance of Rs. 100 crore, which is given. So, that is about some of the investments.

I will come to the specifics of Railways. Between 2014 and 2024, what are the ones which are commissioned? Sir, 1,302 kilometres of new tracks are there only in Tamil Nadu. Sir, 2,152 kilometres of electrification have been done - 215 kilometres per annum, that is, three times of 75 kilometres, which was during 2009 and 2014. In 2009 and 2014, they did only 75 kilometres annually. But what is being done under Prime Minister Modi is 215 kilometres annually. Sir, 687 rail flyovers and underbridges have also been constructed. So, this is just a crisp account of railways.

Now, let us go to metros. On October 3rd, 2024, the Chennai Metro Rail Project Phase-II was approved by the Union Government as a Central sector project, which is 65 per cent of the fund of Rs. 63,246 crore. Sir, Rs. 63,246 crore are the total; of that, 65 per cent will be financed by the Central Government. Then, it will comprise of three corridors -- Madhavaram to SIPCOT, Lighthouse to Poonamallee Bypass, and Madhavaram to Sholinganallur sections.

माननीय अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी, आप तमिलनाडु का इतना विकास बता देंगी, तो अन्य राज्य भी आपसे मांग करने लग जाएंगे ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Now, I come to roadways. Sir, 4,100 kilometres of national highways have been constructed in Tamil Nadu since 2014. ? (*Interruptions*)

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Madam, that has not been fully given to us.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sure. It would not be denied. It will be given.

Now, I come to roadways. Sir, 4,100 kilometres of national highways have been constructed in Tamil Nadu since 2014. Greenfield corridors are being built under the Bharatmala Project -- Bengaluru-Chennai Expressway; Chennai-Salem Corridor; Chittoor-Thatchur Corridor; Bengaluru Ring Road, which also has an impact; and Bengaluru-Kadapa-Vijayawada Corridor. So, a development of 2,414 kilometres of national highway corridors with a tentative capital cost of Rs. 81,131 crore is approved in Tamil Nadu under Phase-I of Bharatmala Pariyojana.

I now move to airways. Airports have been operationalised under the Regional Connectivity Scheme ? UDAN. Salem was included in UDAN scheme in 2018. Airports are also planned to be operationalised in Neyveli and Vellore. Coimbatore and Tiruchirappalli airports are covered under Krishi Udan Scheme to assist farmers in transporting agriculture products.

The Prime Minister inaugurated the new Integrated Terminal Building Phase-I of Chennai International Airport. It was developed at the cost of Rs. 1,260 crore. So, addition of the new Integrated Terminal Building will increase the passenger-serving capacity of the airports from 23 million passengers per annum to 30 million passengers per annum. And then, in every one of these new terminals, which is getting built, there is a striking reflection of Tamil culture in terms of Kolam, in terms of sarees, and in terms of temples. With all those elements, those airport terminals are being constructed.

There are others which I will just briefly point out. The renovation and modernisation of Grand Anicut Canal System, which is a very old one ? Kallanai in Tamil ? is underway. It is an important source of irrigation for the entire delta districts, which are considered to be the rice bowl.

The modernisation of this canal is taken at the cost of Rs. 2640 crore. On 4th March, 2024, the Prime Minister witnessed the initiation of core loading of India?s indigenous prototype fast breeder nuclear reactor of 500 MW capacity at Kalpakkam in Tamil Nadu.

Also, Sir, the PM inaugurated in February, 2024 and laid the foundation stone of a multiple development project worth Rs. 17,300 crore at Thoothukkudi in Tamil Nadu and that includes foundation stone of the outer harbour container terminal and the other projects aimed at making V. O. Chidambaranar Port as India?s first green hydrogen hub port, that is India?s first green hydrogen hub port in Tamil Nadu.

On 25th February, 2024, PM Modi dedicated new composite TB research facility at Tiruvallur in Tamil Nadu, FSSAI Microbiology lab at Coimbatore, and the National Centre for Aging in Chennai. All this is for Tamil Nadu.

Hon. Member Arun Nehru Ji, please take this. I mention this on your observation about Tamil Nadu and how much is being given for Tamil Nadu.

I would also like to recollect about this worry that debt of Tamil Nadu is far lesser than the debt of India. I have already mentioned as to why comparing one State cannot be applicable for the rest of the States. But we have already said because of COVID the debt to GDP went to the level of 61 per cent of GDP. We have already brought it down to 57 per cent and in my Budget speech, we have said by 2030, as per the recommendation of one of the Committees which went into it, we will bring the debt to GDP to 50 plus or minus one by 2030, that is 50 per cent of the GDP. So, it is already a commitment. We are working towards it. So, the concern that the hon. Member has about the debt of the Union Government comparing that with the debt of one State will have to be put in this perspective.

And third is regarding high level of women participation in the workforce and diverse employment opportunities. At the same time, I would like to appreciate, for the States? work, as much as I put on the Table a point on which all of us will have to introspect. We will have to introspect. We cannot, on the one hand, say a State is developed. We are giving opportunities for employment. This is the kind of industrialisation happening but equally, they give us an increasing number of MNREGA demands. If actually that is available, why would MNREGA increase? The increase does not happen even in States which are not as industrialized, as growing, as forward developing, as Tamil Nadu. So, I would want to keep that in the discussion mode. ? (*Interruptions*)

Now, I will be taking the milestone elsewhere. So, the kind of well-wishing, goodwill thinking, that we said, we will hear speeches, we will ask questions, we will respect the institutions, does not apply. It is only during the time of the speech we will say that and after that, we will continue doing what it is. That is not how it works. You raised issues. We will answer questions. When we speak, please have the strength to listen. You may deny me. You may argue with me. You may question me but you should have the patience to listen.

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, you also have to practise it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, sure. We will certainly practise. Do you think we will ignore your suggestion? We will not. But I would like to be seeing that.

So, what does that indicate?

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Madam, tell us about the rest of the States.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming one by one.

So, Sir, we need to have a debate and understand that it cannot be going both ways. The same argument cannot serve two opposite causes. We need to introspect. We want all the States to develop, goodwill and courtesies be extended. About appreciation on the Table, I have no hesitation.

But we cannot contradict ourselves. Sir, another point which the hon. Member raised about the enrolment, an increasing enrolment, is very good. Let it be so; let it be even better. My good wishes for it. But, Sir, the ASER report, which was brought out in 2024, released on January 25th, pertains to 2024. That Report assessed the children?s proficiency in reading, arithmetic, and digital literacy across India.

Unfortunately, Sir, Tamil Nadu was one of the weakest performers before and after the pandemic. I am not saying this with a sense of, ?ha ha, look at it.? I feel absolutely disheartened. I do not want to say it, but I need to answer the hon. Member. So, I will quote this. It is not my report. It is a report prepared by an organisation called Pratham. It is not me. So, what did the report say? Class 3 reading levels show that 8.6 per cent of the students cannot even read letters; 18.2 per cent students can read letters but not words; 36.3 per cent students can read words, but only of class 1 standard. * Class 3 student can only read at the level of Class 1.* Only 12 per cent students can read at a class 2 level. Therefore, a class 3 student is only reading at a class 2 level. A student can reach to class 3 but he can only read at class 1 ? (*Interruptions*) Now, is this educational outcome important or not? Or, are we looking at only enrolment? ? (*Interruptions*) The hon. Member who spoke about enrolment being very high should also answer what the outcome is. It cannot be a propaganda, and substance should come into the discussion. This is very important,

I come to the point raised by an hon. Member whom I cannot see here. Shri Kirti Azad spoke about various items. He felt that the BJP claimed that by 2022 we will provide houses for everybody. We are definitely providing houses for everybody in every State as well. But I would like to put before you the scams at an all-India level performance. The teachers? recruitment scam is something on which honest job seekers and vulnerable students, who were enrolled in schools, need to have someone look into that as well. If Shri Kirti Azad Ja is talking about scams, he should look at this teachers? recruitment scam as well.

Similarly, there are Rs.10,000 plus crores in PDS scams which affect the poorest of the poor. On this, I wish Shir Azad looked at and talked about how scams are predominating in

West Bengal. A Rs.100 crore Mid-Day Meal fraud has happened in West Bengal. So, Shri Azad should look at that. He should raise questions in West Bengal about it.

According to the CAG report, from March 2021, financial misappropriation and malpractices worth nearly Rs. 2 lakh crore by the West Bengal Government were detected by the CAG.

माननीय अध्यक्ष: अगर आप कोई विषय उठाएंगे तो माननीय मंत्री जी जवाब भी देंगी । अगर तमिलनाडु वालों ने विषय उठाया तो मंत्री जी उनको जवाब दे रही है । गुजरात वालों ने विषय उठाया है तो मंत्री जी उनको जवाब देंगी । जो विषय उठाएंगे, उन्हीं को मंत्री जी जवाब देंगी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी उन्हीं का जवाब दे रही हैं, जिन्होंने विषय उठाया है । जिस राज्य ने विषय उठाया है, मंत्री जी उसी का जवाब दे रही हैं ।

मंत्री जी, आप जवाब दीजिए । अगर तमिलनाडु वाले ने विषय उठाया है तो उनको मंत्री जी जवाब देंगी । बंगाल वालों ने उठाया है तो मंत्री जी उनको जवाब देंगी । आप बंगाल वाले को भी सुनाइए ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: About West Bengal, I have said as to how cut money has been a problem.

The Chief Minister of West Bengal herself asked all the representatives of her party about the cut money that has been taken. She said: ?Let the cut money be returned.? ?(*Interruptions*) The Chief Minister herself said: ?Can we have the cut money returned? ?(*Interruptions*)

Sir, therefore, what I want to say here is that if the hon. Member mocks us for not delivering on our promise, I want to say what we have delivered. This is our Government?s achievement. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 54 crore Jan Dhan bank accounts have been opened. I want Kirti Azadji to please recognise this, and also recognise the C&AG report which talks about scams in West Bengal. Under the PM Awas Yojana, four crore houses have been constructed for the poor. Under the Swachh Bharat Abhiyan, 12 crore household toilets have been built.

<u>20.25 hrs</u>

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.

*m161 **माननीय अध्यक्ष :** आप बंगाल वाला जवाब पूरा कर दीजिए । वे जाने वाले हैं ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, they have gone away. सच बोलने में कड़वा लगता है । उसको सुनने के लिए बैठने का आत्मविश्वास चाहिए, जो उनके पास नहीं है । मैं एक्चुअली डीएमके के मेंबर्स को इनवाइट करती हूं, कांग्रेस के मेंबर्स को भी इनवाइट करती हूं, क्योंकि एकाध विषय अभी बाकी हैं । मुझे उनके बारे में बोलना है ।

Under the Saubhagya Yojana, 21 crore rural households have been electrified. Under the Jal Jeevan Mission, over 12 crore households have been provided with tap water

connection. Similarly, under the PM Ujjwala Yojana, 10.3 crore LPG connections have been provided. Under the Ayushman Bharat, 36 crore people have got health insurance cover of Rs. 5 lakh.

The State of West Bengal, of course, has denied giving Ayushman Bharat to its own people. तृणमूल नाम है, मगर जो छोटे-छोटे ग्राउंड में लोग हैं, उनके लिए कोई फायदेमंद काम ये लोग नहीं करते हैं । पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम विदड्रॉन, जल-जीवन मिशन में बहुत स्लो प्रोग्रेस है । In West Bengal, the Ayushman Bharat Scheme has been withdrawn. Under the Jal Jeevan Mission, there is a very slow progress. Under the PM Ujjwala Yojana, a lot of applications are lying in wait due to delay in formation of the District PM Ujjwala Committees for LPG connections. There is high pendency. There is corruption and misgovernance in PM Awas Yojana. There is corruption and nepotism on West Bengal Government's Bangla Awas Yojana. The State Government of West Bengal refused to participate in the Aspirational Districts Program. There are forced delays in critical infrastructure. Only 21 per cent of the land required by the Indian railways has been procured. Rest of the procurement has not been done.

The Metro projects are also being delayed. Four of the five Metro projects are still under construction. स्टेट गवर्नमेंट में इतने सारे डिलेज़, ओमिशन्स एंड कमीशन्स एक तरफ और दूसरी तरफ इतने सारे स्कैम्स हैं । So, Kirti Azadji should probably look into that rather than talk about: ?I am the Vibhishana, I have been sent out of BJP.? Actually, Sir, I don't know in what context he said. श्रीराम विभीषण को भाई मानते थे । लंका में रावण को हराने के बाद विभीषण को ही श्रीलंका का राजा बनाया । He did not say: ?I will rule from Ayodhya.? उनको उधर राजा बनाकर आए थे । इनकी विभीषण की समझ पता नहीं क्या है, उनकी स्टेटमेंट पता नहीं क्या है, किसने किसको बाहर हटाया? राम ने उनको भाई माना । इसलिए उनको रामायण थोड़ा ठीक से पढ़ना चाहिए ।

सर, केरल के बारे में भी बात कही गई । मैं एकाध विषय और कहना चाहती हूं और लास्ट दो पॉइंट्स में अपनी बात कहना चाहती हूं । पलक्कड इंडस्ट्रियल नोड का अप्रूवल हुआ है, कन्नूर एयरपोर्ट आरसीएस उड़ान के तहत आपरेशनलाइज्ड हुआ है । Site clearance for Greenfield Airport in Kottayam has also happened. India's first Water Metro was inaugurated by Prime Minister Modi in April 2023. Kochi Metro was also inaugurated by the Prime Minister in 2017. रेलवेज़ के बजट में 3,000 करोड़ रुपये केरल के लिए दिए गए हैं । Two Vande Bharat trains have also been started. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे हैं । अगर वे इधर होते, तो बात कर सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय, यह विषय थोड़ा सेन्सेटिव है, मैं जरूर पार्लियामेंट के रिकार्ड में इस विषय को रखना चाहती हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आपको जितनी देर अपनी बात रखनी है, उतनी देर अपनी बात रखिए ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष महोदय,सु**.** वेंकटेशन ने बताया that ?India? is not ?Hindia?. काशी तमिल संगम को प्रायोराइटाइज करके उसके लिए बहुत सारे पैसे देते हैं, हमें नहीं देते हैं । यह भी कहा कि हम जो एक रुपया देते हैं, 29 पैसा ही वापस मिलता है । जब मैंने रिप्लाई दिया, अरूण नेहरू जी ने लिस्ट आउट किया कि तमिलनाडु के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, पैसे की गिनती हो रही है कि नहीं । If they want to say that for every rupee that they have given, you are giving only 29 paisa, मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट

और मेंबर से पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ कोयम्बटूर और चेन्नई के ऊपर ही खर्च करेंगे क्योंकि रेवेन्यू उधर से ही आता है । पेरम्बलुर, कोविलपट्टी, शिवकाशी, रामनाथपुरम, तिरुवनन्तपुरम, इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा तो नहीं देना चाहिए । जहां कलैक्शन हो रहा है, उसके ऊपर ही खर्च करना है, क्योंकि एक रुपये का हम 29 पैसा ही दे रहे हैं ।

People in Coimbatore will ask for spending on them. People of Chennai will ask for spending for them. Where will Perambalur people go? Where will Kovilpatti people go? Where the spending will come from for them. They should ask question after giving a thought about its rationality. The way of questing by him is wrong. He should not ask questions like this? Another aspect is he asked about the blocking of Ananta Vikatan?s Cartoon. I want to say to him that today morning when Mr Gogoi was speaking in this House. He told that we should respect our Prime Minister and everyone should be referred with respect and dignity.

We should respect the Prime Minister; we should respect every institution; and we should talk like that. He said that. But that cartoon from that magazine shows the Prime Minister with his hands in cuffs and feet in chains because they want to say that America sent our students like that. So, with Trump sitting there and the Prime Minister sitting there, they have drawn a cartoon showing the hon. Prime Minister with handcuffs on both his legs and wrists. Do you want to support it?

I would like to ask the hon. Member, Gogoi. *Do you support such a caricature?. Will you allow such cartoons? If you support this then why did you speak in the morning like this? You said that Hon Prime Minister should be respected and everybody should respect each other. Why did you say like this?*

Are you being hypocritical? You want to say it here. But when that cartoon is done about hon. Prime Minister, do you want all of us to sit and watch it? Certainly, action will be taken and I am happy that Ananda Vikatan's cartoon was pulled up. And for that, do you have sympathy? Hon. Member, Shri S. Venkatesan from Madurai should answer to this question. Whereas in Tamil Nadu, anyone uttering one word against the hon. Chief Minister of Tamil Nadu is arrested midnight, they want to talk about freedom of expression. I want to ask him about that.

Then he also said that Manipur is burning; nobody has gone there. I want to remind them that in 1993, when Shri Rajkumar Dorendra Singh of the Congress was the Chief Minister of Manipur, a major flare-up between Kukis and Nagas happened. That happened between April and December 1993, resulting in huge destruction. Do you know the numbers? I shake while I read this. About 750 deaths and destruction of around 350 villages happened in Manipur. At that time, Shri P. V. Narasimha Rao was the Prime Minister and Shri Shankarrao Chavan was the Home Minister. They did not even participate in the Parliamentary debates. So where was Gogoi that time? Where was the Congress Party that

time? Did they ask them to come and speak? Did they ask them to go to Manipur? No, they did not do so. Similarly, when a Motion for President?s Rule in Manipur was moved in Rajya Sabha in February 1994, it was the Minister of State for Home Affairs, Shri P. M. Sayeed, who responded, and not the Prime Minister, not the Home Minister. And even at the peak of the violence in August 1993, it was the Minister of State for Home Affairs, Shri Rajesh Pilot, who addressed the Parliament.

Written records of the Rajya Sabha show that while demanding President?s Rule in the violence-ridden State, the hon. Member, Smt. Sushma Swaraj of the BJP did not press for the Prime Minister's reply or presence. That was how we in the Opposition respected the Ruling Party in sensitive matters, and look at the way they go on repeating.

When the violence happened, when the people were in camps, the hon. Home Minister Amit Shah ji went there and spent three nights. After that, the hon. Minister of State for Home, Shri Nityanand Rai ji stayed there for three months. नित्यानंद जी, आप लगातार तीन महीने तक उधर ही थे न?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): मैडम, मैं 24 दिनों तक था ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : ये 24 दिन तक वहां थे ।

श्री नित्यानन्द राय : मैडम, माननीय गृह मंत्री जी भी वहां कई दिनों तक रहे । वे सारी हाट स्पॉट्स जैसी जगहों पर भी गए थे ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : माननीय गृह मंत्री जी खुद गए थे । वे हर कैंप में गए थे और लोगों से बात की थी । मगर, आपके समय में आपने डिस्कशन में भागादारी भी नहीं दिखाई और आपके मंत्रीगण भी नहीं गए । आपको जवाब देने में भी संकोच था ।

Did the then Prime Minister, who served as Prime Minister between 1991 and 1996, ever visit Manipur? In 1993, the violence happened, and about 750 people died. Did the Prime Minister, the Congress Prime Minister, visit then? Would they first apologize for that?

The fault lines of misgovernance of last 50-60 years should be kept in mind. There were further clashes in 1997-98, which claimed nearly 350 lives during the tenure of Prime Minister Shir I.K. Gujral. Did he visit Manipur to console the people or extend any apology? No. The then Chief Minister of Manipur, Congress leader, Shri Ibobi Singh admitted that Manipur witnessed 628 bandhs during his period. Blockades during the last 15 years, from 1995 till June 2010, under Congress in the Centre and Congress in the State, caused huge loss to the tune of Rs.2828 crore in the State.

The possible worst blockade in Manipur happened in 2011, lasting over 120 days, causing severe shortages of essential commodities. Petrol prices were beyond Rs.200 per litre. LPG costed Rs.2000 per cylinder. And, this happened during their time, when they were both in Manipur and in the Central Government. With this kind of a neglect, I hope the Congress Party does not speak about Manipur, as to who is witnessing, who is going, who is not.

With that, I would want to come to another point, which the hon. Member, Dr Rani Srikumar spoke about. She spoke about education; she spoke about Tamil. I am translating roughly what she said. She said, ?We have taught civilization for over 4000 years. We do not want you to teach us.? She also spoke about how Manipur is suffering. She also spoke about Tamil?s civilization. She also spoke about Nirbhaya funds. She also spoke about Dravidian model of governance, that has put women at the forefront by giving free bus passes.

I want to highlight one thing. *They say that they have a culture dating back to 4000 years ago. Please do not teach us anything about culture. They meant and spoke in that way. In the State Assembly of Tamil Nadu which has a civilization dating back to 4000 years old, in March 1989 in the Legislative Assembly of the State it is they who pulled the Saree of Madam Jayalalithaa. Those who talk about civilization, women?s rights and providing free bus pass to women were the ones who pulled the saree of Madam Jayalalitha.*

I wish they were here, they would have shouted at me, saying, how dare you talk about it. It is a truth. She spoke about 4000 years of civilization, about which I am proud of; all of us are proud about it. But the hon. Member says, ?You do not give me any lectures on that. We are the ones who taught the world what civilization values are.?

There was this event in March 1989, where the saree of a lady Member of the House was pulled by one of their Members. I am not naming anybody. Was that *nagarikam*? Was that *pannbadu*? Was that *kalacharam*? She does not want us to teach. The hon. Member does not want us to teach her *kalacharam*, but that is the *kalacharam* of the Dravidian model.

It is not enough that to give free bus pass to women. You should not disrespect women. You did not give respect. Similarly another girl in Anna University. A horrible rape happened on the campus in December 2023. What response has the State Government given till today? *She is also a woman. This is against your civilized portrayal. To whom you are saying not to preach. Third one was a 9 year old girl she was sexually harassed.* A sexual assault occurred on a nine-year-old school child in Trichy. What action has been taken? The hon. Member is telling us not to preach to her about *kalacharam* and *pannbadu*. Is that the Dravidian model? A fourth woman, a 22-year-old, was gang-raped near her home in Thanjavur last year. Under the Dravidian model of the DMK Government, these are the cases of women who are suffering. The saree of a woman was pulled in the Assembly, and there are rape cases. Besides this, the law and order in Tamil Nadu is in such a pathetic state that in Kallakurichi, 68 people died drinking spurious liquor. Not much action has been taken regarding that. There have been 28 cases of honour killing.

We hear the Dravidian model telling us about *samathuvam*. We are the ones who teach equality. If girls and boys of different castes are getting married, they are hacked in the middle of the road. Twenty-eight cases of honour killing have happened in Tamil Nadu. That is the Dravidian model, and they are telling us not to preach to them.

Another case, Sir, I would like to mention. An alarming amount of drug violence is happening. Women are crying that their children are taking drugs, nobody is doing anything, and they do not know what is happening. Sons are killing mothers because they are not given money to buy drugs. What action has been taken? On the contrary, I am not naming anybody, but one particular individual who has been arrested for deep drug smuggling has been associated with one of the prominent families. No answer comes from DMK on that. So, that is important for us to remember.

There is all this affection, love, and emotion for the Tamil language. The Education Minister spoke the truth about how they were ready to sign the MoU, and then they changed their mind under the pretext that the three-language formula is not suitable for them: ?We do not want it, but you are imposing Hindi.? I have lived in Tamil Nadu where if you learn Hindi and Sanskrit, you are targeted. They can say anything. I am sharing my lived experience. But more importantly, Sir, they wanted the hon. Minister, Dharmendra Pradhan, to apologize because he said it is ... **. He probably meant that the way in which you are protesting is ...**. But never mind. They said, ?He is not only telling us, but he is telling the entire Tamil public?, which he did not. However, they made him say, ?I will take back my word.? I want to ask, with all humility, about an eminent leader who spoke about Tamil. I do not want to name him, but the moment I read the passages, anyone with a small, faint familiarity with Tamil will know who I am speaking about. When this person speaks about Tamil, and much more horribly, there is no objection. On the contrary, they keep his photo and say he is our Dravidian icon. I want to read that here.

He says and I quote. This was published in a magazine called Viduthalai on 27 November, 1943. What does he say? I will give you a brief translation afterwards. He says: *?If you read Tamil, you won?t even get alms. Learning Tamil has only helped you to get alms and not even helped to get a livelihood. It would have been beneficial if the time spent in learning Tamil language would have been spent on any other field. This has been sung by an experienced Tamil poet 100 years ago.?*

That one line is enough, but I will read the passage. What does it mean? It means that if you learn Tamil, a beggar also cannot survive. You would not even get alms meaning that you would not even get anyone giving you ?daan?. He says that: ?If you had spent the time learning Tamil for learning something else, then you would have had some kind of meaningful thing in your hand to lead your life. Instead of that, why are you learning Tamil?? The person who said this quoting a poet who lived 100 years ago, you are keeping a picture

in your offices, on your desks and everywhere and you are worshiping him. But you wanted Shri Dharmendra Pradhan to apologise for what he had not said.

Even worse! He said that in an uncivil way these MPs are protesting. You wanted him to withdraw that statement. All right, Shri Dharmendra Pradhan withdrew, but here is that elderly man saying it and again I will read it. This was published in a magazine called *Thuglaq* during their Golden Jubilee Edition between 1970-2019. It was published in 2019. *This Tamil language is a barbaric language. Why I say so?*

I will translate that line and you will understand why I am reading it here. My mother-tongue is Tamil and I am reading this. It really makes me feel angry, but I will tell you. He asks a question right at the beginning. He says: ?Why am I saying that Tamil is a barbaric language?? He says this that ?Why am I saying that Tamil is a barbaric language??.

?Why I say so because the honest persons who get angry don?t think before speaking anything. They speak just like that as they have mouth to speak and try to feed their stomach. Other than this, they do not think at least a little about knowledge or dignity or discipline. But they continue speaking the way they want to. Even if we think in their way, they claim Tamil to be language spoken 3000 years to 4000 years ago. These honest men who get angry on why I say so?.Tamil is seen as an instrument of pride for Tamils. I also cite this as an important reason to mention it as a barbaric language in similar lines. Whether it is Shiva or Agasthiyar or Panini or anyone for that matter. If you do not have knowledge about them, do you qualify to speak about Tamil language? Do you have mouth to speak?

Sir, the brief summary translation of this is and he says: ?For the very reason that you are telling that Tamil is a 3,000-4,000-year-old language, I am using the same reasons to say that it is a barbaric language?. This elderly man who they worship every morning, afternoon and evening says this. I am not even taking his name, and he says that it is a ?barbaric language? for the very reason for which you say: ?3,000-year-old language?, ?we are ancient?, ?we are the oldest?. He says: ?For those very reasons, Tamil is a barbaric language?. He says this: ?Do you know how they lived at that time? Do you know what kind of life these people led? Without studying about these things, you want to say that Tamil is a great language, it is an old language, it is an ancient language, it is very traditional and all that?. He concludes: ?Tamil is a barbaric language?.

Sir, for just saying ?your protests are uncivil?, they made the Education Minister to withdraw his statement. When a man repeatedly says ?Tamil is a barbaric language?, look at the hypocrisy. They keep his photo in every room. I am sure even in the Parliament office of that Party his photo is there.

They garland him, worship him and they say that he is the icon of Dravidian Movement. But he said, ?Tamil is a *kattumirandi bhashaye*?. So, I am saying, it is unbelievable that this person is worshipped. Our poor Dharmendra Pradhan ji just asked not to do uncivil protest,

but he is being accused. And if their love for Tamil is so much, how can they worship somebody who said that Tamil is a *kattumirandi bhashaye*?

Lastly, this very person, who was elderly, also said in a magazine called *Viduthalai* on 16th March, 1967, that Tamil scholars and pundits deserved to be imprisoned for life. So, if you were a pundit of Tamil, you were learning Tamil, you were a scholar in Tamil, he said, ?Put them all in jail?. And even worse, he said, ?Hang them, as they do not create anything that lead to the society's progress?. By ?society's progress?, he meant that there is no contribution of those people who love Tamil, who write in Tamil, and who have scholarship in Tamil. They have not contributed anything to the society. So, ?hang them?, he said. But no, I worship them! That is their Dravidian model of politics. And worse is there. There was a World Tamil Conference, which was held. He says, ?You can take a census of everybody there and enumerate the number; all of them are fools?. That is how far he went to call about those people who were in the World Tamil Conference of 1967. These are the golden words of this elderly man. And he said, ?learning Tamil will not help you, not even in your begging will it help you?. They have a great love for Tamil, they do not want imposition of Hindi.

The New Education Policy actually says, ?Learn in your mother tongue till class 5 and if possible, till class 8; even better, till intermediate?. That is what the New Education Policy says. But no, they want to imagine that it is imposing Hindi and they do not want to therefore talk about it. But wrongly, they create a political mess in Tamil Nadu, denying children their right to learn. And they worship a person who called Tamil a *kattumirandi mozhi* ? ?barbaric language?. The person who said that is the person who they worship. And here, they say this even to an educated and honest Minister of Education. So, that is the hypocrisy and, I would like you to kindly allow me to say this final word, they are sure that I would come to say all this and they do not have the strength to face this and therefore, they have gone away.

* I will tell all these things to everyone. I will tell about the person who called Tamil language a barbaric one. Today the people who are worshipping him have made our Hon Minister of Education to seek apology. I will explain everything to them. They were afraid of the fact that I will reply to all their questions. Having that fear in their minds, they ran away from this august House and did not sit here to listen to my speech. But I know that they would be watching on TV. People of entire Tamil Nadu will be watching my speech on TV. I should explain their hypocrisy to the people of Tamil Nadu. The New Education Policy brought by our Hon Prime Minister Shri Modi will be helpful to all the poor and downtrodden people. I will say this to the people of Tamil Nadu. I humbly request that the people of Tamil Nadu y should question the DMK and their leaders who oppose this New Education Policy.*

Thank you.

माननीय अध्यक्षः अब मैं वर्ष 2024-25 से सम्बंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगें - द्वितीय बैच को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 6, 8, 10, 11 से 13, 15, 17 से 22, 25, 26, 29 से 32, 35, 41, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 58 से 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70 से 72, 74, 76, 78, 79, 85, 86, 89, 91 और 97 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित अनुपूरक राशियां, भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं वर्ष 2021-22 से सम्बंधित अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह हैः

"कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 6 और 39 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में हुए खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित अतिरिक्त राशियां, भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह हैः

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां, मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर राज्य से सम्बंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 3, 5 से 7, 14, 20, 23 से 25, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 46, 48 और 49 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई

राजस्व लेखा और पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित राशियां, मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)